अक्टूबर 2020

सिविल सर्विसेस मासिक

CHAHAL ACADEMY
LEARN TODAY! LEAD TOMORROW!

सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के सभी समाधान एक स्थान पर

शौर्य परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल
जगन्ना विद्या कनुका योजना
भारिबै मौद्रिक नीति 2020
गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020
अर्थ ऑब्ज़र्वेशन उपग्रह ईओएस – 01
कला संस्कृति विकास योजना
बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी)
टाईम युज़ सर्वेक्षण (टीयुएस)
नागोर्नो–काराबाख क्षेत्र
कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020
ट्रैक्टर के लिए उत्सर्जन मानदंड
स्वास्थ्य बीमा शिखर सम्मेलन
भारत का पहला क्लाउड इनोवेशन सेंटर
स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020
कुरुक्षेत्र का सारांश
योजना का सारांश

विषय–सूची

प्रारंभिक परीक्षा

जोंबी दावानल 1
लेसर गाईडेड एंटी–टेंक गाईडेड मिसाईल 2
बोंगोसागर 4
शौर्य परमाणु सक्षम हाईपरसोनिक मिसाईल 5
रवि चोपड़ा समिती 6
जगन्ना विद्या कनुका योजना 8
नोबेल शांति पुरस्कार, 2020 9
भारिबै मौद्रिक नीति 2020 10
विशेष किसान रेल 14
ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 14
गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 15
CuRED 17
अर्थ (पृथ्वी) ऑब्र्ज़वेशन उपग्रह ईओएस–01 18

मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन I

कामचटका आपदा 19
कला संस्कृति विकास योजना 21
जल संरक्षण के बुलढाणा पैटर्न 21
हींग खेती 22
बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) 23
बूंदी – एक भूली हुई राजपूत राजधानी की वास्तुकला विरासत 23
परम्परा श्रृंखला 2020–संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय उत्सव 25

सामान्य अध्ययन II

बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला 25
टाईम युज़ सर्वेक्षण (टीयुएस) 28
स्वामीनाथन आयोग 30
न्यायालय की अवमानना 31
नागोर्नो–करबख क्षेत्र 32
SVAMITVA योजना 34
संयुक्त राष्ट्र स्टिल बर्थ रिपोर्ट 34
बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग 35
गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020 36
संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी (युएनआरडब्ल्युए) 37
कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 38

सामान्य अध्ययन III

मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य (PMNCH) के लिए साझेदारी 39
केट क्यू वायरस 40
एरियल सीडिंग 40
ट्रैक्टर के लिए उत्सर्जन मानदंड 41
अनवरत जैविक प्रदूषक 43
प्रभाव आधारित चक्रवाती चेतावनी प्रणाली 45
राष्ट्र कामधेनु आयोग 47
विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट – आईएमएफ 48
स्वास्थ्य बीमा शिखर सम्मेलन 50
जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट – लैंसेट 52
भारत का पहली 'सेवियर सिबलिंग' 54
वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड प्रदूषण 56
भारत का पहला क्लाउड इनोवेशन सेंटर 57
स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट 2020 59

कुरूक्षेत्र एवं योजना पत्रिका का सारांश 61

ज़ॉम्बी दावानल (अग्नि)

समाचार –

- आर्कटिक क्षेत्र में ज़ॉम्बी दावानल आम होते जा रहे है। इसका अर्थ है कि आर्कटिक क्षेत्र जो कभी बर्फ में जमे हुए टुंड्रा प्रदेश हुआ करते थे में दावानल की घटनाएँ तेजी से हो रही है।

ज़ॉम्बी फायर –

- ज़ॉम्बी दावानल बढ़त के पिछले मौसम के कारण लगी आग होती है जो जमीन के नीचे कार्बन युक्त पीट में सुलग सकती है।
- अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार, जब मौसम गर्म मौसम के कारण आग लग सकती है।

मुद्दा –

- आर्कटिक में आग उन क्षेत्रों में फैल रही है जो पहले आग प्रतिरोधी थे।
- टुंड्रा – आर्कटिक सर्कल के उत्तर में – सूख रहा है और वहां पड़ी वनस्पति जैसे काई, घास, बौनी झाड़ियाँ आदि आग पकड़ने लगी हैं।
- आर्कटिक के दक्षिण में साइबेरिया में पर्माफ्रॉस्ट पर दावानल असामान्य नहीं हैं। लेकिन टीम ने पाया कि 2019 और 2020 में दावानल आर्कटिक सर्कल जहाँ आमतौर पर बड़े दावानल नही जन्मतें हैं, पर जन्मे है।
- इसके अलावा, इस साल साइबेरिया में तापमान बढ़ गया था। इस क्षेत्र में भीषण गर्मी दर्ज की गई। इनमें से आधे क्षेत्र प्राचीन कार्बन युक्त पीट मिट्टी पर जल गए।
- इन आग में कार्बन सिंक को कार्बन स्रोत में बदलने की क्षमता होती है जो बदले में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है।

पर्माफ्रॉस्ट –

- पर्माफ्रॉस्ट ऐसा कोई भी स्थान है जो कम से कम दो साल से पूरी तरह से जमा हुआ हो – 32° F (0° C) या ठंडा। ये स्थायी रूप से जमे हुए मैदान ऊंचे पहाड़ों और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्रों में – उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास सबसे आम हैं।
- पर्माफ्रॉस्ट पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों को ढँके हुए हैं।
- प्राचीन बायोमास से कार्बन की भारी मात्रा में पेमाफ्रॉस्ट में दबी होती है। इस प्रकार, इन पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से वातावरण में अधिक से अधिक कार्बन का उत्सर्जन होता है।

अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन मिशन

समाचार –

- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने अनुसूचित जाति (अजा) के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत "अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) का शुभारंभ किया, जो अजा छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में ASIIM –

- अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन पहल के तहत, अगले चार वर्षों में एक हजार अजा युवाओं की पहचान की जाएगी।

उच्च शिक्षण संस्थान –

- उन्हें अपने स्टार्ट–अप विचारों को वाणिज्यिक उद्यमों में बदलने के लिए इक्विटी फंडिंग के रूप में तीन साल में 30 लाख रुपये का वित्त पोषण किया जाएगा।
- सफल उद्यम आगे अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड से पांच करोड़ रुपये तक के उद्यम वित्त पोषण के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।

सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल – ब्रह्मोस

समाचार –

- भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कई अन्य 'मेड इन इंडिया' सबसिस्टम के साथ–साथ स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन की विशेषता वाली ब्रह्मोस सतह से सतह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सफल परीक्षण उड़ान भरी।

ब्रह्मोस –

- मिसाइल का उड़ान परीक्षण जिसमें 400 किमी से अधिक की स्ट्राइक रेंज है।
- ब्रह्मोस लैंड–अटैक क्रूज मिसाइल (LACM) मैक 2.8 की शीर्ष गति पर मंडरा रहा था।
- ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, समुद्री प्लेटफार्मों के साथ–साथ फाइटर जेट्स से भी लॉन्च किया जा सकता है।
- यह संयुक्त रूप से डीआरडीओ और एनपीओएम द्वारा विकसित किया गया है, जो रूस का एक प्रमुख एयरोस्पेस उद्यम है, ब्रह्मोस मिसाइल एक मध्यम दूरी की रैमजेट है।
- सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू जेट या जमीन से लॉन्च होने में सक्षम है।
- यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
- ब्रह्मोस नाम दो नदियों के नाम, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कवा के संयोग से बना है।
- मिसाइल का एक हाइपरसोनिक संस्करण, ब्रह्मोस–2 भी वर्तमान में एरियल फास्ट स्ट्राइक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 7–8 मैक की गति के साथ विकास के दौर में है।
- 2016 में, भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) का सदस्य बन गया, भारत और रूस अब संयुक्त रूप से 600 किलोमीटर की सीमा के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों की एक नई पीढ़ी को विकसित करने और पिनपॉइंट सटीकता के साथ संरक्षित लक्ष्यों को हिट करने की क्षमता विकसित करने की योजना बना रहे हैं।

भारतीय तटरक्षक पोत वेसल कनकलता बरुआ

समाचार –

- भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज कनकलता बरुआ, पांच फास्ट पैट्रोल वेसल्स (एफपीवी) की श्रृंखला में अंतिम, का कमीशन किया गया।
- इस जहाज का नाम एक स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ के सम्मान में रखा गया था, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए थे।

विवरण –

- इस जहाज को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड, कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, आत्मनिर्भर भारत का यह बेहतरीन उदाहरण अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है।
- 49 मीटर के जहाज में 310 टन के बराबर विस्थापन होता है, जिसे तीन MTU 4,000 श्रृंखला इंजनों से लेस किया गया है, जो 35 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किये गए है।
- जहाज को एक कठोर इनफ्लिशेबल बोट (RIB) हाई–स्पीड बोट और एक मिथुन बोट को स्विफ्ट बोर्डिंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ले जाने के लिए बनाया गया है।
- ICGS कनकलता बरुआ इसी तरह के नाम वाले जहाज का प्रतिस्थापन है जो 1997 से 2018 तक कमीशन में था।
- भारतीय तटरक्षक बल दक्षिण–एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ा है और गतिशील है और राष्ट्र के व्यापक हित को बचाने में महत्वपूर्ण है।
- इस जहाज को ईईजेड निगरानी, तटीय सुरक्षा और अन्य कर्तव्यों जो कि राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए कर्तव्यों के तट रक्षक चार्टर में निहित है, के लिए बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा।

गांधी जयंती

समाचार –

- महात्मा गांधी की जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित करर घोषणा की कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- इस वर्ष, महात्मा गांधी की 151 वीं जयंती पर कोरोनोवायरस महामारी के बीच मनाई गई।

महात्मा गांधी / मोहनदास करमचंद गांधी

- महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्हें 'राष्ट्रपिता' के रूप में भी जाना जाता है।
- उन्हें स्वतंत्रता के संघर्ष में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए याद किया जाता है।
- उनका उद्देश्य एक नए समाज का निर्माण करना था जो अहिंसक और ईमानदार व्यवहार करता हो।
- मोहनदास करमचंद गांधी एक भारतीय वकील, उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी और राजनीतिक नैतिकतावादी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध को नियोजित किया था, और बदले में दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित आंदोलनों का नेतृत्व किया।

लाल बहादुर शास्त्री

समाचार –

- राष्ट्र अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी 116 वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है।
- 1904 में उत्तर प्रदेश में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री ने महात्मा गांधी के साथ अपना जन्मदिन साझा किया।
- वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और 1964 से 1966 तक इस पद पर सेवा दी।
- लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी, 1966 को 61 साल की उम्र में ताशकंद में पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद निधन हो गया।

लाल बहादुर शास्त्री (2 अक्टूबर 1904 – 11 जनवरी 1966) –

- शास्त्री का जन्म शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और रामदुलारी देवी से मुगलसराय में 2 जून 1904 को हुआ था।
- उन्होंने पूर्व मध्य रेलवे इंटर कॉलेज और हरीश चंद्र हाई स्कूल में अध्ययन किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए छोड़ दिया।
- स्वामी विवेकानंद, गांधी और एनी बेसेंट के बारे में पढ़कर शास्त्री के विचार प्रभावित हुए।
- उन्होंने 1965 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया। उनका नारा 'जय जवान, जय किसान' युद्ध के दौरान बहुत लोकप्रिय हुआ।
- उन्होंने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया – दूग्ध उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान छेड़ा – आणंद, गुजरात के अमूल दूध सहकारी संस्थान का समर्थन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का निर्माण किया।
- शास्त्री ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। इससे विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई।

लेजर गाइडड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल

समाचार –

- डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
- हथियार का परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर में बख्तरबंद कोर सेंटर और स्कूल (एसीसी एंड एस) के केके रेंज में एक एमबीटी अर्जुन टैंक से किया गया था।
- अर्जुन डीआरडीओ द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है।

विवरण –

- ATGM में 1.5 से 5 किमी तक की दूरी पर विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच (ERA) संरक्षित बख्तरबंद वाहनों को भेदने के लिए एक खतरनाक HEAT वारहेड होता है।
- ATGM को कई प्लेटफार्मों से लॉन्च करने की क्षमता के साथ विकसित किया गया है।
- वर्तमान में यह एमबीटी अर्जुन की 120 मिमी राइफल वाली बंदूक से तकनीकी मूल्यांकन परीक्षण से गुजर रहा है।
- यह लेजर गाइडेड मिसाइल आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, पुणे द्वारा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, पुणे और इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, देहरादून के सहयोग से विकसित किया गया है।

क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर (CCHF)

समाचार –

- पालघर प्रशासन ने अधिकारियों को महाराष्ट्र जिले में कांगो बुखार के संभावित प्रसार के खिलाफ सतर्क रहने के लिए कहा।
- क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर (CCHF), जिसे आमतौर पर कांगो बुखार के रूप में जाना जाता है, मनुष्यों में टिक के माध्यम से फैलता है।

विवरण –

- यह वायरल बीमारी एक विशेष प्रकार की टिक द्वारा एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है।
- यह बीमारी संक्रमित जानवरों के खून के संपर्क में आने और संक्रमित जानवरों के मांस खाने से होती है।
- यदि समय पर इस बीमारी का निदान और उपचार नहीं किया जाता है, तो 30 प्रतिशत रोगियों की मृत्यु हो जाती है।
- CCHF एक व्यापक बीमारी है, जो बनिएवेरिडा परिवार के टिक–जनित वायरस (नैरोवायरस) से होती है। वायरस गंभीर वायरल का कारण बनता है।
- रक्तस्रावी बुखार का प्रकोप, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार 10 से 40 प्रतिशत की घातक स्थिति दर के साथ होता है।
- बीमारी के खिलाफ लोगों या जानवरों के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

क्रोमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर (CCHF) –

- CCHF परिवार बुन्यवीरिडे में टिक–जनित वायरस (नैरोवायरस) के संक्रमण के कारण होता है।
- इस बीमारी को पहली बार क्रीमिया में 1944 में प्रदर्शित किया गया था और इसे क्रीमियन हेमरेजिक बुखार का नाम दिया गया था।
- इसे बाद में 1969 में कांगो में बीमारी के कारण के रूप में मान्यता दी गई, इस प्रकार रोग का वर्तमान नाम पड़ गया।
- क्रीमियन–कांगो रक्तस्रावी बुखार पूर्वी यूरोप में, विशेष रूप से पूर्व सोवियत संघ में, पूरे भूमध्यसागरीय, उत्तर–पश्चिमी चीन, मध्य एशिया, दक्षिणी यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है।

मिशन लैंटाना

समाचार –

- राजस्थान के उदयपुर जिले के प्रसिद्ध सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में आक्रामक लैंटाना झाड़ियों को उखाड़ने के लिए एक विशेष अभियान ने घास के मैदानों की पारिस्थितिक बहाली और जैव विविधता को बचाने में मदद की है।
- अभियान की शुरूआत भूमि के साफ पैच पर देशी प्रजातियों के रोपण के साथ की गई।

मिशन लैंटाना

- दक्षिणी अरावली पहाड़ियों में छोटा अभयारण्य, बड़ी संख्या में शाकाहारी पशुओं का निवास है।
- लैंटाना कैमारा, एक गाढ़ा रूप झाड़ी है, इसने अभयारण्य में भूमि के विशाल हिस्से को कवर किया है, जिससे वनस्पतियों और जीवों तक प्राकृतिक प्रकाश और पोषण रूकता है।
- इसके पत्ते और पके जामुन में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ जानवरों को प्रभावित करता है, जबकि इसके विस्तार ने घास और अन्य झाड़ियों की प्राकृतिक वृद्धि को रोक दिया है।
- शाकाहारी लोगों को पर्याप्त चारा नहीं मिल रहा था, मांसाहारी जानवरों के शिकार का आधार कम हो रहा था, जिससे खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिक गड़बड़ी हो रही थी।
- 1807 में पहली बार शुरू की गई लैंटाना वन्यजीवों के भंडार, नदी के किनारे और प्रोजेक्ट टाइगर के इलाकों में फैल गई थी, जहां इसने देशी घास को नष्ट कर दिया था और जैव विविधता को कम कर दिया था।

दुनिया का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट

समाचार –

- चीन संसाधनों की पहचान करने और निकालने के लिए दुनिया का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने वाला है।
- मूल रूप से बीजिंग स्थित कंपनी, ओरिजिन स्पेस, नवंबर 2020 तक दुनिया का पहला खनन रोबोट का नाम 'एस्टेरॉयड माईनिंग रोबोट' है।
- क्षुद्रग्रह खनन रोबोट को एक चीनी लॉन्ग मार्च सीरिज़ रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा।
- हालांकि, रोबोट कोई वास्तविक खनन नहीं करेगा।

एकीकृत रक्षा स्टाफ

समाचार –

- एकीकृत रक्षा कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर 2020 को अपना 20 वां स्थापना दिवस मनाया।
- मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, जिसे मुख्यालय आईडीएस के रूप में जाना जाता है, 1 अक्टूबर 2001 को बनाया गया था।

एकीकृत रक्षा स्टाफ –

- आईडीएस एक संगठन है जो समन्वय को बढ़ावा देने और भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न शाखाओं में प्राथमिकता को सक्षम करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, विदेश मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय और मंत्रालय के प्रतिनिधियों से बना है।
- आईडीएस का नेतृत्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के साथ होता है और साथ ही इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के डिप्युटी चीफ होते हैं।
- यह निकाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सलाह देता है और उनकी सहायता करता है।
- सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक चार सितारा जनरल, एक त्रिकोणीय सेवा प्रमुख की स्थापना की, जो रक्षा बलों का नेतृत्व करेगा और साथ ही सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख की भूमिका निभाएगा।
- आईडीएस के रोल्स में बहु–सेवा निकायों के कुशल कामकाज की सुविधा शामिल है, जैसे कि
  – रक्षा उपग्रह नियंत्रण केंद्र (एकीकृत अंतरिक्ष सेल)
  – पूंजी रक्षा खरीद के सभी प्रस्तावों में रक्षा मंत्री को सचिवीय और डोमेन विशेषज्ञता प्रदान करना।
  – खरीद, संयुक्त सिद्धांत, संयुक्त प्रशिक्षण और सामान्य प्रक्रियाओं के लिए इंट्रा–सर्विस विचार–विमर्श के माध्यम से सहयोग के भवन प्रदान करना।

कल्पना चावला कार्गो अंतरिक्ष यान

समाचार –

- भारतीय मूल के मृतक नासा अंतरिक्ष यात्री 'कल्पना चावला' के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) के लिए बाध्य एक वाणिज्यिक कार्गो अंतरिक्ष यान नासा ने लॉन्च किया है।
- एस. एस. कल्पना चावला ने वर्जीनिया में नासा के वॉलॉप्स फ्लाइट फैसिलिटी में मिड–अटलांटिक रीजनल स्पेसपोर्ट (MARS) से लॉन्च किया।

विवरण –

- एस. एस. कल्पना चावला स्टेशन पर लगभग 3,630 किलोग्राम माल पहुंचाएंगी।

उसमे समाविष्ट हैं –

- एक जैविक दवा का परीक्षण जो ल्यूकेमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- एक पौधे की वृद्धि का अध्ययन, जो अंतरिक्ष में भविष्य की फसलों के लिए एक मॉडल के रूप में मूली की खेती करेगा।
- अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों पर उपयोग करने के लिए एक कॉम्पैक्ट शौचालय।
- एक 360–डिग्री वर्चुअल रियलिटी कैमरा, जिसका उपयोग स्पेसवॉक के दौरान एक विशाल सिनेमाई उत्पादन के लिए फिल्माने के लिए किया जाएगा।
- कार्गो विमान में नए स्पेससूट का एक घटक भी होता है जिसे हम अंतरिक्ष स्टेशन पर माइक्रोग्रैविटी में परीक्षण करेंगे।
- एक उन्नत कण मॉनिटर हवा के कण और कई चीजों को मापने के लिए।

बोंगोसागर

समाचार –

- भारत और बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में वार्षिक 'बोंगोसागर' अभ्यास के भाग के रूप में एक मेगा सैन्य अभ्यास किया, जिसका पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में आयोजित किया गया था।

विवरण –

- इसका उद्देश्य अंतर–संचालन और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है।
- दोनों नौसेनाओं के जहाज सतह युद्ध अभ्यास अभ्यास, सीमेन्सशिप के विकास और हेलीकाप्टर संचालन में भाग लेंगे।
- 4 और 5 अक्टूबर को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में कोऑर्डिनेट पैट्रोल (कॉर्पेट) के तीसरे संस्करण के बाद अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। कॉर्पेट के आचरण ने दोनों नौसेनाओं और गैरकानूनी गतिविधियों के संचालन को रोकने के उपायों को स्थापित करने के बीच समझ को मजबूत किया है।
- भारतीय नौसेना 'बोंगोसागर' अभ्यास में पनडुब्बी रोधी युद्धक दल कार्वेल्ट और गाइडेड–मिसाइल कोरवेट खुखरी को तैनात करेगी।
- बांग्लादेशी नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड–मिसाइल फ्रिगेट अबू बक्र और गाइडेड–मिसाइल कोरवेट प्रेटॉय द्वारा किया जाएगा।
- समुद्री नौसैनिक विमान के साथ–साथ दोनों नौसेनाओं के कई हेलीकॉप्टर भी अभ्यास में भाग लेंगे।

अटल सुरंग – दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग

समाचार –

- प्रधान मंत्री ने मनाली में 'दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग' सुरंग का उद्घाटन किया है।
- 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली को पूरे साल लाहौल–स्पीति से जोड़ती है।
- वर्तमान में, भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण यह क्षेत्र हर साल लगभग 6 महीने तक कट जाता है।
- अटल सुरंग का बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व है क्योंकि यह सशस्त्र बलों की आवाजाही में बहुत मदद करेगा।

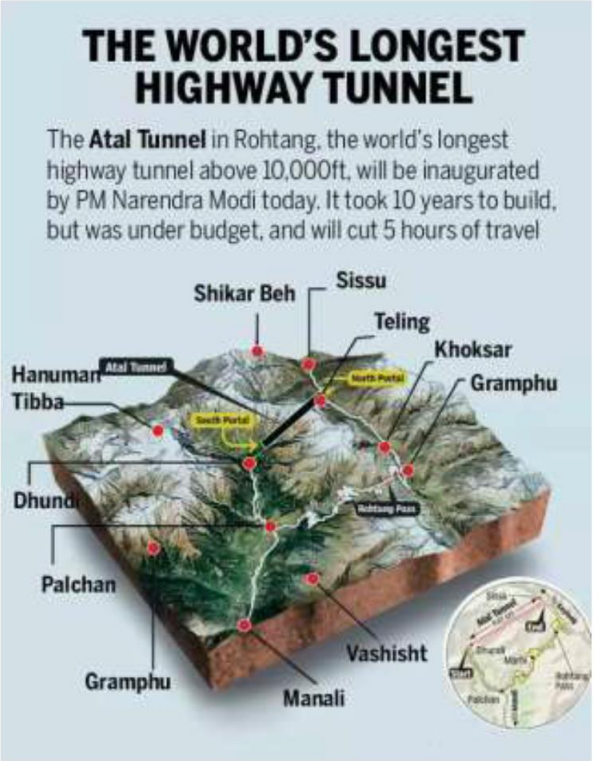

अटल सुरंग –

- अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में बनाई गई है।
- सुरंग मीन सी लेवल (MSL) से 10,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।
- सुरंग को लेह और मनाली के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करने के लिए निर्धारित किया गया है।
- अटल सुरंग से यात्रा का समय भी लगभग 4 से 5 घंटे कम हो जाता है।
- रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक सुरंग बनाने का निर्णय 03 जून, 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान लिया गया था।

मल्टी–मोड हैंड ग्रेनेड

समाचार –

- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए मल्टी–मोड हैंड ग्रेनेड (MMHG) की स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई आपूर्ति के लिए एक नागपुर स्थित निजी संस्था के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
- ये ग्रेनेड अब सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने 'मिल्स बम' प्रकार के 36M हैंड ग्रेनेड की जगह लेंगे।

मल्टी–मोड हैंड ग्रेनेड –

- इनमें समान वितरण को प्राप्त करने के लिए पहले से तैयार बेलनाकार हल्के स्टील के प्रीफ्रैगमेंट का उपयोग किया जाता है।
- इसे DRDO के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) ने विकसित किया है।
- एमएमएचजी को दो अलग–अलग संरचनाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दो अलग–अलग मोड हैं – रक्षात्मक और आक्रामक।
- भारत में अब तक सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथगोले मुख्य रूप से रक्षात्मक मोड हथगोले हैं, जिसका अर्थ है कि यदि फेंकने वाला शरण में या कवर में है तो खुले में खड़े व्यक्ति को विखंडन द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
- दूसरी ओर, आक्रामक हथगोले का विखंडन नहीं होता हैं, और विरोधी को विस्फोट से नुकसान होता है एवं फेंकने वाला सुरक्षित रहता है।
- यदि उत्पाद को सामान्य परिस्थितियों में संग्रहीत किया जाता है, तो इनका शेल्फ जीवन, निर्माण की तारीख से 15 वर्ष तक होता है।

पशु पुल (एनीमल ब्रिज)

समाचार –

- भारत निर्माणाधीन दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहले पांच पशु ओवरपास बनाए जाएंगे।

विवरण –

- ये ओवरपास वन्यजीवों के सुरक्षित मार्ग के लिए नीदरलैंड में 'पशु पुलों' की तर्ज पर होंगे।
- राजस्थान के रणथंभौर और मुकुंदरा (दर्रा) वन्यजीव अभयारण्यों को जोड़ने के रास्ते पर आने वाले गलियारे में रणथंभौर वन्यजीवों के एक वर्ग पर वन्यजीवों के आवाजाही को परेशान नहीं करने की चिंताओं के कारण इन पुलों की योजना बनाई गई है।
- पशु पुल मानव–पशु संघर्ष को रोकने में मदद करेंगे और जानवरों और वाहनों के बीच टकराव से भी बचेंगे।

शौर्य – परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल

समाचार –

- भारत ने अपने स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम, सतह से सतह पर सामरिक हाइपरसोनिक मिसाइल 'शौर्य' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

'शौर्य' के बारे में –

- शौर्य भारत की K–15 मिसाइल का भूमि संस्करण है, जिसकी स्ट्राइक रेंज 700 किमी से 1000 किमी है।
- यह 200 किलोग्राम टी 1000 किलोग्राम के पेलोड ले जाने में सक्षम है।
- यह 10 मीटर लंबा, 74 सेमी व्यास और 6.2 टन वजन का है। इसके दो चरण ठोस प्रणोदक का उपयोग करते हैं।
- शौर्य अपनी कक्षा में दुनिया की शीर्ष 10 मिसाइलों में से एक है।

- यह अपने उच्च प्रदर्शन नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली, कुशल प्रणोदन प्रणाली, परिष्कृत नियंत्रण प्रौद्योगिकियों और कनस्तर लॉन्च के लिए जाना जाता है।
- मिसाइल को साइलो और कनस्तरों से एक ट्रक पर चढ़ाकर जमीन के रास्ते ले जाया जा सकता है। एक ट्रक ही एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है।
- शौर्य मिसाइलें उन स्थानों पर रखी जा सकती हैं, जहां दुश्मन उनका पता नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा, यह उपग्रह इमेजिंग द्वारा पता नहीं लगाई जा सकती है।

विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, 2020

समाचार –

- विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 अक्टूबर, 2020 और 10 अक्टूबर, 2020 के बीच मनाया गया। ये तिथियां दो घटनाओं को याद दिलाती हैं –
- 4 अक्टूबर, 1957 – पहले मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण, इस प्रकार अंतरिक्ष की खोज का रास्ता खुला।
- 10 अक्टूबर, 1967 – चंद्रमा और अन्य आकाशीय निकायों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और शांतिपूर्ण उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि पर हस्ताक्षर।

विवरण –

- सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत मनाया जा रहा है जिसे 1999 में पारित किया गया था।
- विश्व अंतरिक्ष सप्ताह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव है, और मानव स्थिति की बेहतरी में उनका योगदान है।
- इस वर्ष सप्ताह की थीम 'उपग्रहों जीवन में सुधार लाते हैं' है।
- 2021 में, सप्ताह 'अंतरिक्ष में महिला' विषय के तहत मनाया जाना है।

विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के लक्ष्य –

- अंतरिक्ष आउटरीच और शिक्षा में अद्वितीय उत्तोलन प्रदान करना।
- दुनिया भर के लोगों को अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभों के बारे में शिक्षित करना।
- स्थायी आर्थिक विकास के लिए अंतरिक्ष के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए जनता का समर्थन प्रदर्शित करना।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में युवा लोगों को उत्तेजित करना।
- अंतरिक्ष आउटरीच और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

विश्व शिक्षक दिवस

समाचार –

- 1994 से हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
- विश्व शिक्षक दिवस 2020 का विषय 'टीचरः लिडिंग इन क्राईसिस, रिईमेजिनिंग द फ्युचर है।

विवरण –

- विश्व शिक्षक दिवस यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाता है।
- यह दिन शिक्षकों की स्थिति के संबंध में 1966 ILO/UNESCO की सिफारिश को अपनाने की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है।
- यह सिफारिश शिक्षकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों और उनकी प्रारंभिक तैयारी और आगे की शिक्षा, भर्ती, रोजगार और शिक्षण और सीखने की स्थिति के बारे में मानदंड निर्धारित करती है।
- उच्च–शिक्षा शिक्षण की स्थिति के विषय में सिफारिश को 1997 में उच्च शिक्षा में शिक्षण और अनुसंधान कर्मियों को शामिल करके 1966 की सिफारिश को पूरा करने के लिए अपनाया गया था।
- शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्य 4 को अपनाने के साथ, और समर्पित लक्ष्य (SDG 4-c) शिक्षा 2030 एजेंडा की उपलब्धि के लिए शिक्षकों को महत्वपूर्ण मानता है।

रवि चोपड़ा समिति

समाचार –

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रवि चोपड़ा समिति ने आरोप लगाया है कि चारधाम सड़क परियोजना (उत्तराखंड में तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए) ने अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है।

विवरण –

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि चारधाम परियोजना के तहत निर्मित सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। पहाड़ की सड़कों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की सिफारिश के आधार पर यह फैसला सुनाया गया था।
- इसके विपरीत, भारत सरकार ने सड़क की चौड़ाई 10–12 मीटर स्वीकृत की थी।
- MoRTH ने 700 किमी की सड़क परियोजना को 10–मीटर चौड़ाई के साथ जारी रखने की अनुमति दी है। यह समिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है।

चारधाम परियोजना –

- चार धाम परियोजना में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के श्रद्धालुओं के लिए 900 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और मरम्मत शामिल है।
- यह एक प्रस्तावित दो–लेन राष्ट्रीय राजमार्ग है।

पिपवर्ट्स की नई प्रजातियां

समाचार –

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों से पिपवर्ट्स की दो नई प्रजातियों की खोज की।

विवरण –

- महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में पाई गई इन प्रजातियों का नाम एरिओक्यूलोन परविसेफालम (इसके छोटे पुष्पक्रम आकार के कारण) रखा गया है।
- कुमटा, कर्नाटक से प्राप्त अन्य रिपोर्ट को एरिकोकुलोन करावलेंस (करावली, तटीय कर्नाटक क्षेत्र के नाम पर) कहा जाता है।

पिपवर्ट्स –

- पिपवर्ट्स एक पौधा समूह है जो मानसून के दौरान एक छोटी अवधि में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। यह पश्चिमी घाट की महान विविधता को प्रदर्शित करता है।
- भारत में पिपवर्ट्स की लगभग 111 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- इनमें से अधिकांश पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय से बताई जाती हैं, और उनमें से लगभग 70% देश की स्थानिक (एंडेमिक) हैं।

तथ्य –

- एक प्रजाति, एरिकोकोलोन सिनेरियम, अपने कैंसर विरोधी, एनाल्जेसिक, विरोधी भड़काऊ और कसैले गुणों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है।
- ई क्विनक्वंगुलारे का उपयोग यकृत रोगों के खिलाफ किया जाता है।
- ई मादयीपारेंसे केरल का एक एंटी–बैक्टीरियल है।

2020 नोबेल पुरस्कार

समाचार –

- भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, 2020 प्रदान किया गया है।

झलकियाँ –

- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रोजर पेनरोज को भौतिकी के 2020 नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा दिया और अन्य आधा रेनहार्ड जेनजेल और एंड्रिया घेज को संयुक्त रूप से ब्रम्हांड की सबसे 'गूढ़' वस्तु ब्लैक होल की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया है।
- एंड्रिया भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली चौथी महिला बनीं।
- तीन वैज्ञानिकों के बीच 10 मिलियन अमरीकी डालर की पुरस्कार राशि साझा की जानी है।
- हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज और पहचान के लिए तीन वैज्ञानिकों ने मेडिसिन नोबेल साझा किया।

> - एकमात्र भारतीय जिसने भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वह 1930 में सर सी वी रमन थे। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की।

भौतिकी के लिए –

- तारों के ढहने पर एक ब्लैक होल का निर्माण होता है और इसे ब्रह्मांड में एक स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका पलायन वेग इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है।
- पलायन वेग वह गति है जिस पर किसी वस्तु को किसी ग्रह या किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए यात्रा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह को छोड़ने के लिए, इसे लगभग 40,000 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा करने की आवश्यकता होती है।
- चूंकि प्रकाश इन स्थानों से बाहर नहीं निकल सकता है, ब्लैक होल अदृश्य होते हैं और केवल एक अंतरिक्षीय दूरबीन या अन्य विशेष उपकरणों की मदद से इन्हें ट्रैक किया जा सकता है।
- मुख्य रूप से बात यह है कि ब्लैक होल के अंदर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारे पदार्थ एक छोटी सी जगह में सिकुड़ जाते है।

चिकित्सा के लिए –

- इस वर्ष का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार एक ऐसे प्रयास के लिए दिया गया है जो अंततः सभी के लिए रक्त आधान को सुरक्षित बनाता है।
- अमेरिकी वैज्ञानिकों हार्वे ऑल्टर और चार्ल्स राइस और यूके के माइकल ह्यूटन को एक नए वायरस की खोज के लिए पहचाना गया है, जो कि पुराने हेपेटाइटिस के अधिकांश मामलों का कारण था, या गंभीर जिगर की सूजन के मामलों में, जिन रोगियों में रक्ताधान की आवश्यकता होती थी। इस वायरस को अंततः हेपेटाइटिस सी वायरस कहा गया।
- वायरस की पहचान 1970 और 1980 के दशक में की गई थी, अब इसका इलाज प्रभावी एंटी–वायरल दवाओं के रूप में उपलब्ध हैं।
- टेस्ट को इस वायरस से ग्रसित रक्त की पहचान करने के लिए विकसित किया गया है, जिससे संक्रमित रक्त किसी भी रोगी को नहीं दिया जा सके।

विश्व डाक दिवस

समाचार –

- विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को स्विस कैपिटल, बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है।

विवरण

- 1969 में टोक्यो, जापान में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था।
- प्रस्ताव भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य श्री आनंद मोहन नरूला द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तब से, डाक सेवाओं के महत्व को उजागर करने के लिए पूरे विश्व में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है।

- यूपीयू वैश्विक संचार क्रांति की शुरुआत थी, जिसने पूरी दुनिया में दूसरों को पत्र लिखने की क्षमता का परिचय दिया।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन –

- यूपीयू, 1874 की बर्न की संधि द्वारा स्थापित, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में डाक प्रणाली के अलावा सदस्य राष्ट्रों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है।
- UPU में कांग्रेस, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (CA), पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल (POC) और इंटरनेशनल ब्यूरो (IB) से युक्त चार निकाय शामिल हैं।
- यह टेलीमैटिक्स और एक्सप्रेस मेल सर्विस (ईएमएस) सहकारी समितियों की भी देखरेख करता है।
- यूपीयू का मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

साहित्य 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार

समाचार –

- साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुईस ग्लूक को दिया गया है।

विवरण –

- 77 वर्षीया ग्लूक को 'उनकी अचूक काव्यात्मक आवाज के लिए सम्मानित किया गया था, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है,' अकादमी ने कहा।
- येल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, ग्लुक ने 1968 में 'फर्स्टबोर्न' शीर्षक से अपने संग्रह की शुरुआत की। उन्हें अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवि और निबंधकार के रूप में देखा जाता है।
- उन्होंने अपने नवीनतम संग्रह, फेथफुल और सदाचारी रात, 2014 में अपने संग्रह द वाइल्ड आइरिस और नेशनल बुक अवार्ड के लिए 1993 में पुलित्जर पुरस्कार जीता।
- वे पिछले दशक में ओल्गा टोकरसीक, स्वेतलाना अलेक्सीविच और एलिस मुनरो के बाद नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली चौथी तथा 1901 में पहली बार इन पुरस्कारों को दिए जाने के बाद सोलहवीं महिला हैं।

जगन्ना विद्या कनुका योजना

समाचार –

- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने जगन अन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है।

जगन्ना विद्या कनुका –

- जगन्ना विद्या कनुका योजना में तीन जोड़ी वर्दी, एक स्कूल बैग, एक जोड़ी जूते और दो जोड़ी मोजे, स्कूल बेल्ट और किताबें होती हैं।
- सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को किट मिलेगी।
- वर्दी के सिलाई शुल्क को माता के खातों में जमा किया जाता है।
- योजना में जिले के 43 मंडलों के 3.17 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।

उद्देश्य –

- राज्य सरकार इन गतिविधियों के माध्यम से स्कूलों में प्रवीणता दर और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बनाने का इरादा रखती है।

सागर कवच अभ्यास

समाचार –

- केरल और कर्नाटक तटों के साथ दो दिवसीय अर्ध–वार्षिक तटीय सुरक्षा अभ्यास, सागर कवच का समापन हुआ।
- यह नौसेना, तटरक्षक बल के साथ तटीय पुलिस, पुलिस विशेष शाखा, खुफिया ब्यूरो, सीमा शुल्क, आव्रजन, पोर्ट विभाग, मत्स्य विभाग, लाइटहाउस के महानिदेशक, और मछली पकड़ने के समुदाय जैसे अन्य हितधारकों के साथ आयोजित किया गया था।
- अभ्यास के दौरान, संबंधित सरकारी तंत्र और एजेंसियों को निजी स्थानों पर हमलों को संबंधित सुरक्षा तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया था।
- इस अभ्यास का उद्देश्य तटीय सुरक्षा और मछली पकड़ने वाले समुदायों को तटीय सुरक्षा के साथ एकीकृत करना तथा सुरक्षा बलों की 'आंख और कान' के रूप में काम करना है।
- इस अभ्यास में, विभिन्न एजेंसियों के बीच संचार, सूचना का समय पर प्रवाह, संग्रह और खुफिया प्रसार का मूल्यांकन किया गया।

मतला अभियान व्यायाम –

- मतला अभियान का संचालन किया गया।
- मतला अभियान एक पाँच दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास है जो कि भारतीय नौसेना द्वारा मतला नदी में किया गया था।
- दो भारतीय नौकाओं ने अभ्यास के दौरान सुंदरबन डेल्टा में गश्त की।
- नाविकों ने स्थानीय मछुआरों के साथ बातचीत की जिससे तटीय सुरक्षा, समुद्री पुलिस स्टेशनों के बारे में जागरूकता फैली।
- नदी सुंदरबन में और उसके आसपास एक विस्तृत मुहाना बनाती है।

मुख्मंत्री सौर स्वरोजगार योजना –

समाचार –

- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया।

लक्ष्य –

- सौर स्वरोजगार योजना का उद्देश्य कोविड–19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खो चुके राज्य के लगभग 10,000 युवाओं, प्रवासियों के लिए स्व–रोजगार पैदा करना है।
- प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के तहत 10,000 लोगों को स्वरोजगार मिलेगा।

लक्षित व्यक्ति –

- कोविड–19 महामारी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में नौकरी छोड़कर घर लौट चुके युवा और प्रवासी।

महत्व –

- यह रोजगार प्रदान करेगा और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देगा।

- स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र एक ही भूमि पर फल सब्जियों और जड़ी बूटियों की एकीकृत खेती में मदद करेंगे।
- राज्य सरकार ने एक ही भूमि में जलवायु आधारित स्पंजी और औषधीय पौधों के खेती के बीज को बढ़ावा देने की भी योजना बनाई है।

विवरण –

- इन पौधों में से प्रत्येक को स्थापित करने के लिए भूमि की कुल 1.5–2 नालिस (भूमि माप इकाई) और 40,000 रुपये प्रति यूनिट की दर से 10 लाख रुपये की आवश्यकता होती है, जिससे प्रतिवर्ष 38,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इसे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 25 साल के लिए खरीदा जाएगा।
- सहकारी बैंक निजी भूमि पर या पट्टे पर ली गई भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए 15 वर्षों के लिए प्रति वर्ष आठ प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेंगे।
- तकनीकी समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए आवेदकों को जिला स्तर पर परियोजनाओं को आवंटित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

नोबेल शांति पुरस्कार, 2020

समाचार –

- विश्व खाद्य कार्यक्रम को शांति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार, 2020 प्रदान किया गया है।

विवरण –

- डब्ल्यूएफपी को संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए बेहतर परिस्थितियों में योगदान देने की दिशा में अपनी भूमिका के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युद्ध क्षेत्रों में भूख को रोकने के लिए यह एक प्रेरणा शक्ति है।

नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में त्वरित तथ्य –

- 1901 से 2019, 100 नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
- कुल 24 संगठनों को सम्मानित किया गया है।
- दो शांति पुरस्कारों को तीन व्यक्तियों के बीच विभाजित किया गया है।
- अब तक सत्रह महिलाओं को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
- एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता व्यक्ति ले डुक थो, ने नोबेल शांति पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया था।

नोबेल पुरस्कार –

- नोबेल पुरस्कार, जिसमें एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर ($ 1.1 मिलियन, 950,000 यूरो) का चेक होता है, विजेता को 10 दिसंबर को स्वीडिश उद्योगपति और लोकोपकारक अल्फ्रेड नोबेल (जिन्होंने अपनी इच्छा से पुरस्कार बनाए) की 1896 में मृत्यु की वर्षगांठ पर भेंट किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस –

समाचार –

- हर साल 11 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में यूनिसेफ ने लड़कियों के साथ एक वार्षिक अभियान शुरू किया है ताकि वे अपनी आवाज बुलंद करे और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकें।

2020 की थीम –

- 'माय वॉईस, अवर ईक्वल फ्युचर', लेट्स सीज़ द ऑर्पच्युनिटी टु रिईमेजिन ए बेटर वर्ल्ड इन्सपायरड बाय एडोलसेंट गर्ल्स – एर्नजाईज्ड एंड रिकॉग्नाईज्ड, काऊँटेड एंड इन्वेस्टेड इन।

विवरण –

- 2020 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उनकी मांगों पर केंद्रित होगा –
  – लिंग–आधारित हिंसा, हानिकारक प्रथाओं और एचआईवी और एड्स से मुक्त रहें।
  – उनके द्वारा चुने गए वायदा के प्रति नए कौशल सीखें।
  – सामाजिक परिवर्तन को गति देने वाले कार्यकर्ताओं की एक पीढ़ी के रूप में नेतृत्व करें।

इतिहास –

- दिन की शुरुआत कनाडा में प्लान इंटरनेशनल के रूप में हुई। इसकी शुरुआत एक एनजीओ ने की थी। बाद में एनजीओ ने संयुक्त राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को चिह्नित करने का अनुरोध किया।

भारत –

- भारत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों मनाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है।

बीजिंग घोषणा –

- यह महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन, 1995 में अपनाया गया था। सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के नेताओं ने वैश्विक समानता हासिल करने की योजना पर सहमति व्यक्त की।

कार्रवाई के लिए एक मंच –

- बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन महिलाओं बल्कि लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे प्रगतिशील खाका है।
- द प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन लैंगिक समानता पर प्रगति का आकलन करने के लिए एक शक्तिशाली आधार बना हुआ है।

- यह एक ऐसी दुनिया का आह्वान करता है, जहां हर लड़की और महिला अपने सभी अधिकारों को महसूस कर सकती है, जैसे कि हिंसा से मुक्त रहना, स्कूल जाना और पूरा करना, यह चुनने के लिए कि वह कब और किससे शादी करती है और समान काम के लिए समान वेतन अर्जित करती है।
- प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन विशेष रूप से वैश्विक समुदाय को –
  1. लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने
  2. लड़कियों के खिलाफ नकारात्मक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और प्रथाओं को खत्म करने
  3. लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना और उनकी आवश्यकताओं और क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने
  4. शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण में लड़कियों के साथ भेदभाव को खत्म करने
  5. स्वास्थ्य और पोषण में लड़कियों के प्रति भेदभाव को खत्म करने
  6. बाल श्रम के आर्थिक शोषण को खत्म करना और काम पर युवा लड़कियों की रक्षा करने
  7. लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने
  8. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लड़कियों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देने
  9. लड़कियों की स्थिति सुधारने में परिवार की भूमिका को मजबूत करने, की अपील करता है।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

समाचार –

- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य के समर्थन में प्रयास करना है।

विवरण –

- इस दिन की शुरुआत पहली बार वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा की गई थी।
- ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देशों में, यह दिन मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का एक हिस्सा है।
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 के लिए थीम 'मेंटल हेल्थ फॉर ऑल – ग्रेटर इनवेस्टमेंट – ग्रेटर एक्सेस' है।
- 2019 में 'मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन और आत्महत्या की रोकथाम' थीम के तहत दिवस मनाया गया।
- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस विश्व भर में स्वास्थ्य और नागरिक संगठनों के मंत्रालयों के साथ अपने मजबूत संबंधों का उपयोग करके मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से डब्ल्यूएचओ द्वारा समर्थित है।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए वर्ल्ड फेडरेशन –

- यह मानसिक और भावनात्मक विकारों को रोकने के लिए 1948 में स्थापित किया गया था।
- संगठन का उद्देश्य मानसिक विकारों को रोकना, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना और सर्वोत्तम पुनर्प्राप्ति प्रथाओं को अपनाना है।

इतिहास –

- पहली बार 10 अक्टूबर, 1992 को मनाया गया, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व महासंघ की एक वार्षिक गतिविधि के रूप में मनाया गया और इसकी कुछ विशिष्ट थीम थी।
- 1994 में, पहली बार दिन के लिए एक थीम का उपयोग किया गया था। दिन का पहला विषय 'दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार' था।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का महत्व –

- एक स्वस्थ भावनात्मक जीवन मुख्य रूप से एक व्यक्ति के दिमाग की प्रक्रिया, जानकारी, अनुभव और ज्ञान को समझने की प्रक्रिया है।
- मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भावनात्मक रूप से फिट होना जीवन के सभी पहलुओं में सफलता की कुंजी है।

भारिबै मौद्रिक नीति 2020

समाचार –

- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को चार प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा।

मुख्य विचार –

- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मौजूदा वित्त वर्ष में 9.5 प्रतिशत का अनुबंध कोरोनोवायरस महामारी की वजह से होगा।
- मुद्रास्फीति पर, भारिबै को लगातार गिरावट की उम्मीद है।
- सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान Q2 – 2020–21 के लिए 6.8 प्रतिशत, H2: 2020–21 के लिए 5.4–4.5 प्रतिशत और Q1: 2021–22 के लिए 4.3 प्रतिशत पर लगाया गया है।
- छह सदस्यीय एमपीसी इस सप्ताह तीन नए स्वतंत्र सदस्यों, शशांक भिडे, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा के शामिल होने के बाद मिली।
- एमपीसी वैधानिक समिति है जो देश की प्रमुख नीतिगत ब्याज दर और मौद्रिक नीति रुख के साथ–साथ मुद्रास्फीति लक्ष्य को भी तय करती है।

स्मॉग टॉवर –

समाचार –

- दिल्ली सरकार ने दस महीने के भीतर कनॉट प्लेस में दुनिया के दूसरे स्मॉग टॉवर की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी।

विवरण –

- दुनिया में पहला स्मॉग टॉवर चीन में स्थापित किया गया था।
- चीन में, स्मॉग टॉवर नीचे से प्रदूषित हवा चूसता है और ऊपर से स्वच्छ हवा छोड़ता है।
- भारत में, स्मॉग टॉवर ऊपर से प्रदूषित हवा चूसेंगे और नीचे से स्वच्छ हवा छोड़ेंगे।

स्मॉग टॉवर –

- दिल्ली का पहला स्मॉग टॉवर लाजपत नगर केंद्रीय बाजार में आया।

- 20 फुट ऊंचे टॉवर को प्रदूषित हवा में चूसने के लिए निकास पंखे से सुसज्जित किया गया है और यह दिल्ली की हवा में से 80% तक कण पदार्थ (पीएम 2.5 और पीएम 10) – प्राथमिक प्रदूषक को हटा सकता है।
- स्मॉग टावरों को बड़े पैमाने पर एयर प्यूरिफायर के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे आमतौर पर एयर फिल्टर की कई परतों के साथ फिट होते हैं, जो प्रदूषकों की हवा को साफ करते हैं क्योंकि यह उनके माध्यम से गुजरता है।
- स्मॉग टॉवर प्रदूषित हवा को चूसता है, जिसे वायुमंडल में पुर्नपरिचालित होने से पहले कई परतों द्वारा शुद्ध किया जाता है। हवा को शुद्ध करने के लिएय अत्यधिक प्रभावी H14 ग्रेड अत्यधिक प्रभावी पार्टिकुलेट अरेस्ट (HEPA) फिल्टर का उपयोग किया जाएगा। यह फिल्टर पूर्व फिल्टर और सक्रिय कार्बन की मदद से हवा में मौजूद 99.99% पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) को साफ कर सकता है।
- लाजपत नगर में स्थापित स्मॉग टॉवर डिजाइन में बेलनाकार है और एक बड़े इनलेट और चार आउटलेट इकाइयों के साथ एक पोल की तरह बनाया गया है। विशाल वायु शोधक निकास पंखे के साथ एक बड़ी इनलेट इकाई की मदद से प्रदूषित हवा में चूसने के लिए फिट है। इसे चार रंगों में चित्रित किया गया है – शीर्ष पर नारंगी, मध्य में सफेद, नीचे के ऊपर हरा रंग और सबसे नीचे नीला। टॉवर बिजली से चलेगा।

रूस्तम–II ड्रोन

समाचार –

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित रुस्तम–II मध्यम ऊंचाई वाले लंबे रूस्तम–II ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

विवरण –

- इसने 16,000 से अधिक की ऊंचाई पर आठ घंटे की उड़ान भरी।
- ड्रोन के 2020 के अंत तक 26,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे की निरंतर उड़ान प्राप्त करने की उम्मीद है।
- पेलोड के विविध संयोजनों को ले जाने में सक्षम, जिसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और स्थितिजन्य जागरूकता प्रणाली शामिल हैं।
- यह एक वास्तविक समय के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी को रिले करने के लिए एक उपग्रह संचार लिंक का दावा करता है।
- डीआरडीओ रूस्तम–2 ड्रोन को इजरायल हेरोन मानव रहित हवाई वाहन के विनिर्देशों से मेल करने के लिए विकसित कर रहा है जो पहले से ही भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किये जा रहे है।
- हेरॉन ड्रोन का तकनीकी उन्नयन और आर्मीकरण अनुबंध वार्ता समिति स्तर पर है।
- हेरॉन के उन्नयन में एक उपग्रह संचार लिंक स्थापित करना शामिल है ताकि जमीन पर भी स्थिति को रिले करने में कोई समय अंतराल न हो।
- मिसाइलों और लेजर गाइडेड बमों के लिए पंखों पर कठिन बिंदुओं को स्थापित करने के रूप में।
- जबकि इजरायलियों ने अपने सशस्त्र ड्रोन कार्यक्रम को कवर में रखा है, हेरॉन का एक हथियारबंद संस्करण है।
- भारत ने लागत के साथ सी गार्जियन निगरानी ड्रोन के बजाय अमेरिकी MQ–9B स्काई गार्जियन सशस्त्र ड्रोन के लिए जाने का फैसला किया है जिसके की खर्च एवं संख्याओं पर कार्य किया जा रहा है।
- MQ–9B में 40,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई के साथ 40 घंटे की क्षमता है। इसमें 2.5 टन से अधिक की पेलोड क्षमता भी है।
- इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम शामिल हैं।

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस

समाचार –

- विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में दो बार मनाया जाता है, अर्थात मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को।
- इससे पहले मई में, 9 मई 2020 को यह दिवस मनाया जाता था।
- दोनों दिन एक ही थीम के तहत मनाए जाते हैं।
- इस वर्ष, इस दिवस को – बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड थीम के तहत मनाया गया है।
- विश्व प्रवासी दिवस मनाने का विचार 1993 में अमेरिकी मछली और वन्यजीव सेवा द्वारा डिजाइन किया गया था।
- विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (WMBD) एक जागरूकता अभियान है, जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
- इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों, उनके पारिस्थितिक महत्व, और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के खतरों पर ध्यान आकर्षित करना है।
- यह अभियान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित दो अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संधियों द्वारा आयोजित किया जाता है। ये हैं –
  - (i) अफ्रीकी–यूरेशियन माइग्रेटरी वॉटरबर्ड समझौता
  - (ii) जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन।

विजया राजे सिंधिया

समाचार –

- प्रधानमंत्री ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया।
- विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप में भी जाना जाता है।
- राजमाता सिंधिया ने अपना जीवन राष्ट्र के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया और देश की भावी पीढ़ियों के लिए अपनी सारी खुशियों को त्याग दिया।

विजया राजे सिंधिया (12 अक्टूबर 1919 – 25 जनवरी 2001) –

- विजया राजे सिंधिया का जन्म 1919 में वर्तमान मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था। विजया राजे सिंधिया, जन्म दिव्येश्वरी देवी और ग्वालियर के राजमाता के रूप में लोकप्रिय थीं, एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक व्यक्तित्व थीं।
- ब्रिटिश राज के दिनों में, ग्वालियर के अंतिम शासक महाराजा, जीवाजीराव सिंधिया की सहमति के रूप में, वह भूमि के उच्चतम शाही इलाकों में से एक थे।
- बाद के जीवन में, वह काफी प्रभाव की राजनीतिज्ञ बन गईं और भारतीय संसद के दोनों सदनों के लिए बार–बार चुनी गईं।
- वह जनसंघ के एक सक्रिय सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के सह–संस्थापक भी थे।

कस्तूरी कपास

समाचार –

- केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने भारतीय कपास के लिए एक ब्रांड और एक लोगो का अनावरण किया।
- ब्रांडिंग – कस्तूरी कपास – शुरू में भारत में उगाए जाने वाले लंबे स्टेपल कपास पर लागू होगी और निर्धारित मानकों को पूरा करती है।

पृष्ठभूमि –

- भारतीय कपास का एक ब्रांड बनाना व्यापार की लंबे समय से लंबित आवश्यकता थी।
- मिस्र और अमेरिका जैसे दुनिया के कपास निर्यातक देशों के पास अपने कपास ब्रांड हैं।

महत्व –

- कस्तूरी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) को निर्यात बढ़ाने में मदद कर सकता है, क्योंकि केंद्र की MSP खरीद बढ़ने की उम्मीद है।
- कस्तूरी ब्रांड के बारीक मापदंडों से भारतीय कपास को प्रचलित बाजार मूल्य की तुलना में कम से कम 5% अधिक मूल्य का एहसास होगा।
- सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार –

- हर साल संयुक्त राष्ट्र 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में चिह्नित करता है।
- इस दिन को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस भी कहा जाता है।

विवरण –

- यह दिवस यह फैलाने के लिए मनाया जाता है कि कैसे दुनिया भर में लोग और समुदाय आपदाओं के जोखिम को कम कर रहे हैं।
- इस वर्ष, 2020 में, इस दिन को थीम 'आपदा जोखिम शासन' के तहत चिह्नित किया गया है।
- जोखिम–जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक दिन के आह्वान के बाद, 1989 में अंतर्राष्ट्रीय जोखिम निवारण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की गई थी।
- संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया।
- सात रणनीतिक लक्ष्य और 38 संकेतक आपदा नुकसान को कम करने पर प्रगति को मापने के लिए निर्धारित किए गए थे। 2016 से शुरू करके प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा गया था।
- 2016 – लक्ष्य 1 – 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करने के लिए। इसका उद्देश्य 2005–15 की तुलना में 2020–30 में वैश्विक मृत्यु दर को कम करना है।
- 2017 – लक्ष्य 2 – विश्व स्तर पर प्रभावित लोगों की संख्या को कम करने के लिए
- 2018 – लक्ष्य 3 – जीडीपी के संदर्भ में आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना
- 2019 – लक्ष्य 4 – आपदा के कारण बुनियादी सेवाओं के व्यवधान को कम करना
- 2020 – लक्ष्य 5 – 2020 तक राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों वाले देशों की संख्या में वृद्धि करना
- 2021 – लक्ष्य 6 – स्थायी और पर्याप्त समर्थन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए
- 2022 – लक्ष्य 7 – मल्टीहार्ड चेतावनी प्रणाली और आकलन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए।

अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार, 2020

समाचार –

- अल्फ्रेड नोबेल 2020 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में Sveriges Riksbank पुरस्कार संयुक्त रूप से पॉल आर मिल्ग्रोम और रॉबर्ट बी. विल्सन को नीलामी के सिद्धांत में सुधार के लिए और नए नीलामी प्रारूपों का आविष्कार करने के लिए प्रदान किया गया था।
- मिलग्रोम द्वारा तैयार सिद्धांत ने सामान्य और निजी मूल्यों की गणना करने की अनुमति दी जो बोली लगाने वाले से बोली लगाने वाले से भिन्न होते हैं।

विवरण –

- मिलग्रोम और विल्सन, दोनों कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं।
- 1969 और 2019 के बीच 84 पुरस्कारों के लिए पुरस्कार 51 बार दिया गया है। नियम के अनुसार पुरस्कार तीन से अधिक नहीं साझा किए जा सकते है।
- नोबेल आर्थिक पुरस्कार की स्थापना 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक Sveriges Riksbank फाउंडेशन के दान से नोबेल को मिली थी।
- यह 1895 में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किए गए पुरस्कारों में से एक नहीं है। लेकिन फिर भी इसे प्रशासित किया जाता है और नोबेल पुरस्कार के लिए भेजा जाता है।
- रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के अनुसार, अर्थशास्त्रियों ने एक विक्रेता केवल उच्चतम मूल्य प्राप्त करने के बजाए समाज के लिए अच्छा काम करने के प्रेरणा के साथ है की ओर से कई परस्पर संबंधित वस्तुओं की नीलामी के लिए नए प्रारूपों का आविष्कार किया।

सैनिकों के लिए मनोवैज्ञानिक कैप्सूल

समाचार –

- आतंकी समूहों में शामिल होने वाले युवाओं के बढ़ते मामलों के बीच, भारतीय सेना ने उन सैनिकों के लिए अपने प्रशिक्षण में एक बदलाव किया है जो कि दुरदराज के क्षेत्रों और नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर तैनात हो रहे हैं।

लक्ष्य –

- सैनिकों को नागरिक आबादी के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना

विवरण –

- सैनिकों के प्रति नागरिकों को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए सेना ने जनवरी में एक कैप्सूल पेश किया है।
- इस कैप्सूल को डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च (DIPR) के साथ मिलकर विकसित किया गया है।
- इस मनोविज्ञान कैप्सूल के माध्यम से प्रशिक्षुओं से 250 सैनिकों / अधिकारियों को चयनित किया गया।
- खुरस बैटल स्कूल में प्रशिक्षण का उद्देश्य, क्रू, सैनिकों के संज्ञानात्मक सीखने की मदद से न केवल परिचालन रिफ्लेक्सिस में सुधार करना है, बल्कि उसे स्थानीय लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं होने के लिए कैप्सूल के माध्यम से जाना है और संपार्श्विक क्षति को दूर करना है।
- सामान्य संवेदीकरण कैप्सूल में आत्मसमर्पण करने के लिए मुठभेड़ों में पकड़े गए स्थानीय युवाओं को समझाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- 15 कॉर्प्स क्षेत्र के तहत घाटी और एलओसी पर तैनात सभी सैनिकों को सीबीएस (कॉर्प्स बैटल स्कूल) में एक संवेदीकरण कार्यक्रम से गुजरना पड़ता है।
- एलओसी पर तैनात सभी कर्मियों को 14 दिन का कैप्सूल और घाटी में तैनात 28 दिन के कैप्सूल से गुजरना पड़ता है।
- चार सिद्धांत हैं जिन पर उन्मुखीकरण आधारित है – अच्छा विश्वास और आचरण, न्यूनतम बल, संपार्श्विक क्षति, निष्पक्षता और संचालन की आवश्यकता।
- प्रशिक्षण अभ्यास के अलावा, सैनिकों को एलओसी के साथ–साथ एयरड्रॉप के लिए यूएवी के उपयोग के आसन्न खतरों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है और आतंकवादियों के परिवार के सदस्यों की मदद के लिए उन्हें आत्मसमर्पण के लिए राजी किया जा रहा है।

विश्व विद्यार्थी दिवस

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया।
- विश्व छात्र दिवस 2020 का विषय 'लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना' है।

विवरण –

- विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर चिह्नित किया जाता है।
- 'मिसाइल मैन ऑफ इंडिया' के रूप में लोकप्रिय, कलाम का जन्म 15 अक्टूबर, 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11 वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
- कलाम न केवल एक राजनीतिज्ञ और एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे, बल्कि एक शिक्षक भी थे। वे चाहते थे कि दुनिया उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद रखे।
- कलाम की मृत्यु 27 जुलाई, 2015 को हुई थी। उन्हें शिक्षण पसंद था। जब उनकी मृत्यु हुई वे आईआईएम शिलॉन्ग के छात्रों को एक व्याख्यान दे रहे थे।

स्टार्स प्रोजेक्ट

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ल्ड बैंक समर्थित स्ट्रेंथिंग टीचिंग–लर्निंग एंड स्टेट्स–स्टेट्स–प्रोजेक्ट के लिए परिणाम को मंजूरी दे दी है।
- इस परियोजना में शिक्षा के परिणामों में सुधार के लिए प्रत्यक्ष संबंधों के साथ हस्तक्षेपों के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और सुधार में राज्यों का समर्थन करना है।
- परियोजना चयनित राज्यों में हस्तक्षेप के माध्यम से भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में समग्र निगरानी और माप गतिविधियों में सुधार करती है।

विवरण –

- विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल परियोजना लागत 5 हजार 718 करोड़ रुपये है।
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत STARS परियोजना को एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।
- यह परियोजना छह राज्यों, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा को कवर करेगी।
- परियोजना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी।

जोजोला टनल

समाचार –

- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कोजीगल जिले के जोजीला में जोजीला सुरंग कार्य शुरू करेगा।
- सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर सैनिकों की सभी मौसम की आवाजाही के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

विवरण –

- यह सुरंग NH–1 पर श्रीनगर घाटी और लेह (लद्दाख पठार) के बीच सभी मौसम की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, और जम्मू और कश्मीर के एक सर्वांगीण आर्थिक और सामाजिक–सांस्कृतिक एकीकरण को सामने लाएगी।
- परियोजना में जोजिला पास के तहत लगभग 3,000 मीटर की ऊँचाई पर 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण शामिल है, जो वर्तमान में केवल वर्ष में 6 महीने के लिए मोटर योग्य है, एनएच–1 पर श्रीनगर और लेह को द्रास एंड कारगिल के माध्यम से जोड़ता है।
- यह वाहन चलाने के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है।

विशेष किसान रेल

समाचार –

- केंद्रीय परिवहन मंत्री ने नागपुर रेलवे स्टेशन से चौथी स्पेशल किसान रेल 'नागपुर–आदर्श नगर नई दिल्ली' को रवाना की।
- वर्तमान में तीन अन्य किसान रेल – नासिक से दानापुर, नई दिल्ली से अनंतपुर तथा बेंगलुरु से हजरत निजामुद्दीन तक फल और सब्जियों का संचालन कर रही हैं।

विवरण –

- यह ट्रेन विदर्भ में खट्टे उत्पादक जिलों से 205 टन संतरों की पहली खेप ले जाएगी।
- ट्रेन का स्टेशन– कटोल, नरखेड़, पांढुर्ना, बैतूल, इटारसी में ठहराव होगा।
- किसान रेल का संचालन मध्य रेलवे के नागपुर मंडल द्वारा किया जाता है।
- किसान रेलवे कृषि उपज के परिवहन की लागत को कम करेगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा जिससे विदर्भ के किसानों में आर्थिक परिवर्तन आएगा।
- सरकार ने अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन लागत पर 50% अनुदान की घोषणा की, जो किसान रेल द्वारा किया जाएगा।
- यह सब्सिडी 11 दिसंबर तक व्यक्तिगत किसानों, खाद्य प्रोसेसर, सहकारी समितियों, खुदरा विक्रेताओं, राज्य और सहकारी विपणन एजेंसियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
- अधिसूचित फलों में केला, अमरूद, आम, खट्टे, अनानास, अनार, पपीता और जैक फल और सब्जियों प्याज, आलू, टमाटर, फ्रेंच बीन्स, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी और भिंडी की सूची शामिल हैं।
- सब्सिडी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा वहन किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर पहल के तहत सभी फलों और सब्जियों (TOTAL) को टमाटर, प्याज और आलू (TOP) से ऑपरेशन ग्रीन्स को लागू कर रहा है।
- केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय रेलवे की संतरा किसान रेलवे वेबसाइट का भी उद्घाटन किया, जिसमें कृषि उपज के लिए बुकिंग की सुविधा है।

ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

समाचार –

- ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
- यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की आजीविका और समग्र कल्याण तथा स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण सुधार लाने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है।
- इन महिलाओं के संघर्षों, उनकी आवश्यकताओं और हमारे समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, ग्रामीण महिलाओं के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम 'कोविड–19 के मद्देनजर ग्रामीण महिलाओं को मजबुत बनाना है।'

पृष्ठभूमि –

- ग्रामीण महिलाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया था।
- इसने कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार और ग्रामीण लोगों के उन्मूलन में स्वदेशी महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को मान्यता दी है।

महिला किसान दिवस

समाचार –

- कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 15 अक्टूबर 2020 को महिला किसान दिवस का आयोजन किया।
- प्रगतिशील महिला किसानों की प्रेरक कहानियां 'पर एक ई–पुस्तक का विमोचन किया गया और महिला कृषक और उनके योगदान पर दो लघु फिल्में और 'सफल महिला किसानों के वैश्विक उदाहरण' लॉन्च की गई।

झलकियाँ –

- महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को भारत में पहली बार 2017 में मनाया गया।
- दिवस का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है।
- यह कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने के लिए किया जा रहा था क्योंकि भारत में 80% स्वतंत्र महिलाएं कृषि क्षेत्र से जुड़ी थीं, जबकि महिलाएं सभी कृषि परिवारों का 18% नेतृत्व करती हैं।
- स्मरणोत्सव के लिए टैगलाइन तय की गई है– 'सशक्त महिला, सशक्त भारत' (सशक्त महिला, सशक्त भारत)।

आईएनएस सिंधुवीर

समाचार –

- भारत रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में म्यांमार नौसेना को एक किलो वर्ग पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर वितरित करेगा।
- यह एक ऐसा कदम है जो क्षेत्र में अपने सैन्य प्रभाव का विस्तार करने के चीन के बढ़ते प्रयासों की पृष्ठभूमि में आता है।

झलकियाँ –

- मार्च 2020 तक जहाज को म्यांमार नौसेना को वितरित किया जाना था।
- यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी।
- यह भारत की एसएजीएआर सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास के दृष्टिकोण के अनुसार है।
- यह हमारे सभी पड़ोसी देशों में क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

सामरिक महत्व –

- म्यांमार भारत के रणनीतिक पड़ोसियों में से एक है और उग्रवाद प्रभावित नागालैंड और मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों की 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।

कोलो क्लास पनडुब्बी –

- कीलो क्लास, सोवियत पदनाम परियोजना 877 पाल्टर, सोवियत नौसेना के लिए सोवियत संघ में डिजाइन और निर्मित डीजल–इलेक्ट्रिक हमले पनडुब्बियों का एक वर्ग है।
- 1990 के मध्य तक वर्ग का निर्माण किया गया था, जब उत्पादन को अधिक उन्नत परियोजना 636 वर्षाव्यंका संस्करण में बदल दिया गया था, जिसे पश्चिम द्वारा बेहतर कीलो–क्लास भी कहा जाता था।
- ये हमले पनडुब्बियां मुख्य रूप से अपेक्षाकृत उथले पानी में शिपिंग और एंटी–पनडुब्बी संचालन के लिए होती हैं।
- मूल परियोजना 877 नावें रुबिकॉन एमजीके–400 सोनार प्रणाली से लैस हैं, जिसमें एक खदान का पता लगाने और परिहार एमजी–519 आरफा शामिल है।

नगरनार स्टील प्लांट

समाचार –

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर नागरनार स्टील प्लांट (NSP) के अवगुणों को अपनी सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है।
- मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NMDC) लिमिटेड मंत्रिमंडल ने एक रणनीतिक खरीदार को संपूर्ण भारत सरकार की हिस्सेदारी बेचकर ध्वस्त कंपनी (एनएसपी) के रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी दी।
- डिमर्जर और विनिवेश की प्रक्रियाएं एक साथ शुरू की जाएंगी और डिमर्जर कंपनी (NSP) का विनिवेश सितंबर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।

नगरनार स्टील प्लांट (NSP) –

- NSP नगरनार, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ में NMDC द्वारा स्थापित किया जा रहा एक मिलियन टन प्रति वर्ष (mta) एकीकृत स्टील प्लांट है।
- NMDC स्टील मंत्रालय के तहत एक सूचीबद्ध CPSE है और भारत सरकार की कंपनी में 69.65% शेयरधारिता है।
- एनएमडीसी लौह अयस्क, तांबा, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट, मैग्नेसाइट, हीरा, टिन, टंगस्टन, ग्रेफाइट, आदि की खोज में शामिल है।

एमएसीएस–6478

समाचार –

- एमएसीएस 6478 नामक नई गेहूं किस्म महाराष्ट्र के एक गांव में किसानों को उनकी उपज को दोगुना करने में मदद कर रही है।
- इस गेहूं की किस्म को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, अघारकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई) के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है।
- इस गेहूं के आटे से चपाती भी गुणवत्ता में उच्च होती है।

विवरण –

- नव विकसित आम गेहूं या ब्रेड गेहूं, जिसे उच्च उपज देने वाला एस्टिवम भी कहा जाता है, 110 दिनों में परिपक्व हो जाता है और पत्ती और तने के जंग के अधिकांश नस्लों के लिए प्रतिरोधी होता है।
- एम्बर रंग के मध्यम आकार के अनाज में 14% प्रोटीन, 44.1 पीपीएम जस्ता और 42.8 पीपीएम लोहा होता है जो अन्य खेती की किस्मों से अधिक है।
- इस गेहूं के आटे की चपाती की गुणवत्ता उत्कृष्ट है, अच्छी रोटी की गुणवत्ता के साथ 8.05 का स्कोर 6.93 है।
- बीज गुणन के लिए महाराष्ट्र राज्य बीज एजेंसी, श्महाबीजश किसानों के उपयोग के लिए एमएसीएस 6478 का प्रमाणित बीज उत्पादन कर रही है।
- महाराष्ट्र के किसानों को अब नई किस्म के साथ 45–60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिल रही है, जबकि पहले औसत उपज 25–30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जब उन्होंने 1, एचडी 2189 और अन्य पुरानी किस्मों की खेती की थी।

विश्व खाद्य दिवस

समाचार –

- विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है।
- इस वर्ष, विश्व खाद्य दिवस थीम के तहत मनाया जाता है – ग्रो, नॉरिश, सस्टेन। टुगेदर। अवर एक्शन्स आर अवर फ्युचर।
- थीम इस तरह से काम करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है कि हर व्यक्ति को सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक मात्रा में पौष्टिक भोजन मिले।

विवरण –

- यूएन खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने 1979 में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में नामित किया।
- विश्व खाद्य दिवस को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है।
- विश्व खाद्य दिवस 2020 का महत्व है क्योंकि इस वर्ष एफएओ की 75 वीं वर्षगांठ है, जो दुनिया भर में 130 से अधिक देशों में काम करता है।
- एफएओ का लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है और यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच हो।

गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020

समाचार –

- गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है।
- यह दुनिया भर में गरीबी, भूख, हिंसा, भय को चिह्नित करने और इसे कम करने के तरीके खोजने का दिन है।

विषय –

- इस वर्ष का विषय 'सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करना' है।
- इस वर्ष दिवस के लिए विषय सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने की चुनौती को संबोधित करता है।

- गरीबी की बहु–आयामीता की बढ़ती मान्यता का अर्थ है कि ये दो मुद्दे अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं, और यह कि सामाजिक न्याय पूरी तरह से पर्यावरणीय अन्याय को ठीक किए बिना महसूस नहीं किया जा सकता है।

विश्व सांख्यिकी दिवस 2020

समाचार –

- तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को दुनिया भर में मनाया जाएगा, इस विषय पर 'दुनिया को हम जिस डेटा पर भरोसा कर सकते हैं, उससे जोड़ना'।
- यह विषय विश्वास, आधिकारिक डेटा, नवाचार और राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणालियों में जनता की भलाई के महत्व को दर्शाता है।

विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 अभियान –

- विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 का उत्सव संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकीय आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित एक वैश्विक सहयोगी प्रयास है।
- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक मामलों के विभाग का सांख्यिकी विभाग अभियान का वैश्विक समन्वयक है।

भारत का पहला सीप्लेन प्रोजेक्ट

समाचार –

- गुजरात में पांच सीप्लेन सेवाओं में से पहली, नर्मदा जिले के केवडिया में अहमदाबाद में साबरमती नदी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ पटेल की जयंती पर उद्घाटन किया जाएगा।
- अन्य स्थान हैं, मेहसाणा जिले के धारोई बांध, भावनगर जिले के पलिताना में अंबाजी और शत्रुंजय बांध को जोड़ने के लिए और साथ ही अगले चरण में तापी।

भारत की पहली सीप्लेन परियोजना क्या है?

- यह परियोजना केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का हिस्सा है।
- निर्देश के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों से अनुरोध किया और अंडमान और निकोबार के प्रशासन ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जल एयरोड्रोम स्थापित करने के लिए संभावित स्थानों का प्रस्ताव किया है।
- एक सीप्लेन एक निश्चित पंख वाला हवाई जहाज है जो पानी पर उतरने के लिए बनाया गया है।
- यह एक नाव की उपयोगिता के साथ जनता को एक हवाई जहाज की गति प्रदान करता है।
- दो मुख्य प्रकार के सीप्लेन हैं – फ्लाइंग बोट (जिन्हें अक्सर पतवार सीप्लेन कहा जाता है) और फ्लोटप्लेन।
- फ्लाइंग बोट के धड़ के नीचे इसका मुख्य लैंडिंग गियर होता है। यह आमतौर पर विंगटिप्स के पास छोटे फ्लोट के साथ पूरक होता है, जिसे विंग या टिप फ्लोट कहा जाता है। एक फ्लाइंग बोट के पतवार में चालक दल, यात्रियों के बैठने और सामान रखने की व्यवस्था होती है, इसमें जहाज या नाव के पतवार से कई समानताएँ हैं।

चीनी गुलाबी डॉल्फिन

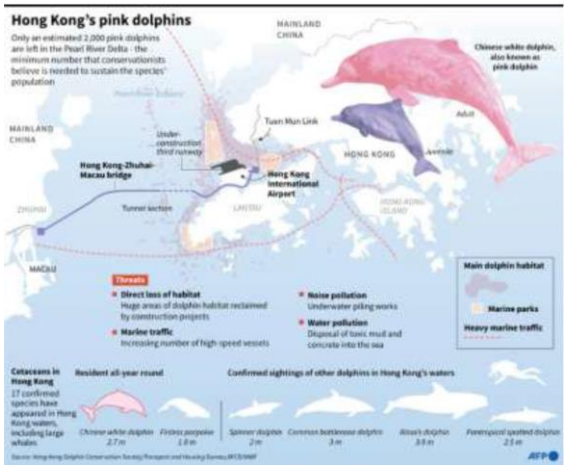

समाचार –

- चीनी गुलाबी डॉल्फिन पर्ल नदी के मुहाने में वापसी कर रहे हैं।
- पर्ल नदी मुहाना में हांगकांग, मकाऊ और साथ ही शेन्जेन, ग्वांगझोउ और डोंगगू के मुख्य भूमि चीनी शहर शामिल हैं।
- आईयूसीएन स्थिति – कमजोर।

विवरण –

- पिछले 15 वर्षों में पिंक डॉल्फिन की संख्या में 70–80 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।
- डॉल्फिन पानी में अपना रास्ता खोजने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं।
- मुहाना दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है।
- जहाज अक्सर डॉल्फिन को अपना रास्ता खोजने में परेशान करते हैं और यहां तक कि उन्हें मार भी देते हैं।
- लेकिन हॉन्गकॉन्ग और मकाऊ के बीच के पानी में डॉल्फिन की संख्या में इस साल एक पलटाव देखने को मिला है क्योंकि नोवेल कोरोनावायरस बीमारी महामारी ने घाटों को बंद कर दिया है।
- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अनुसार, पर्ल नदी डेल्टा में केवल अनुमानित 2,000 – प्रजातियों को बनाए रखने कि न्यूनतम संख्या, गुलाबी डॉल्फिन बचे हैं।
- डॉल्फिन, और विशेष रूप से ये एस्टुरीन डॉल्फिन, की धीमी जन्म दर, धीमी वृद्धि दर, और धीमी प्रजनन दर होती है।

मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमाडोमीटर (MODIS)

समाचार –

- नासा के एक्वा उपग्रह पर मॉडरेट रिजॉल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमाडोमीटर या MODIS ने बोलिविया के विशाल स्वाथे में जलने वाली आग पर कब्जा कर लिया है।
- दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वेटलैंड पैंटाल में आग जल रही है, जो बोलीविया के पूर्वी हिस्से में स्थित है।
- आग दक्षिण–पूर्व बोलीविया के सूखे चीकिटानो जंगल और उत्तर में बेनी सवाना और अमेजॅन वर्षावन क्षेत्रों में भी लगी है।

कारण –

- नासा ने आग के लिए लंबे समय तक सूखे के साथ–साथ हाल ही में गर्मी की लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
- अटलांटिक महासागर में गर्म तापमान पर सूखे को दोषी ठहराया गया है जिससे उत्तरी गोलार्ध में नमी आ गई है।

MODIS –

- MODIS एक पेलोड इमेजिंग सेंसर है जिसे 1999 में नासा द्वारा पृथ्वी की कक्षा में टेरा (EOS AM) उपग्रह पर और 2002 में Aqua (EOS PM) उपग्रह पर लॉन्च किया गया था।
- उपकरण 36 स्पेक्ट्रल बैंड में तरंगदैर्ध्य में 0.4 μm से 14.4 μm तक और अलग–अलग स्थानिक संकल्पों में डेटा कैप्चर करते हैं।
- यंत्र हर 1 से 2 दिन में पूरी पृथ्वी की छवि बनाते हैं।
- वे बड़े पैमाने पर वैश्विक गतिशीलता में माप प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिसमें पृथ्वी के बादल कवर, विकिरण बजट और महासागरों में होने वाली प्रक्रियाओं, भूमि पर और निचले वातावरण में परिवर्तन शामिल हैं।
- अपने कम स्थानिक रिजॉल्यूशन लेकिन उच्च अस्थायी समाधान के साथ, मॉडिस डेटा समय के साथ परिदृश्य में बदलाव को ट्रैक करने के लिए उपयोगी होते हैं।

COVIRAP

समाचार –

- इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में COVIRAP नामक कोविड–19 परीक्षण को मंजूरी दी।
- आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित, कोरोनावायरस के तेजी से निदान के लिए एक कम लागत वाली पोर्टेबल इकाई है, जो एक घंटे के भीतर परिणाम उत्पन्न करती है।

विवरण –

- परीक्षण सुविधा कहीं भी रखी जा सकती है और एक वातानुकूलित प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है।
- COVIRAP विधि के लिए बहुत कम उपकरणों की आवश्यकता होती है, और सीमित सुविधाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए आदर्श है। इसे ग्रामीण युवाओं द्वारा न्यूनतम प्रशिक्षण के साथ संचालित किया जा सकता है।
- यह नई परीक्षण विधि एक अति विश्वसनीय और सटीक आणविक नैदानिक प्रक्रिया को लागू करती है, जो अल्ट्रा–लो–कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस यूनिट में आयोजित की जाती है और प्रति परीक्षण केवल 500 के आसपास खर्च होती है।
- प्रत्येक परीक्षण में एक किट, तीन मास्टर–मिक्स की आवश्यकता होती है जो टीम द्वारा बनाई जाती है। मिश्रण और हीटिंग के कई चरणों के बाद, परीक्षण स्ट्रिप्स की एक छवि को कस्टम–निर्मित मोबाइल एप्लिकेशन के स्मार्टफोन कैमरा द्वारा पकड़ा जाता है, और एक निश्चित परिणाम उत्पन्न होता है।
- उनके परीक्षण के परिणामों ने पुष्टि की है कि विधि और परिणाम उच्चतम मानकों के हैं और उच्च–अंत आरटी–पीसीआर परीक्षणों के लिए तुलनीय हैं।
- इससे इन्फ्लूएंजा, मलेरिया, तपेदिक, और डेंगू सहित अन्य बीमारियों की जाँच भी हो सकती है।

CuRED

समाचार –

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'सीएसआईआर उशरड रिपरपज़्ड ड्रग्स' पोर्टल लॉन्च किया जिसे CuRED कहा जाता है।
- पोर्टल सीएसआईआर द्वारा पुनः प्रस्तुत दवाओं के बारे में विवरण प्रदान करेगा।

पृष्ठभूमि –

- सीएसआईआर महामारी की शुरुआत के बाद से COVID–19 के संभावित उपचार के लिए मेजबान–निर्देशित चिकित्सा के साथ एंटीवायरल के कई संयोजन नैदानिक परीक्षणों की खोज कर रहा है।

CuRED –

- यह सीएसआईआर रिपरपज़्ड दवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
- वेबसाइट, CuRED, निदान और उपकरणों के नैदानिक परीक्षणों के बारे में विवरण प्रदान करेगी जिसमें वैज्ञानिक निकाय शामिल हैं।
- पांच नैदानिक परीक्षण, विथानिया सोम्निफेरा, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया प्लस पाइपर लोंगम (संयोजन में), ग्लाइसीर्रिजा ग्लबरा, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और अधतोडा वासिका (व्यक्तिगत रूप से और संयोजन में) और आयुष–64 फॉर्मूलेशन सुरक्षा और प्रभावकारिता परीक्षणों से गुजर रहे हैं।
- सीएसआईआर द्वारा एक प्रमुख नैदानिक परीक्षण कैडिला की साझेदारी में कोविड–19 के खिलाफ सेप्सिवैक (Mw) का है।
- इस दवा का चरण–दो नैदानिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और एक अधिक व्यापक चरण–तीन परीक्षण एनविल पर है।
- सन फार्मा और DBT के साथ कोविड–19 रोगियों पर फाइटोफार्मास्युटिकल AQCH का चरण–दो परीक्षण चल रहा है।

एटलांटिफिकेशन

समाचार –

- वैज्ञानिकों ने 'हॉटस्पॉट्स' को उजागर किया है, जहां बैरेंट्स सागर के कुछ हिस्से अटलांटिक जैसे दिखने लगे हैं। इस घटना को 'एटलांटिफिकेशन' कहते हैं।

एटलांटिफिकेशन क्या है?

- स्कैंडिनेविया के ऊपर के समुद्रों में, एक बिंदु है जहां आर्कटिक महासागर अटलांटिक के गर्म, खारे पानी से टकराता है।
- यहाँ आर्कटिक क्षेत्र – जिसे बैरेंट्स सी के रूप में जाना जाता है – ने हाल के दशकों में तेजी से बदलाव किया है।
- औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से यहां के हवा के तापमान वैश्विक औसत दर से चार गुना से अधिक बढ़ गए हैं।
- बढ़ते प्रमाण हैं, सुझाव है कि आर्कटिक महासागर की अनूठी संरचना इस क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने 'हॉटस्पॉट्स' को उजागर किया है, जहां बैरेंट्स सागर के कुछ हिस्से अटलांटिक से अधिक निकटता से शुरू हो रहे हैं। इस घटना को 'एटलांटिफिकेशन' कहते हैं।

कारण –

- इन सभी की पृष्ठभूमि में वैश्विक जलवायु परिवर्तन है।
- वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण आर्कटिक की समुद्री सीमा और मोटाई दशकों से गिर रही है।
- जैसे–जैसे आर्कटिक बर्फ खोता है और महासागर अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है।
- यह समुद्री संचलन, मौसम के पैटर्न और आर्कटिक पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित करता है, जो खाद्य श्रृंखला में फैटोप्लांकटन से लेकर शीर्ष शिकारियों तक सभी को प्रभावित करता है।

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS–01

समाचार –

- भारत 7 नवंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष यान से अपने नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस–01 और नौ अंतरराष्ट्रीय ग्राहक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा।
- EOS–01 कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन समर्थन में अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत है।
- ग्राहक उपग्रहों को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), अंतरिक्ष विभाग के साथ वाणिज्यिक समझौते के तहत लॉन्च किया जा रहा है।

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह –

- एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या अर्थ रिमोट सेंसिंग उपग्रह एक उपग्रह है जिसका उपयोग पृथ्वी के अवलोकन (ईओ) के लिए कक्षा से किया जाता है, जिसमें जासूसी उपग्रह और इसी तरह के गैर–सैनिक उपग्रह शामिल हैं।
- पर्यावरण निगरानी, मौसम विज्ञान, कार्टोग्राफी और अन्य जैसे उपयोग करता है।
- सबसे आम प्रकार पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह हैं, जो उपग्रह चित्रों को लेते हैं, जो हवाई तस्वीरों के अनुरूप हैं, कुछ ईओ उपग्रह चित्र बनाने के बिना रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, जैसे कि जीएनएसएस रेडियो कांड।
- 1988 में IRS–1, से शुरू होकर, ISRO ने कई ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए हैं।
- आज, भारत के पास सुदूर संवेदी उपग्रहों का सबसे बड़ा तारामंडल है।
- वर्तमान में, 'तेरह ' परिचालन उपग्रह सूर्य–समकालिक कक्षा में और 'चार' भूस्थैतिक कक्षा में हैं।

आदिवासी कल्याण के लिए उत्कृष्टता केंद्र

समाचार –

- केंद्रीय जनजातीय मंत्री ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) और आर्ट ऑफ लिविंग (AoL) के बीच सहयोग में जनजातीय कल्याण के लिए दो उत्कृष्टता केंद्र (CoE) का शुभारंभ किया।
- आर्ट ऑफ लिविंग के पास स्वयंसेवकों का एक विशाल नेटवर्क है जो इस कार्यक्रम को सफल बनाएगा। AoL पूरे भारत में 750 स्कूल चला रहा है।

विवरण –

- महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 10ए000 आदिवासी किसानों को गो–अधारित कृषि तकनीकों पर आधारित स्थायी प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के क्षेत्र में पहला सीओई। किसानों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिलाने में मदद की जाएगी और उनमें से प्रत्येक आत्मनिर्भर आदिवासी किसानों को बनाने के लिए मार्केटिंग के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- झारखंड के 30 ग्राम पंचायतों और 150 गाँवों को कवर करने वाले 5 जिलों में पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ करने के क्षेत्र में दूसरा सहयोग।
- आदिवासी पीआरआई को मजबूत करने से उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करने में मदद मिलेगी।
- यह निर्णय लेने और उनके समुदाय के विकास से संबंधित मामलों में पीआरआई को सशक्त करेगा।
- ये कदम अत्निनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेगा।

सामान्य अध्ययन– ।
भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल और समाज

कामचटका आपदा

समाचार –

- एक 'पारिस्थितिक आपदा' रूसी सुदूर पूर्व में कामचटका प्रायद्वीप के एक काले ज्वालामुखी समुद्र तट पर सामने है।
- कामचटका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।

संकट –

- पेट्रोपावलोव्स्क–कामचत्स्की के बाहर खलकट्रीस्की समुद्र तट पर सर्फर्स ने आंखों, गले में दर्द, सिरदर्द, बुखार और पानी से उभरने पर आंखों की रोशनी खोने का डर का अनुभव किया।
- फिर, बड़ी संख्या में लाखों समुद्री जानवर मरने लगे। उनके शव समुद्र तट पर इकट्ठे होना शुरू हो गए। इनमें ऑक्टोपस, सील, समुद्री अर्चिन, तारे, केकड़े और मछली शामिल थे।

ऐसा क्यों हो रहा है?

- प्रशासकों ने दिखाया है कि फिनोल और तेल यौगिकों का स्तर समुद्र के पानी में बढ़ गया है।
- जबकि, उपग्रह तस्वीरें पीले रंग में एक नदी दिखाती हैं जो इस क्षेत्र में प्रशांत महासागर में बह रही हैं।
- इसके अलावा, ऐसी आशंकाएं हैं कि सैन्य परीक्षण के मैदान में संग्रहीत रॉकेट ईंधन लीक हो सकता है। रूसी सैन्य अपस्ट्रीम का एक प्रशिक्षण शिविर है।
- एक अन्य सिद्धांत में अनुमान लगाया जा रहा है कि आसपास के क्षेत्र में तेल ले जाने वाले जहाजों ने इसे समुद्र के पानी में रिसाव किया था।

तापमान में वृद्धि –

- अंटार्कटिक महाद्वीप के सबसे उत्तरी सिरे, अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर 2020 में तापमान लगभग तीन दशकों में सबसे अधिक रहा है।
- यह एक खतरनाक विकास था क्योंकि यह संकेत दे सकता है कि क्षेत्र में महासागर एक बार फिर से गर्म हो रहा था।

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल –

- (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य माना जाने वाले दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, संरक्षण और संरक्षण को प्रोत्साहित करना चाहता है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है जिसे 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन कहा जाता है।

मिशन –

- वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने और अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशों को प्रोत्साहित करें।
- विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए अपने राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर साइटों को नामित करने के लिए कन्वेंशन के लिए राज्यों की पार्टियों को प्रोत्साहित करें।
- राज्यों को प्रोत्साहित करें कि वे प्रबंधन योजनाओं की स्थापना करें और अपने विश्व विरासत स्थलों के संरक्षण की स्थिति पर रिपोर्टिंग सिस्टम स्थापित करें।
- राज्यों की पार्टियां तकनीकी सहायता और पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करके विश्व विरासत संपत्तियों की सुरक्षा करे।
- तत्काल खतरे में विश्व विरासत स्थलों के लिए आपातकालीन सहायता प्रदान करें।
- विश्व विरासत संरक्षण के लिए सहायता राज्यों की सार्वजनिक जागरूकता निर्माण गतिविधियों का समर्थन करे।
- अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में स्थानीय आबादी की भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
- हमारे विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करें।

विश्व धरोहर स्थल क चयन का मानदंड –

- स्थल में जैविक विविधता का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास होना चाहिए।
- इसमें संरक्षण के बिंदु में सार्वभौमिक मूल्य की खतरे वाली प्रजातियां शामिल हैं।
- यह चल रही जैविक और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए।
- यह मीठे पानी और स्थलीय तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और जानवरों और पौधों के समुदायों का विकास करता हो।
- पृथ्वी के इतिहास का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थान उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए।
- इसमें आपकी तार्किक प्रक्रियाएँ होनी चाहिए जो लैंडफॉर्म, जियोमॉर्फिक और फिजोग्राफिक सुविधाएँ विकसित करती हैं।
- इसमें स्थिर महत्व और प्राकृतिक सुंदरता की प्राकृतिक घटना होनी चाहिए।
- यह स्थल उन घटनाओं से जुड़ी होनी चाहिए जो सार्वभौमिक महत्व रखती हैं।
- यह पारंपरिक भूमि के उपयोग का एक उदाहरण होना चाहिए।
- यह वास्तुशिल्प परिदृश्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए जो महत्वपूर्ण चरणों में मानव इतिहास का चित्रण करता है।
- इसमें सांस्कृतिक परंपरा की गवाही होनी चाहिए।

- इसे स्मारकीय कला शहर योजना और परिदृश्य डिजाइन में विकास को प्रदर्शित करना चाहिए।
- यह मानवीय सृजनशीलता की उत्कृष्ट कृति होनी चाहिए।

कम दबाव क्षेत्र

समाचार –

- उत्तरी अंडमान सागर और उसके पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके उत्तर आंध्र प्रदेश में भारी बारिश होने का अनुमान है।
- मछुआरों को मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन समुद्र और अंडमान समुद्र में उद्यम नहीं करने के लिए कहा गया है।

कम दबाव क्षेत्र –

- कम दबाव वाला क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र होता है, जहां हवा का दबाव आसपास के स्थानों की तुलना में कम होता है।
- कम दबाव प्रणाली हवा के विचलन के क्षेत्रों के तहत बनती है जो वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में होती है। कम दबाव वाले क्षेत्र की गठन प्रक्रिया को साइक्लोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है।
- कम दबाव वाला क्षेत्र आमतौर पर खराब मौसम के साथ जुड़ा होता है, जबकि उच्च दबाव वाला क्षेत्र हल्की हवाओं और निष्पक्ष आसमान से जुड़ा होता है।
- कम दबाव वाले क्षेत्र ऐसे स्थान हैं जहां वातावरण अपेक्षाकृत पतला होता है।
- हवाएँ इन क्षेत्रों की ओर भीतर की ओर बढ़ती हैं। इससे हवा उठती है, बादलों और संघनन का उत्पादन होता है।
- कम दबाव वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से संगठित तूफान होते हैं।

भुमध्य न्यून दबाव क्षेत्र (इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट) या डॉल्ड्रम्स –

- 10° N और 10° S अक्षांशों के बीच स्थित है।
- चौड़ाई 5° N और 5° S और 20° N और 20° S के बीच भिन्न हो सकती है।
- यह बेल्ट उप–उष्णकटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट से दो गोलार्द्धों से व्यापार हवाओं के अभिसरण का क्षेत्र होता है।
- बेहद शांत हवा की चाल के कारण इस बेल्ट को डोलड्रम्स भी कहा जाता है।
- बेल्ट की स्थिति सूर्य के स्पष्ट आंदोलन के साथ बदलती है।

उप–ध्रुवीय निम्न दबाव बेल्ट –

- 45° N और S अक्षांशों और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल (66.5° N और S अक्षांश) के बीच स्थित है।
- इन अक्षांशों में कम तापमान के कारण उप ध्रुवीय कम दबाव की बेल्टें साल भर अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होती हैं।
- लंबे समय तक औसत जलवायु मानचित्रों पर, उत्तरी गोलार्ध के उप–दाब कम दबाव वाले बेल्टों को वायुमंडलीय गतिविधि के दो केंद्रों में बांटा जाता है – आइसलैंडिक लो और एलेयूटियन डिप्रेशन।
- दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी बेल्टें अंटार्कटिका की परिधि को घेरती हैं और अलग–अलग नहीं हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग

- IMD भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।
- यह मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम की भविष्यवाणी और भूकंपीय विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है।
- IMD का मुख्यालय दिल्ली में है और यह भारत और अंटार्कटिका के सैकड़ों अवलोकन स्टेशनों का संचालन करता है।
- आईएमडी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए पूर्वानुमान, नामकरण और वितरण की जिम्मेदारी है, जिसमें मलक्का जलडमरू, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और फारस की खाड़ी शामिल हैं।

डाक्टर ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

समाचार –

- भारत ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी।

अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम –

- डॉ. कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था।
- उनका जन्म और परवरिश रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुई और उन्होंने भौतिकी और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया।
- वे एक भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11 वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक के रूप में चार दशक बिताए, मुख्य रूप से DRDO और ISRO में और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में गहन रूप से शामिल थे।
- उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी के विकास पर अपने काम के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है।

- उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण–2 परमाणु परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई, जो 1974 में भारत द्वारा मूल परमाणु परीक्षण के बाद पहला था।
- कलाम को 2002 में भारत के 11 वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और व्यापक रूप से उन्हें 'जनवादी राष्ट्रपति' के रूप में जाना जाता था।
- वह भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान देते समय, कलाम गिर गये और 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में एक स्पष्ट हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई।

कला संस्कृति विकास योजना

समाचार –

- संस्कृति मंत्रालय कला संस्कृति विकास योजना (KSVY) को लागू कर रहा है, जिसके माध्यम से सांस्कृतिक संगठनों को कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

विवरण –

- कला संस्कृति विकास योजना (KSVY) देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत एकछत्र योजना है।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। जो विशुद्ध रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
- केएसवीवाई योजनाओं के तहत पहले से ही अनुदान प्राप्त कर चुके कलाकारों/संगठनों को योजनाओं के विभिन्न घटकों जैसे कला और शिल्प, व्याख्यान–सह–प्रदर्शन, वेबिनार, ऑनलाइन कार्यक्रम/त्यौहार आदि के माध्यम से सामाजिक मोड मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, यूट्यूब आदि पर आभासी मोड के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।
- KSVY की निम्नलिखित उप–योजनाएँ हैं जिनके माध्यम से सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की योजना।
- सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की योजना।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए योजना।

पृष्ठभूमि –

- महामारी के कारण, प्रदर्शन कलाओं और सांस्कृतिक क्षेत्र पर प्रदर्शनियों, आयोजनों और प्रदर्शनों के साथ या तो रद्द या स्थगित होने का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

बुलढाणा जल संरक्षण पैटर्न –

समाचार –

- महाराष्ट्र के 'जल संरक्षण के बुलढाना पैटर्न' ने राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है और नीति अयोग इसके आधार पर जल बातचीत पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है।

विवरण –

- राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और जल संरक्षण का समन्वय पहली बार बुलढाणा जिले में जल निकायों, नालों और नदियों से मिट्टी का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।
- इसके परिणामस्वरूप बुलडाना जिले में जल–निकायों में जल भंडारण की क्षमता में वृद्धि हुई और इसे 'बुलढाना पैटर्न' के रूप में जाना जाने लगा।
- महाराष्ट्र में इस गतिविधि के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में 225 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी का उपयोग किया गया और इसके परिणामस्वरूप चौड़ीकरण/गहरीकरण के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को बिना किसी लागत के 22,500 हजार घन मीटर (टीएमसी) जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई।

तमस्वदा पैटर्न –

- नागपुर और वर्धा जिले में ली गई जल संरक्षण परियोजना का तमस्वाड़ा पैटर्न 'जिसमें पूर्वी विदर्भ के इन दो जिलों में स्थित प्राकृतिक जल निकायों की जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन, संरक्षण और भूजल पुनर्भरण कार्य किए गए थे।
- यह पैटर्न 60 गांवों नागपुर और वर्धा जिले में लागू किया जा रहा था, जबकि 40 गांवों में काम पूरा हो चुका था।

कुल –

- कुल डायवर्सन चैनल हैं जो एक ग्लेशियर से गांव तक पानी ले जाते हैं।
- वे हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी और जम्मू में भी लोगों की जीवन रेखा हैं।
- कुल की शुरुआत ग्लेशियर से होती है।
- कुल उस गाँव की ओर जाता है जहाँ पानी एक वृत्ताकार पानी की टंकी में जमा होता है।
- गांव की जरूरत के मुताबिक यहां से पानी निकाला जाता है।

बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली –

- जल संरक्षण और धारा और वसंत के पानी के उपयोग की यह प्रणाली बांस के पाइप का उपयोग करके की जाती है।
- मेघालय में अभ्यास किया जाता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य वृक्षों की सिंचाई करना है।
- 200 साल पुरानी इस प्रणाली में डाउनहिल खेतों की सिंचाई के लिए हर मिनट बांस के पाइप सिस्टम में 18–20 लीटर पानी डालना शामिल है।

जोहड़ –

- जोहड़, एक अर्धचंद्राकार आकार का छोटा सा चेक डैम, जो पृथ्वी और चट्टान से निर्मित होता है, जो वर्षा के पानी को रोकने और संरक्षित करने के लिए, इस प्रकार पुनर्निमित किया गया।
- यह परकोलेशन में सुधार करने में मदद करता है और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाता है।
- सतह के नीचे एक्वीफर को रिचार्ज करके, जोहड ने क्षेत्र में कृषि को बढ़ाने में मदद की है।
- जोहड़ के उपयोग ने अरवरी नदी के प्रवाह को बढ़ाने में भी मदद की है, जिससे यह अब एक बारहमासी नदी बन गई है। यह पहले मानसून के बाद सूख जाती थी।

ज़ाबो -

- ज़ाबो का अर्थ होता है पानी को प्राप्त करना। स्थानीय रूप से रूजा प्रणाली के रूप में जाना जाता है, यह प्रणाली पशु देखभाल, वन और कृषि के साथ जल संरक्षण का एक अनूठा संयोजन है।

- ज्यादातर नागालैंड में प्रचलित, ज़ाबो का उपयोग पेयजल आपूर्ति की कमी से निपटने के लिए किया जाता है।
- मानसून के दौरान, पहाड़ी इलाकों पर गिरने वाले वर्षा जल को संरचनाओं की तरह तालाब में इकट्ठा किया जाता है, जिसे पहाड़ियों पर उकेरा जाता है। इसके बाद पानी को मवेशियों के गड्ढे के नीचे से गुजारा जाता है, जहां से पानी धान के खेतों में जाता है।

एरी –

- भारत में सबसे पुरानी जल संरक्षण प्रणालियों में से एक, तमिलनाडु के एरी (टैंक) को अभी भी राज्य के आसपास व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- परंपरागत जल संचयन प्रणाली एरी कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- उनके पास कई फायदे हैं जैसे मिट्टी का कटाव रोकना, भूजल पुनर्भरण और बाढ़ नियंत्रण।
- एरी को या तो चैनलों के माध्यम से भरा जा सकता है जो नदी के पानी को मोड़ते हैं, या ये बारिश से भर जाती है। अधिक या कम आपूर्ति के मामले में पानी को संतुलित करने के लिए उन्हें आमतौर पर आपस में जोड़ा जाता है।

जिंग –

- यह लद्दाख में पाये जाने वाले छोटे टैंक हैं जो पिघलने वाले ग्लेशियर के पानी को इकट्ठा करते हैं। मार्गदर्शक चैनलों का एक नेटवर्क ग्लेशियर से टैंक में पानी लाता है।

Kuhls –

- वे सतह के पानी के चैनल हैं जो हिमाचल प्रदेश के इलाकों में पाए जाते हैं। चैनल नदियों और नालों से ग्लेशियल पानी को खेतों में ले जाते हैं।

खडीन –

- खडीन एक जल संरक्षण प्रणाली है जिसे कृषि के उद्देश्य से सतह अपवाह जल को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह एक ढलान के चारों ओर बने तटबंध को घेरता है, जो वर्षा जल को एक कृषि क्षेत्र में एकत्रित करता है।
- यह मिट्टी को नम करने में मदद करता है और टॉपसाइल के नुकसान को रोकने में मदद करता है।
- इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतिरिक्त पानी की निकासी बंद है, स्पिलवेज प्रदान किया जाता है।
- जल संरक्षण की यह प्रणाली राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्रों में आम है। कुआं आमतौर पर खडीन से थोड़ा आगे बनाया जाता है।

हींग की खेती

समाचार –

- इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिर्सोसेस पालमपुर (आईआईएचबीटी) के वैज्ञानिक, भारतीय हिमालय में हींग उगाने के मिशन पर हैं।
- हिमाचल प्रदेश के कुँवरिंग गाँव में लाहौल घाटी में हाल ही में पहला पौधारोपण किया गया है।
- भारत ईरान, उजबेकिस्तान और अफगानिस्तान से हींग, या हींग, तीखे स्वाद वाली जड़ी–बूटी का आयात करता है।

हींग क्या है? –

- फेरूला हींग, वेजाइलेरी परिवार का एक जड़ी बूटी वाला पौधा है।
- यह एक बारहमासी पौधा है जिसका ओलेओ गम राल इसकी मोटी जड़ों और प्रकंद से निकाला जाता है।
- संयंत्र अपने पोषक तत्वों को अपनी गहरी मांसल जड़ों के अंदर संग्रहीत करता है।

आमतौर पर इसकी खेती कहां की जाती है? –

- हींग का मुख्य वैश्विक आपूर्तिकर्ता ईरान और अफगानिस्तान है।
- यह सूखे और ठंडे रेगिस्तान की स्थितियों में पनपता है।
- यह भारत में बहुत लोकप्रिय है।
- कुछ यूरोपीय देश अपने औषधीय गुणों के लिए भी इसका उपयोग करते हैं।

भारत कैसे हिंग की खेती में प्रवेश कर रहा है?

- भारत में हींग की खेती नहीं की जाती है।
- भारत हर साल ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से 600 करोड़ रुपये की लगभग 1200 टन कच्ची हींग का आयात करता है।
- 1963 और 1989 के बीच, भारत ने एक बार हींग के बीज खरीदने का प्रयास किया। हालाँकि, इसके कोई प्रकाशित परिणाम नहीं हैं।
- 2017 में, CSIR - Institute of Himalayan Bioresource Technology ने ICAR – National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR) के साथ मिलकर भारतीय हिमालय में हिंग की खेती की प्रायोगिक परियोजना पर विचार किया।
- शोध के लिए, ईरान से हींग के बीज आयात किए गए।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से सभी विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, IHBT द्वारा आयात परमिट – 409/2018 और EC 968466 – 70 के साथ आयात परमिट –409 (EC 966538) के छह परिग्रहणों को आयात परमिट –409 / 2018 के साथ शुरू किया गया था।
- CSIR–IHBT में, बीज का अध्ययन किया गया, और फिर यह देखने के लिए परीक्षण किया गया था कि क्या वे एक नियंत्रित प्रयोगशाला सेट–अप के तहत अंकुरित होंगे।
- जून 2020 में, CSIR संस्थान ने हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। संयुक्त रूप से, इस परियोजना को राज्य में अगले पांच वर्षों में विकसित किया जाएगा।

भारत में हींग की खेती के लिए कौन से क्षेत्र अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं?

- IHBT के सेंटर फॉर हाई अल्टीट्यूड बायोलॉजी में उगाया गया पहला हींग का पौधा, 15 अक्टूबर को लाहौल घाटी के क्वारिंग गांव में लगाया गया था।
- भारत में कुछ खास किस्मों की खेती के लिए आवश्यक भू–जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध हैं।
- कृषि मंत्रालय ने घाटी में चार स्थानों की पहचान की है और क्षेत्र के सात किसानों को हेग बीज वितरित किए हैं।
- हींग सबसे अच्छी तरह से सूखी और ठंडी स्थितियों में बढ़ती है।
- संयंत्र 35 और 40 डिग्री के बीच अधिकतम तापमान का सामना कर सकता है, जबकि सर्दियों के दौरान, यह शून्य से 4 डिग्री तक के तापमान में जीवित रह सकता है।

- अत्यधिक मौसम के दौरान, पौधे निष्क्रिय हो सकते है।
- रेतीली मिट्टी वाले क्षेत्र, बहुत कम नमी और 200 मिमी से अधिक की वार्षिक वर्षा को भारत में हींग की खेती के लिए अनुकूल माना जाता है।

हींग के क्या फायदे हैं?

- हींग के औषधीय गुणों की एक श्रृंखला, जिसमें पाचन, ऐंठन और पेट की बीमारियों, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लिए राहत शामिल है।
- जड़ी बूटी का उपयोग आमतौर पर दर्द और अत्यधिक रक्तस्राव में मदद करने के लिए किया जाता है।
- पेट फूलने पर इस जड़ी बूटी को नई माताओं को खिलाया जाता है।
- इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT 1983 में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद की एक घटक अनुसंधान प्रयोगशाला है।
- हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में स्थित यह संस्थान हिमालयी जैव–संसाधनों और आधुनिक जीव विज्ञान के विभिन्न उन्नत अनुसंधान पहलुओं में लगा हुआ है।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP)

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) के चरण II और चरण III को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 19 राज्यों में 736 बांधों को मजबूत करना है, जिसमें केंद्र के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) शामिल हैं।

लक्ष्य –

- परियोजना का उद्देश्य सिस्टम के व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संस्थागत मजबूती के साथ देश भर में चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना है।

उद्देश्य –

- चयनित मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए और एक स्थायी तरीके से जुड़ा हुआ है।
- केंद्रीय राज्यों में भाग लेने वाले राज्यों के साथ–साथ बांध सुरक्षा संस्थागत स्थापना को मजबूत करने के लिए।
- डैम के स्थायी संचालन और रखरखाव के लिए आकस्मिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए कुछ चयनित बांधों पर वैकल्पिक आकस्मिक साधनों का पता लगाने के लिए।
- उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, डीआरआईपी में निम्नलिखित घटक होते हैं –
  – बांधों और संबंधित आश्रयों का पुनर्वास और सुधार
  – प्रतिभागी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों में बांध सुरक्षा संस्थागत मजबूती
  – डैम के स्थायी संचालन और रखरखाव के लिए आकस्मिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए कुछ चयनित बांधों में वैकल्पिक आकस्मिक साधनों की खोज।

विवरण –

- पंजाब में 12 बांध, राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित, परियोजना के लिए चिन्हित कुल बांधों में से हैं।
- परियोजना में शामिल बांध केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रबंधित किए गए हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रबंधित किए गए हैं।
- शामिल किए गए बांधों की पहचान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई थी।
- विश्व बैंक (WB) और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) परियोजना के लिए सहायता प्रदान करेंगे।
- यह दो चरणों में 10 साल की अवधि में लागू किया जाएगा, प्रत्येक छह साल की अवधि के दो साल के साथ अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक ओवरलैपिंग होगा।

ड्रिप –

- इस परियोजना का मूल उद्देश्य भारत में 223 बांधों में सुधार करना है। बाद में, परियोजना का लक्ष्य 736 बांधों का पुनर्वास करना है।
- यह परियोजना केंद्रीय जल आयोग के केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- भारत बड़े बाँधों की संख्या में चीन और अमरीका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में 5,264 बड़े बांध हैं और 437 निर्माणाधीन हैं।

बूंदी – एक भूली हुई राजपूत राजधानी की वास्तुकला विरासत

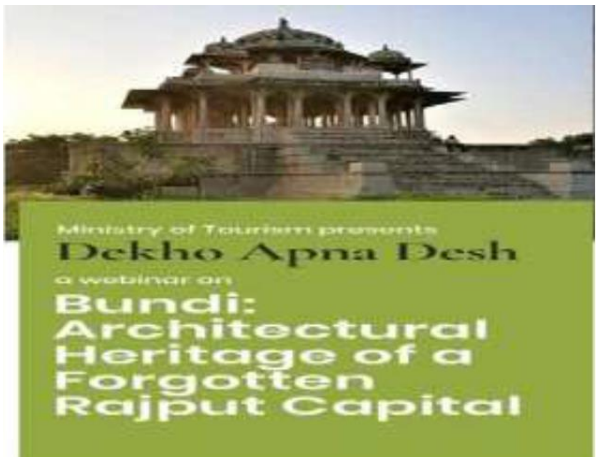

समाचार –

- पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला जिसका शीर्षक है 'बूंदी – एक राजपूत राजधानी की वास्तुकला की विरासत' जो कि बूंदी, राजस्थान पर केंद्रित है।
- राजस्थान, ऐसी ही एक जगह है।
- सेव बूंदी को सौतेले शहर के रूप में भी जाना जाता है, नीला शहर और चट्टी काशी के रूप में भी।
- प्राचीन समय में, बूंदी के आसपास का क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभिन्न स्थानीय जनजातियों द्वारा बसा हुआ था, जिनमें से परिहार जनजाति, मीणा प्रमुख थे।
- बाद में इस क्षेत्र को राव देव द्वारा शासित किया गया, जिसने 1242 में जैता मीणा से बूंदी पर अधिकार कर लिया, आसपास के क्षेत्र का नाम बदलकर हरवती या हरोटी रख दिया।

इतिहास –

- दो दशकों तक राव देव द्वारा शासित, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया के जागीरदार थे और 1569 तक राव के पद पर शासन करते थे, जब सम्राट अकबर ने रणथंभौर किले के आत्मसमर्पण के बाद राव सुरजन सिंह को राव राजा का खिताब दिया था।

- 1632 में, राव राजा चत्तर साल शासक बने, वह बूंदी के सबसे बहादुर, राजसी और न्यायप्रिय राजा थे।
- उन्होंने केशोरायतन और केशरी महल में बूंदी में केशवराव का मंदिर बनवाया।
- वह अपने दादा राव रतन सिंह के बाद बूंदी के राजा बने, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ का निधन हो गया था जबकि रतन सिंह अभी भी शासन कर रहे थे।
- राव चतरा साल 1658 में अपने सबसे छोटे बेटे भरत सिंह राव भाऊ सिंह के साथ सामगढ़ की लड़ाई में अपने हाड़ा राजपूत सैनिकों के प्रमुख के रूप में बहादुरी से लड़ते हुए मर गए, छत्तर साल के सबसे बड़े बेटे भरत सिंह बूंदी के सिंहासन के लिए अपने पिता के उत्तराधिकारी बने।

मुगल काल के बाद –

- 1804 में राव राजा बिशन सिंह ने होलकर से पहले अपने विनाशकारी पीछे हटने में कर्नल मोनसन को बहुमूल्य सहायता दी, जिसका बदला लेने के लिए मराठा साम्राज्य और पिंडारियों ने लगातार अपने राज्य को तबाह किया और 1817 तक राज्य को श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर किया।
- नतीजतन, बिशन सिंह ने 10 फरवरी 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक सहायक गठबंधन किया, जिसने उन्हें इसके संरक्षण में लाया।
- वह बूंदी के बाहरी इलाके में सुख निवास के सुख महल के निर्माण के लिए जिम्मेदार था।
- महाराव राजा राम सिंह एक बड़े शासक के रूप में विकसित हुए जिन्होंने आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की और संस्कृत के शिक्षण के लिए स्कूलों की स्थापना की।
- 68 वर्षों तक सिंहासन पर, उन्हें राजपूत सज्जन का एक भव्य नमूना और 'रूढ़िवादी राजपुताना में सबसे अधिक रूढ़िवादी राजकुमार' के रूप में वर्णित किया गया था।
- 1947 में भारत के विभाजन के समय, अंग्रेजों ने रियासतों पर अपनी संप्रभुता का परित्याग कर दिया, जो यह तय करने के लिए छोड़ दिए गए थे कि उन्हें स्वतंत्र रहना है या भारत तथा पाकिस्तान में से किसमें शामिल होना है।
- बूंदी राज्य के शासक ने भारत में प्रवेश करने का फैसला किया, जो बाद में भारत का संघ बन गया। इससे बूंदी के आंतरिक मामले दिल्ली के नियंत्रण में आ गए।
- बूंदी के अंतिम शासक ने 7 अप्रैल 1949 को भारतीय संघ में प्रवेश किया।

महत्वपूर्ण और अनोखे पहलू –

- होदा राजपूत भयंकर थे, निडर योद्धा अक्सर अपने शासनकाल की ओर से लड़ते हुए कम उम्र में अपना जीवन व्यतीत करते थे।
- इसके कारण कई बार होदा बालक बूंदी के सिंहासन पर चढ़े।
- इसलिए, शाही रानी, दीवान और ढाई मा की भूमिका बूंदी के शाही प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण हो गई।
- इस प्रकार बूंदी शहर तारागढ़ पहाड़ी से बाहर की ओर बढ़ा।
- गढ़ महल फोकस बन गया और नीचे घाटी से बूंदी के क्षितिज पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिखाई दिया।
- बूंदी के अधिकांश घरों में झरोखे हैं जिनमें ऊपरी मंजिल पर कुछ स्क्रीन हैं जो सड़क पर खुलते हैं, प्रकाश और वेंटिलेशन प्रदान करते हैं।
- आंदोलन और कनेक्टिविटी को सक्षम करने के अलावा, इन सड़कों ने दीवार वाले शहर के निपटान के कपड़े के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- बूंदी में दरवाजों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है – तारागढ़ के प्रवेश द्वार, सबसे पुराना दरवाजा, चारदीवारी शहर के चार द्वार, बाहरी शहर की दीवार के द्वार, चारदीवारी वाले शहर की प्रमुख सड़कों पर दरवेश, छोटे दरवाजे

पानी की वास्तुकला –

- मध्ययुगीन भारतीय शहर का सबसे अच्छा उदाहरण जल संचयन विधियों को निपटान स्तर पर अपनाया गया और साथ ही पानी की वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण हैं।
- चारदीवारी के बाहर बौरिस और कुंडों का स्थान भी सामाजिक विचारों से प्रभावित था क्योंकि बौरिस और कुंड की दीवार के भीतर स्थित कुंड नियंत्रित थे।
- बूंदी को हाडा राजधानी के भीतर और आसपास सौ से अधिक मंदिरों की उपस्थिति के कारण चट्टी काशी के रूप में भी जाना जाता था।
- मुगल साम्राज्य का उपनिवेश राज्य होने के बावजूद, हाड़ा शासकों ने न केवल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखा, बल्कि हाडा आधिपत्य के चार शताब्दियों के दौरान बनाए गए बड़ी संख्या में मंदिरों में इसे प्रकट करते हुए उनके अधूरा जुड़ाव को बढ़ा दिया।
- बूंदी के विकास के शुरुआती चरण में निर्मित मंदिरों में शास्त्रीय नगरी शैली थी, जबकि बाद के चरणों में शास्त्रीय नगरी शैली के साथ पारंपरिक हवेली के स्थापत्य रूप के समामेलन से मंदिर की नई अवधारणाएँ सामने आईं।
- जैन मंदिरों का निर्माण तीसरे प्रकार के मंदिर के प्रकार से हुआ, जो अंतर्मुखी रूप में निर्मित था, प्रवेश द्वार पर नागिन टोरण द्वार जैसे विशिष्ट जैन मंदिर की विशेषताओं को एकीकृत करता है, बड़े घनाकार अपारदर्शी द्रव्यमान और मध्य आंगन और नगाड़ा शैली इसके गर्भगृह पर दिखाई देती है।
- एक चौथा मंदिर ऊंचे उठे हुए मंदिर के रूप में उभरा। बूंदी में मंदिरों की एक विशिष्ट विशेषता उनके पैमाने में स्मारक का अभाव है।
- मंदिरों में विविधता और इस सृष्टि में स्वतंत्रता का प्रयोग शास्त्रीय, स्थापित मानदंडों से हटकर स्वतंत्रता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी का सूचक है।
- बूंदी की वास्तुकला विरासत को छह प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है –
  1) गढ़ (किला) तारागढ़
  2) गढ़ महल (रॉयल पैलेस) – भज महल, चतरा महल, उम्मेद महल
  3) बाउरी – खोज दरवाजा की बावरी, भलवाड़ी बावरी
  4) कुंड (स्टेप्ड टैंक) – धाभाई जी का कुंड, नगर कुंड और सागर कुंड, रानी कुंड

सिंधु सुचर जोन (आई एस ज़ेड)

समाचार –

- लद्दाख क्षेत्र में हिमालय या सिंधु सुचर जोन (ISZ) का सिवनी जोन जहाँ भारतीय और एशियाई प्लेट्स सम्मिलित हैं, टेक्टोनिक रूप से सक्रिय पाए गए हैं, जैसा कि वर्तमान समझ के विरुद्ध है कि यह एक लॉक जोन है।

- भूकंप के अध्ययन, भविष्यवाणी, पर्वतीय श्रृंखलाओं की भूकंपीय संरचना को समझने के साथ ही इसके विकास के बारे में इसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं।

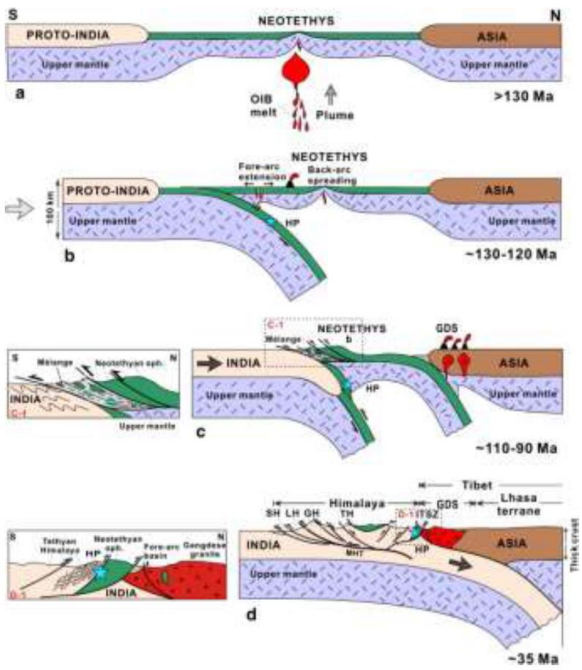

विवरण –

- हिमालय का सिंधु सुचर क्षेत्र जिसे परंपरागत रूप से अक्रिय माना जाता था, विवर्तनिक रूप से सक्रिय है।
- वैज्ञानिकों ने लद्दाख के सुदूर क्षेत्रों की मैपिंग की, जो हिमालय का सबसे भीतरी भाग है।
- भूवैज्ञानिकों ने देखा कि तलछटी बेड झुके हुए और टूटे हुए हैं, नदियों उठे हुए पठारों से जुड़ी है, और बेडरोल भंगुर विरूपण को दर्शाता है जो बहुत उथली गहराई पर होता है।
- इन विकृत भूवैज्ञानिक विशेषताओं को तब देहरादून में प्रयोगशाला में वैकल्पिक रूप से उत्तेजित ल्युमिनीसेंस (OSL) नामक तकनीक का उपयोग करके दिनांकित किया गया था। (भूवैज्ञानिक तलछट के ल्युमिनीसेंस के डेटिंग की विधि) और भूकंपीयता और मूल्यह्रास दर के आंकड़ों की समीक्षा की गई थी।
- फील्ड और लैब डेटा के संयोजन ने सुझाव दिया कि सिंधु सुचर जोन (ISZ) का क्षेत्र पिछले 78000–58000 वर्षों से नव–विवर्तनिक रूप से सक्रिय है और 2010 में उप्शी गांव के पास कम परिमाण 4.0 के भूकंप के कारण थ्रस्ट रप्चर था।
- हिमालय को मुख्य मध्य थ्रस्ट (MCT), मेन बाउंड्री थ्रस्ट (MBT), और मेन फ्रंटल थ्रस्ट (MFT) जैसे उत्तर सूई थ्रस्ट से बना माना जाता था।
- स्थापित मॉडलों के अनुसार, एमएफटी को छोड़कर बाकि सभी थ्रस्ट लॉक हैं।

परम्परा श्रृंखला 2020 – संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व

समाचार –

- उपराष्ट्रपति ने 'परम्परा श्रृंखला 2020 – संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय उत्सव' का आभासी उत्सव शुरू किया।
- यह त्यौहार ऑडियो–विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस के साथ मेल खाने के लिए आयोजित किया गया है।
- 'परम्परा' का अर्थ है 'सांस्कृतिक खजाने का एक पीढ़ी से दुसरी पीढ़ी में प्रसारण।'

विवरण –

- परम्परा सीरीज 2020 – नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस 'संयुक्त राष्ट्र की साझेदारी में नाट्य तरंगिनी द्वारा आयोजित किया जाता है।
- नाट्य तरंगिणी पिछले 23 वर्षों से लगातार 'परम्परा श्रृंखला' का आयोजन कर रही है।
- संगीत और नृत्य का त्योहार कायाकल्प और स्फूर्तिदायक बनाकर जीवन को अधिक पूर्ण करता है।
- वे जीवन में सामंजस्य लाते हैं और निराशा को दूर करके आंतरिक भावना का पोषण करते हैं।
- भारत के नृत्य, संगीत और नाटक के विविध कला रूप हमारे सामान्य सभ्यता दर्शन और सद्भाव, एकता और जैसे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- भक्ति, आध्यात्मिकता पर एक अलग ध्यान केंद्रित है और नौं रासों' के भावों का एक पूरा सरगम है जो मानव अस्तित्व का निर्माण करता है।

सामान्य अध्ययन– II
शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध

बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला

समाचार –

- एक विशेष अदालत ने 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाया।
- अपने फैसले में, न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था और कार सेवकों के मध्य उपस्थित 'अनियंत्रित तत्व (आरजक तत्त्व)' की करतूत थी।
- विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को कानूनी विभाग से परामर्श के बाद बरी कर दिया।

बाबरी मस्जिद का विध्वंस –

- बाबरी मस्जिद (अयोध्या, उत्तर प्रदेश के शहर में 16 वीं सदी की बाबरी मस्जिद) को 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और संबद्ध संगठनों के कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह द्वारा अवैध रूप से चलाया गया था।
- हिंदू परंपरा में, अयोध्या शहर राम की जन्मभूमि है। 16 वीं शताब्दी में, एक मुगल सेनापति, मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण किया था, जिसे कुछ हिंदुओं द्वारा राम जन्मभूमि के रूप में पहचाने जाने वाले स्थल पर बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता था।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहता है कि मस्जिद का निर्माण उस भूमि पर किया गया था जहाँ पहले एक गैर–इस्लामिक ढांचा मौजूद था।

एक समयरेखा –

- 1528 – मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण।
- 1885 – महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद की जिला अदालत में याचिका दायर की और विवादित ढांचे के बाहर चंदवा बनाने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

- **1949** – राम लला की मूर्तियों को विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद के नीचे रखा गया।
- **1950** – गोपाल सिमला विशारद ने राम लला की मूर्तियों की पूजा करने के अधिकार के लिए फैजाबाद जिला अदालत में मुकदमा दायर किया।
- परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा को जारी रखने और मूर्तियों को रखने के लिए न्यायालय का रूख किया।
- **1959** – निर्मोही अखाड़ा ने इस स्थल पर कब्जे की मांग की।
- **1961** – यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्थल पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया।
- **फरवरी 1986** – स्थानीय अदालत ने सरकार को हिंदू उपासकों को स्थल खोलने का आदेश दिया।
- **अगस्त 1989** – इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित ढांचे के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया।
- **6 दिसंबर, 1992** – बाबरी मस्जिद ध्वस्त।
- **दिसम्बर 1992** – मामले में दो प्राथमिकी दर्ज। मस्जिद के विध्वंस के लिए अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ एक। विध्वंस से पहले कथित रूप से सांप्रदायिक भाषण देने के लिए अन्य नेताओं में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, एम। एम। जोशी और अन्य नाम शामिल हैं।
- **अक्टूबर 1993** – सीबीआई ने आडवाणी और अन्य पर साजिश का आरोप लगाते हुए समग्र आरोप पत्र दायर किया।
- **मई 2001** – सीबीआई की विशेष अदालत ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे और अन्य के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी।
- **नवंबर 2004** – सीबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के सामने चुनौती दी कि तकनीकी आधार पर भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्यवाही को रोका जाए। कोर्ट ने नोटिस जारी किए।
- **मई 2010** – उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की। कहते हैं कि सीबीआई की संशोधन याचिका में कोई योग्यता नहीं है।
- **सितम्बर 2010** – 2:1 बहुमत में, HC ने सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच विवादित क्षेत्र के विभाजन का नियम बनाया।
- **मई 2011** – उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद पर उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखा।
- **फरवरी 2011** – केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने मस्जिद विध्वंस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
- **मार्च 2017** – उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया कि यह बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोप को पुनर्जीवित करने पर विचार कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए नए सिरे से प्रयास करने का सुझाव दिया।
- उच्चतम न्यायालय मामले में मुकदमे की समयबद्ध पूर्णता और सीबीआई की याचिका पर आदेश के पक्ष में है।
- उच्चतम न्यायालय ने आडवाणी, जोशी और उमा भारती सहित नेताओं के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के आरोप को बहाल किया और वीआईपी और कारसेवकों के खिलाफ लंबित मामलों में परीक्षण किया।
- **नवंबर 2019** – उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में पूरी तरह से विवादित भूमि को राम लल्ला को दे दिया, मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को वैकल्पिक पांच एकड़ भूखंड आवंटित करने का निर्देश दिया।
- **अगस्त 2020** – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 'भूमि पूजन' किया, राम मंदिर का निर्माण शुरू किया।
- सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मुकदमे की सुनवाई की समय सीमा एक महीने बढ़ा दी गई है।
- **30 सितंबर** – विशेष न्यायाधीश एस. यादव ने मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाया, सभी आरोपी बरी हो गए।

भारत की वार्षिक अपराध रिपोर्ट

समाचार –

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने अपनी 2019 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट जारी की है।
- रिपोर्ट ने संकेत दिया कि भारत में महिलाएं किस तरह से असुरक्षित होती जा रही हैं।

मुख्य निष्कर्ष –

- महिलाओं के खिलाफ अपराध 2018 से 2019 तक 7.3 फीसदी बढ़े है।
- अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध भी 2018 से 2019 तक 7.3 प्रतिशत हो गए।
- निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश ने इन श्रेणियों में (महिलाओं के खिलाफ और SC के खिलाफ) दोनों मामलों में सबसे अधिक मामले दर्ज हुए।
- असम में महिलाओं के प्रति अपराधों की उच्चतम दर (प्रति लाख जनसंख्या) पर रिपोर्ट की गई, जबकि राजस्थान में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों की उच्चतम दर थी।
- 2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 2018 में 7.3% की वृद्धि हुई।
- आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के अधिकांश मामलों को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के तहत दर्ज किया गया था (30.9 %), उसके बाद महिलाओं पर उनकी शीलता को अपमानित करने के इरादे से किए गए हमले (21.8 %), महिलाओं का अपहरण और अपहरण (17. 9%) और बलात्कार' (7.9%)।
- 2018 में 58.8 की तुलना में 2019 में प्रति लाख महिलाओं की जनसंख्या का अपराध दर 62.4 है।
- यूपी ने महिलाओं (59,853) के खिलाफ सबसे अधिक अपराधों की सूचना दी, देश भर में इस तरह के मामलों का प्रतिशत 14.7 है।
- इसके बाद राजस्थान (41,550 मामले, 10.2 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (37,144 मामले, 9.2 प्रतिशत) थे।
- असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर 177. 8 (प्रति लाख जनसंख्या) दर्ज की गई, इसके बाद राजस्थान (110.4) और हरियाणा (108.5) का स्थान रहा।
- राजस्थान में 5,997 मामलों के साथ सबसे अधिक बलात्कार हुए, इसके बाद यूपी (3,065) और मध्य प्रदेश (2,485) दर्ज किए गए।
- बलात्कार के मामलों की दर के मामले में, राजस्थान 15.9 (प्रति लाख जनसंख्या) पर सबसे अधिक था, उसके बाद केरल (11.1) और हरियाणा (10.9) था।

- यूपी में 7,444 मामलों के साथ पोस्को अधिनियम के तहत बालिकाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध हुए, इसके बाद महाराष्ट्र (6,402) और एमपी (6,053) थे।
- इन अपराधों की उच्चतम दर सिक्किम (27.1 प्रति लाख जनसंख्या), एमपी (15.1), और हरियाणा (14.6) में थी।
- यूपी में 2.2 (प्रति लाख जनसंख्या) की दर से दहेज के मामलों (2,410) की संख्या सबसे ज्यादा थी, उसके बाद बिहार (1,120) का स्थान था।
- रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में 150 एसिड हमले हुए, जिनमें से 42 यूपी में और 36 पश्चिम बंगाल में हुए।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 45,935 मामले अनुसूचित जाति (एससी) के खिलाफ अपराध के रूप में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2018 (42,793 मामलों) में 7.3% की वृद्धि हुई है।
- पंजीकृत अपराध दर में 2018 में 21.2 (प्रति लाख जनसंख्या) से 2019 में 22.8 की वृद्धि हुई है।
- क्राइम हेड–वार मामलों से पता चला कि 28.9% (13,273 मामलों) के साथ सरल चोट ने 2019 के दौरान अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों/अत्याचार के मामलों का सबसे बड़ा हिस्सा बनाया।
- इसके बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 9.0% (4,129 मामले) के साथ मामले थे, और 7.6% (3,486) के साथ बलात्कार के तहत मामले मामले)।
- यूपी ने अनुसूचित जातियों के खिलाफ सबसे अधिक मामलों की सूचना दी – 11,829 मामले, देश भर में 25.8 प्रतिशत मामलों का लेखा–जोखा।
- इसके बाद राजस्थान (6,794 मामलेय 14.8 प्रतिशत) और बिहार (6,544य 14.2 प्रतिशत) का स्थान रहा।
- हालांकि, ऐसे मामलों की दर राजस्थान में सबसे अधिक 55.6 (प्रति लाख जनसंख्या) थी, उसके बाद एमपी (46.7) और बिहार (39.5) थी।
- राजस्थान में भी दलित महिलाओं (554) के खिलाफ सबसे ज्यादा रेप हुए, उसके बाद यूपी (537) और एमपी (510) का नंबर आता है।
- दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की दर केरल में सबसे अधिक 4.6 (प्रति लाख जनसंख्या) थी, उसके बाद एमपी (4.5) और राजस्थान (4.5) थी।

संज्ञेय अपराध –

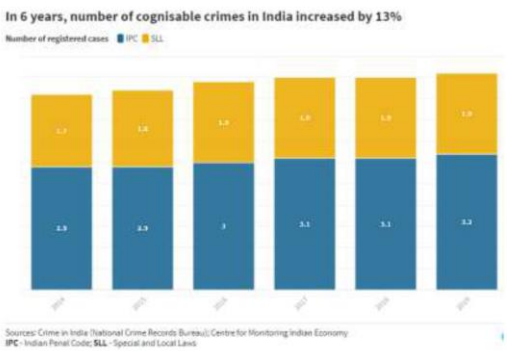

- भारत ने 2018 और 2019 के बीच संज्ञेय अपराधों की संख्या में 1.6% की वृद्धि दर्ज की।
- इन संज्ञेय अपराधों में भारतीय दंड संहिता (IPC) के साथ–साथ विभिन्न विशेष और स्थानीय कानूनों (SLL) के अंतर्गत आने वाले मामले शामिल हैं।
- जबकि पहली श्रेणी में लगभग 3% की वृद्धि देखी गई, दूसरे के तहत मामलों की संख्या में 0.6% की कमी हुई।
- आईपीसी के तहत 2019, या लगभग 1.1 मिलियन में दर्ज लगभग हर तीसरा मामला मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में था जैसे हत्या, बलात्कार, मौत का कारण, अपहरण आदि।
- संपत्ति के खिलाफ अपराधों, जैसे चोरी और आपराधिक विश्वासघात, में लगभग 26% या 0.9 मिलियन मामले शामिल थे।

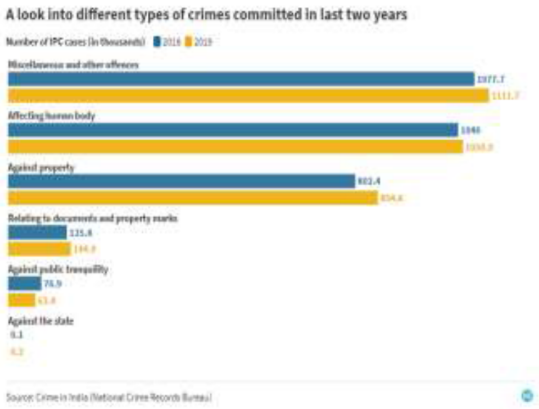

- संपत्ति के खिलाफ अपराधों में 6.5% की वृद्धि हुई – इसमें चोरी शामिल है जिसमें 8% की वृद्धि हुई और यह भारत का एकमात्र सबसे अधिक अपराध था जिसमें सभी आईपीसी अपराधों में 21% शामिल थे।
- महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित अपराधों में 2018 और 2019 के बीच अलग–अलग डिग्री की वृद्धि हुई।
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.3% की वृद्धि हुई।

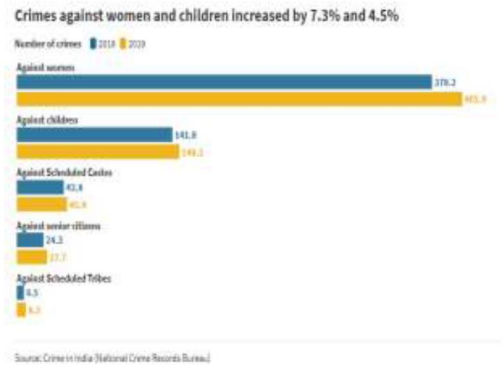

- पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता 2019 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध था, जिसमें महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों का 31% शामिल था।
- बलात्कार में महिलाओं के खिलाफ लगभग 8% अपराध शामिल थे।
- बच्चों के खिलाफ अपराध, अपहरण और अपहरण, और यौन अपराध दो सबसे अधिक अपराध थे।

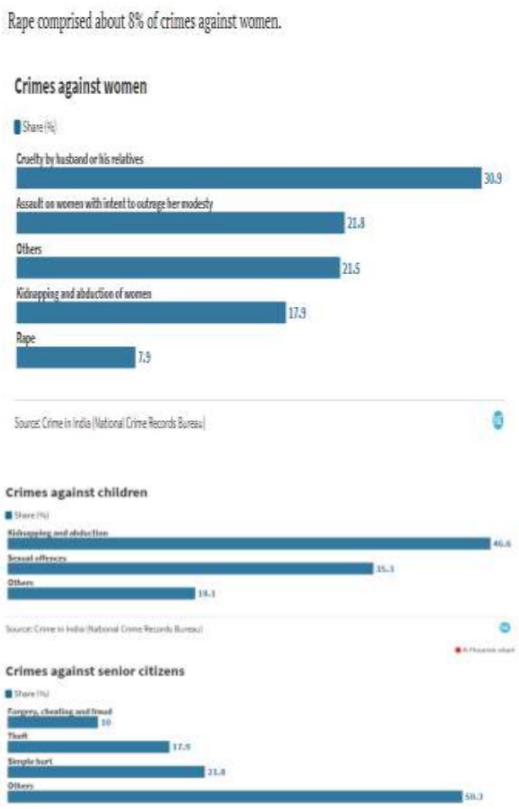

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो –

- NCRB एक भारतीय सरकारी एजेंसी है, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) और विशेष और स्थानीय कानूनों (SLL) द्वारा परिभाषित अपराध आंकड़ों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है।
- NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह गृह मंत्रालय (MHA) का हिस्सा है।
- NCRB की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों पर सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई ताकि अपराधियों को अपराधियों से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके।
- इसे समन्वय निदेशालय और पुलिस कंप्यूटर (DCPC), CBI की इंटर स्टेट क्रिमिनल्स डेटा ब्रांच और CBI के सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो को विलय करके टास्क फोर्स, 1985 और राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 1977 की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था।

एनसीआरबी का विकास –
Evolution of NCRB

1986	NCRB Created
1987	Motor Vehicle Coordination software (Lost and Found)
1990	Commencement of training for Foreign Police Officers
1991	Portrait Building System (PBS) developed (Colour PBS in 2011)
1993	7 IIF forms finalized
1995	FACTS and CCIS implementation (Windows based CCIS in 2001 & FACTS-5 in 2005)
1999	Talash software for matching of missing and dead persons
2003	Counterfeit Currency (FICN)Software released
2004	Common Integrated Police Application (CIPA)
2005	Organized Crime System software
2009	CCTNS Approval
2013	CCTNS Pilot Launch & CAS STQC certified
2014	Revised Proforma and software for Crime in India, Motor Vehicle Coordination System(MVCS) Online ve
2015	Digital India Award - Silver Medal in Open Championship category (Digitization of Crime in India since 19
2017	Digital Police Portal launched

टाईम युज़ सर्वेक्षण (TUS)

समाचार –

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला पैन इंडिया समय उपयोग सर्वेक्षण जारी किया गया था।

टाईम युज़ सर्वेक्षण क्या है?

- एक समय का उपयोग सर्वेक्षण विभिन्न कार्यों, जैसे कि भुगतान किए गए कार्य, चाइल्डकैअर, स्वयंसेवा, और सामाजिककरण को करने में बिताए गए समय की मात्रा को मापता है।
- समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) का प्राथमिक उद्देश्य भुगतान और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापना है।
- अवैतनिक देखभाल करने वाली गतिविधियों, स्वयंसेवक के काम, घर के सदस्यों की अवैतनिक घरेलू सेवा उत्पादन गतिविधियों में बिताए गए समय की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- यह सीखने, सामाजिककरण, अवकाश गतिविधियों, स्व–देखभाल गतिविधियों पर खर्च किए गए समय की जानकारी भी प्रदान करता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका 2003 से प्रतिवर्ष एक TUS कर रहा है।
- ऑस्ट्रेलिया ने 1992 में अपना पहला पूर्ण पैमाने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया, कनाडा यह 1961 से कर रहा है।
- जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इजराइल ने भी ये सर्वेक्षण किए हैं।

महत्व –

- इन सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को गरीबी, लिंग इक्विटी और मानव विकास पर नीतियों का मसौदा तैयार करने में मददगार माना जाता है।

मुख्य निष्कर्ष –

- यह जनवरी और दिसंबर 2019 के बीच किया गया एक नमूना सर्वेक्षण है।
- रिपोर्ट एक दिन में विभिन्न गतिविधियों में भारतीयों की भागीदारी दर और उन गतिविधियों में उनके द्वारा खर्च किए जाने वाले औसत समय पर डेटा प्रदान करती है।
- डेटा, इस तथ्य को इंगित करता है कि भुगतान किए गए कार्यों का बड़ा हिस्सा पुरुषों द्वारा किया जाता है, जबकि अवैतनिक कार्य बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा किया जाता है।
- भुगतान किए गए रोजगार में पुरुषों की भागीदारी दर – जिसमें अन्य आर्थिक गतिविधियों में नौकरी, खेती, मछली पालन, खनन शामिल है – महिलाओं की तुलना में 57.3 प्रतिशत है, जिनकी भागीदारी दर केवल 18.4 प्रतिशत है।
- भारतीय पुरुष पेड वर्क पर अधिक समय बिताते हैं, महिलाओं द्वारा खर्च किए गए 5 घंटे 33 मिनट की तुलना में औसतन 7 घंटे 39 मिनट खर्च करते हैं।
- घर के सदस्यों के लिए घरेलू सेवाओं की तरह अवैतनिक कार्य जिसमें खाना पकाना, सफाई करना, या अवैतनिक देखभाल करना शामिल है जैसे कि आश्रित बच्चे या वयस्क की देखभाल करना, महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है।
- प्रति दिन औसतन 4 घंटे 59 मिनट खर्च करने वाली 81.2 प्रतिशत महिलाएं अवैतनिक घरेलू सेवाओं में भाग लेती हैं।

- घरेलू सेवाओं में पुरुषों की भागीदारी दर 26.1 प्रतिशत से कम है, और इस सेवा का संचालन करने में उनका खर्च लगभग 1 घंटा 37 मिनट है।
- भारतीयों का अवैतनिक स्वयंसेवी कार्यों में भाग लेने की ओर झुकाव नहीं है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 91.4 प्रतिशत पुरुषों ने सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया, प्रत्येक दिन दो घंटे और 27 मिनट बिताए।
- महिलाओं की भागीदारी दर 91.3 प्रतिशत है, और वे भी पुरुषों की तुलना में दो घंटे और 19 मिनट कम समय बिताती हैं।
- रिपोर्ट बताती है कि केवल 2.7 प्रतिशत भारतीय पुरुष अवैतनिक स्वयंसेवकों या प्रशिक्षुओं के रूप में भाग लेते हैं, या अन्य अवैतनिक कार्यों में भाग लेते हैं।
- वे प्रति दिन 1 घंटा 42 मिनट उस गतिविधि को करने में बिताते हैं।
- स्वयंसेवकों के काम में महिलाओं की भागीदारी 2 प्रतिशत कम है, 1 घंटे 39 मिनट खर्च करते हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस)

- एनएसएस अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में लार्जस्केल नमूना सर्वेक्षण के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
- मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई), आदि पर देशव्यापी घरेलू सर्वेक्षणों के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाता है।
- एनएसएस ग्रामीण और शहरी कीमतों पर डेटा एकत्र करता है और राज्य एजेंसियों के क्षेत्र गणना और फसल आकलन सर्वेक्षणों की निगरानी के माध्यम से फसल के आंकड़ों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एनएसएस के चार विभाग हैं –

सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग (SDRD) –

- कोलकाता में स्थित यह प्रभाग, सर्वेक्षणों की तकनीकी योजना, संकल्पनाओं और परिभाषाओं के निरूपण, नमूने के डिजाइन, जांच अनुसूचियों के डिजाइन, सारणीयन योजना की रूपरेखा, विश्लेषण और सर्वेक्षण परिणामों की प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है।

फील्ड ऑपरेशन डिवीजन (FOD) –

- डिवीजन, जिसका मुख्यालय दिल्ली / फरीदाबाद है, एनएसएस द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के लिए प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह के लिए जिम्मेदार है।
- डिवीजन, कोलकाता में अपने मुख्यालय के साथ, नमूना चयन, सॉफ्टवेयर विकास, प्रसंस्करण, सत्यापन और के लिए जिम्मेदार है।
- सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों का सारणीकरण।

सर्वेक्षण समन्वय विभाग (SCD) –

- नई दिल्ली में स्थित यह प्रभाग, एनएसएस के विभिन्न प्रभागों की सभी गतिविधियों का समन्वय करता है।

डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे

समाचार –

- नीति आयोग और विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) ने हाल ही में डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे किया।
- केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं (सीएस) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के कार्यान्वयन पर विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए नीति आयोग द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया।

मुख्य निष्कर्ष –

- रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उर्वरक विभाग को 16 आर्थिक मंत्रालयों/विभागों में से दुसरा स्थान तथा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) पर 5 के पैमाने पर 4.11 स्कोर के साथ 65 मंत्रालय/विभाग में से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
- इस सर्वेक्षण में, DGQI के छह प्रमुख विषयों के तहत एक ऑनलाइन प्रश्नावली तैयार की गई – डेटा जनरेशन, आँकड़े की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी का उपयोग, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, डेटा सुरक्षा और एचआर क्षमता और केस स्टडीज।
- हर विषय के लिए 0 से 5 के बीच अंतिम DGQI स्कोर तक पहुंचने के लिए वेटेज को प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न के लिए विषयों और वेटेज में बाँटा गया था।
- सीधी–अप्रासंगिक तुलनाओं से बचने के लिए, मंत्रालयों / विभागों को 6 (छह) श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था – प्रशासनिक, सामरिक, अवसंरचना, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक।
- प्रश्नावली को तब मंत्रालयों / विभागों के साथ साझा किया गया था, जो सीएस/सीएसएस योजनाओं को लागू कर रही हैं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस) –

- वे केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से और सीधे वित्त पोषित और निष्पादित होती हैं।
- संघ सूची के विषयों के आधार पर, केंद्र द्वारा योजनाएं तैयार की जाती हैं।
- इन योजनाओं में वित्तीय संसाधनों को राज्यों में स्थानांतरित नहीं किया जाता है।

केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) –

- ये ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती हैं।
- इन योजनाओं की लागत 50:50, 70:30, 75:25 या 90:10 के अनुपात में साझा आधार पर वहन की जाती है।
- लागत अनुपात के तहत, बड़ा हिस्सा हमेशा केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।
- CSS एक प्रणाली है जिसके तहत केंद्र राज्य सरकार को योजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय –

- DEMO का गठन सितंबर 2015 में पूर्ववर्ती कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय (PEO) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) के विलय से किया गया था।
- यह नीति आयोग के तहत एक संलग्न कार्यालय है।

- इसका उद्देश्य संगठन की निगरानी और मूल्यांकन (M–E) को पूरा करना और भारत में M–E पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- संगठन कोएम एंड ई कार्यों के विकास का कार्य सौंपा गया है जिसमें शामिल है –
  – रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम के ढांचे और प्रगति की प्रभावकारिता की निगरानी करना एवं के लिए आवश्यक मध्य–पाठ्यक्रम सुधार सहित नवीन सुधारों में मदद करने के लिए पहल करना।
  – जरूरत के सामानों को पहचान कर कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन को सक्रिय रूप से मॉनिटर करना और उनका मूल्यांकन करना
  – सफलता की संभावना और वितरण के दायरे को मजबूत करने के लिए संसाधन जुटाना।

DMEO के उद्देश्य हैं –

- डेटा–संचालित नीति बनाने को सक्षम करने के लिए, सरकार के सभी स्तरों में नियमित आत्म–मूल्यांकन से गहन सीखने की संस्कृति को सक्षम करना।
- प्रदर्शन मेट्रिक्स और व्यापक कार्यक्रम मूल्यांकन के कठोर ट्रैकिंग को संस्थागत बनाना।
- पूरे पारिस्थितिक तंत्र को मुख्यधारा के कठोर परिणाम निगरानी और मूल्यांकन के लिए मजबूत करना।
- सरकारी कार्यक्रमों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों के उपयोग का परिचय और विस्तार करना।
- सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और दक्षता को चलाने के लिए डेटा और उपकरण प्रदान करना।
- आवश्यक पाठ्यक्रम सुधार के लिए कमजोरियों और बाधाओं की पहचान करने में मदद करना।

स्वामीनाथन आयोग

समाचार –

- सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना शुरू करती है और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रही है।

स्वामीनाथन रिपोर्ट – किसानों पर राष्ट्रीय आयोग –

- किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का गठन 18 नवंबर, 2004 को प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था।
- रिपोर्ट में '11 वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में परिकल्पित' तेज और अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के सुझाव शामिल हैं।

NCF में निम्न मुद्दों पर सुझाव देना अनिवार्य है –

- समय के साथ सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए एक मध्यम अवधि की रणनीति।
- देश की प्रमुख कृषि प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ाना।
- सभी किसानों को ग्रामीण ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार।
- शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में किसानों के लिए और साथ ही पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में किसानों के लिए शुष्क खेती के लिए विशेष कार्यक्रम।
- खेत की वस्तुओं की गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
- अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से गिरावट आने पर किसानों को आयात से बचाना।
- स्थायी कृषि के लिए पारिस्थितिक नींव का प्रभावी ढंग से संरक्षण और सुधार करने के लिए निर्वाचित स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना।

कुछ मुख्य सिफारिशों में शामिल हैं –

- सीलींग–अधिशेष और बेकार भूमि को वितरित करें।
- गैर–कृषि उद्देश्यों के लिए प्रमुख कृषि भूमि और वन को कॉरपोरेट सेक्टर के लिए रोकना।
- आदिवासियों और पशुपालकों को वनों के लिए अधिकारों और मौसमी पहुंच सुनिश्चित करें, और आम संपत्ति संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करें।
- एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाहकार सेवा की स्थापना, जिसमें भूमि उपयोग के निर्णयों को पारिस्थितिक मौसम विज्ञान तथा मौसम विशिष्ट आधार पर विपणन कारकों के साथ जोड़ने की क्षमता हो ।
- भूमि की मात्रा, प्रस्तावित उपयोग की प्रकृति और खरीदार की श्रेणी के आधार पर कृषि भूमि की बिक्री को विनियमित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें।

नार्को और पॉलीग्राफ परीक्षण

समाचार –

- उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस में कथित गैंगरेप और हत्या की जांच के तहत पॉलीग्राफ और नारकोनेलिसिस परीक्षण कराने का फैसला किया है।
- परीक्षण 'अभियुक्त और पीड़ित पक्ष के सभी लोगों' इसके अलावा 'मामले में शामिल पुलिस अधिकारी और मामले से संबंधित अन्य व्यक्ति' पर किया जाएगा।

पॉलीग्राफ परीक्षण –

- एक पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर परीक्षण इस धारणा पर आधारित है कि जब किसी व्यक्ति के झूठ बोलने पर शारीरिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं जो उसके सामान्य होने पर नही होती है।
- कार्डियो–कफ या संवेदनशील इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण व्यक्ति से जुड़े होते हैं, और चर जैसे कि रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन, पसीने की ग्रंथि की गतिविधि में परिवर्तन, रक्त प्रवाह, आदि को उनसे प्रश्न पूछते समय नापा जाता हैं।
- प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए एक संख्यात्मक मान दिया जाता है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि व्यक्ति सच कह रहा है, धोखा दे रहा है या अनिश्चित है।
- इस तरह का परीक्षण पहली बार 19 वीं सदी में इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट सेसारे लोम्ब्रोसो द्वारा किया गया था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के रक्तचाप में बदलाव को मापने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया था।

नारकोएनेलिसिस टेस्ट –

- नार्कोनालिसिस या ट्रुथ सीरम में एक दवा, सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन शामिल होता है, जो एक कृत्रिम निद्रावस्था या बेहोश अवस्था को प्रेरित करती है, जिसमें विषय की कल्पना बेअसर हो जाती है, और उनसे जानकारी के सही होने की उम्मीद की जाती है।

- दवा, जिसे 'सत्य सीरम' कहा जाता है, का उपयोग सर्जरी के दौरान बेहोशी के लिए किया जाता था, और कहा जाता है कि इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खुफिया अभियानों के लिए किया गया था।

कानूनी पहलु –

- सेल्वी एंड ऑर्सेस बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अनर'(2010) में, एक सुप्रीम कोर्ट बेंच ने फैसला सुनाया कि किसी भी लाई डिटेक्टर परीक्षण' को 'अभियुक्तों की सहमति के बिना' प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए।
- बेंच ने यह भी कहा कि, जो लोग स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं उन्हें एक वकील की सुविधा दी जानी चाहिए तथा पुलिस और वकील द्वारा उन्हें समझाये गये परीक्षण के भौतिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ बताना चाहिए।
- खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 2000 में प्रकाशित अभियुक्तों पर प्रशासन के लिए दिशानिर्देश' जारी किए हैं, एक अभियुक्त के लिए दिशानिर्देशों' का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विषय की सहमति दर्ज की जानी चाहिए।
- परीक्षणों के परिणामों को 'स्वीकारोक्ति' के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि नशीली दवाओं की स्थिति वाले लोग उन सवालों के जवाब देने में एक विकल्प का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो उनके लिए लगाए गए हैं।
- लेकिन पीठ ने उल्लेख किया कि, स्वेच्छा से ली गई परीक्षा की मदद से बाद में खोजी गई किसी भी जानकारी या सामग्री को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
- उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 20 (3) या स्व–उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
- पीड़ितों, विशेष रूप से यौन अपराधों के संदर्भ में, बेंच ने कहा कि इस तरह के मामलों में जांच में तेजी लाने की आवश्यकता के बावजूद, अपराध के शिकार को इन परीक्षणों से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह 'मानसिक गोपनीयता में अनुचित घुसपैठ' और पीड़ित के लिए कलंक का कारण बन सकता है"।
- डी. के. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस, 1997 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पॉलीग्राफ और नार्कोस टेस्ट का अनैच्छिक प्रशासन अनुच्छेद 21 अर्थात जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार होगा।
- यह निजता के अधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है जो जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1871 इन परीक्षणों के परिणामों को सबूत के रूप में स्वीकार नहीं करता है।

लड़कियों के स्कूल छुटने का खतरा

समाचार –

- हरियाणा के सोनीपत जिले ने स्कूल छुट जानी वाली लड़कियों के लिए हेल्पलाइन शुरू की।
- यह बच्चों की सामाजिक–भावनात्मक चुनौतियों को दूर करने और सोनीपत में स्कूल नामांकन बढ़ाने के लिए एक पहल है।

लक्ष्य –

- टोल–फ्री हेल्पलाइन (1800180135) का उद्देश्य कोविड–19 के कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले बच्चों को परामर्श प्रदान करना है, परामर्शदाता माता–पिता को लिंग पूर्वाग्रह के कारण स्कूली शिक्षा तक पहुंच से वंचित करने और करियर मार्गदर्शन का विस्तार करने की धमकी देते हैं।
- यह उन माता–पिता की भी मदद करेगा जो यूपी और बिहार जैसे राज्यों से आए प्रवासी हैं। लॉकडाऊन के दौरान विस्थापित हुए लोगो के बच्चे इसमें दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि –

- केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने स्कूलों को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के दिशानिर्देश जारी किए हैं।

हेल्पलाइन की टीम –

- पांच व्यक्ति हेल्पलाइन का संचालन करेंगे।
- 60 मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, NCERT– और CBSE– प्रमाणित कैरियर और अकादमिक परामर्शदाताओं का एक समूह
- जिले के विभिन्न विद्यालयों के प्रिंसिपल।

मुद्दा –

- महामारी के कारण स्कूल बंद होने से जल्दी शादी करने के मामलों में तेजी आने की संभावना है।
- आंकड़े बताते हैं कि अगर लड़कियां स्कूल में हैं, तो शादी की संभावना बहुत कम हो जाती है और वे जितनी देर शिक्षा में रहती हैं, उतनी ही देर से वे शादी में देरी करा पाती हैं।
- 2004 की सुनामी के दौरान, इंडोनेशिया, भारत और श्रीलंका में लड़कियों को सुनामी विधुरों के साथ शादी के लिए मजबूर किया गया था।
- 2014 में पश्चिम अफ्रीका के इबोला प्रकोप के दौरान स्कूल बंद हुआ और 2015 में नेपाल में भूकंप आया, जिसके परिणामस्वरूप बाल विवाह में तेजी आई।
- कोविड–19 महामारी के आर्थिक प्रभावों के परिणामस्वरूप अगले पाँच वर्षों में 2.5 मिलियन अतिरिक्त लड़कियों की शादी की उम्मीद है तथा यह 58.4 मिलियन बाल विवाहों के अतिरिक्त है।
- ऑनलाइन कक्षाएं अधिकांश छात्रों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हुई हैं जहां बिजली कटौती आम है, इंटरनेट डेटा अप्रभावी है और फोन तक पहुंच सीमित है।

अदालत की अवमानना –

समाचार –

- गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अधिवक्ता यतिन ओझा (गुजरात उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष) को दोषी ठहराया।
- उनके खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई एक अवमानना कार्यवाही में अदालत की अवमानना का मामला है।

मुद्दा –

- श्री ओझा ने उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को निशाना बनाया था और उच्च न्यायालय प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था।
- श्री ओझा ने उच्च न्यायालय के भीतर न्याय के प्रति दुर्भावना के सार्वजनिक आरोप लगाए थे।

न्यायालय की अवमानना क्या है? –

- यह एक अवधारणा है जो न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों और अनुचित आलोचना से बचाने के लिए, और इसके अधिकार को कम करने वालों को दंडित करने के लिए एक कानूनी तंत्र के रूप में देखना चाहती है।

अवमानना की अवधारणा कैसे अस्तित्व में आई? –

- अदालत की अवमानना की अवधारणा कई सदियों पुरानी है।
- इंग्लैंड में, यह एक सामान्य कानून सिद्धांत है जो राजा की न्यायिक शक्ति की रक्षा करने का प्रयास करता है, शुरू में स्वयं द्वारा और बाद में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा जो उसके नाम पर कार्रवाई करता है।
- न्यायाधीशों के आदेशों का उल्लंघन स्वयं राजा के आदेशों के उल्लंघन के बराबर माना जाता था।
- समय के साथ, न्यायाधीशों की किसी भी तरह की अवज्ञा, या उनके निर्देशों, या टिप्पणियों और कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उनके प्रति असम्मान प्रकट करना दंडनीय हो गया।

न्यायालय की अवमानना का वधानिक आधार क्या है?

- भारत में अवमानना के स्वतंत्रता–पूर्व के कानून। शुरुआती उच्च न्यायालयों के अलावा, कुछ रियासतों की अदालतों में भी ऐसे कानून थे।
- जब संविधान को अपनाया गया था, तो अदालत की अवमानना को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध माना गया था।
- अलग से, संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना को दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों पर एक समान शक्ति प्रदान की।
- न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971, विचार को वैधानिक समर्थन देता है।

अदालत की अवमानना के प्रकार क्या हैं?

- अवमानना संहिता कानून इसे नागरिक और आपराधिक के रूप में वर्गीकृत करता है।
- नागरिक अवमानना तब होती है जब कोई न्यायालय के आदेश की अवज्ञा करता है, या न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन करता है।

- आपराधिक अवमानना अधिक जटिल है। इसके तीन रूप हैं –
  (ए) शब्द, लिखित या बोली, संकेत और कार्य जो किसी भी अदालत के अधिकार को 'निंदनीय' या 'कमतर' साबित करने के लिए दिए जाते हैं'।
  (इ) किसी भी न्यायिक कार्यवाही में पूर्वाग्रह या हस्तक्षेप करते हो।
  (ब) न्याय प्रशासन में बाधा डालते है।
- अदालत की अवमानना की सजा छह महीने तक की साधारण कारावास और / या 2000 रूपये तक का जुर्माना है।

क्या अदालत की अवमानना नहीं है?

- न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग अदालत की अवमानना नहीं होगी।
- न ही किसी मामले की सुनवाई और निपटारे के बाद न्यायिक व्यवस्था की खूबियों पर निष्पक्ष आलोचना ही अदालत की अवमानना होती है।

स्यो मोटो कॉग्निजेंस –

- कानून में, स्यो मोटो या स्यो स्पोंटे किसी अन्य पक्ष से औपचारिक संकेत दिए बिना प्राधिकरण के एक अधिनियम का वर्णन करता है।
- इस शब्द को आमतौर पर पूर्व प्रस्ताव या पक्षकारों के अनुरोध के बिना लिए गए न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई के लिए लागू किया जाता है।
- स्यो मोटो संज्ञान एक लैटिन शब्द है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जनहित याचिका दायर (पीआईएल) करने के प्रावधान किए हैं। यह अदालत को किसी मामले के संज्ञान पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की शक्ति देता है।
- स्यो मोटो की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति भारतीय के अनुच्छेद 131 के तहत प्रदान की गई है संविधान।
- भारतीय अदालतों द्वारा स्यो मोटो की कार्रवाई न्यायिक सक्रियता का प्रतिबिंब है।

नागोनो–काराबाख क्षेत्र

समाचार –

- विवादित नागोर्नो–करबाख क्षेत्र पर अर्मेनियाई और अजरबैजानी बलों के बीच युद्ध हुआ।
- यह लड़ाई 28 सितंबर को नागोर्नो–करबाख पर एक लंबे अरसे से चल रहे क्षेत्रीय विवाद में शुरू हुई थी, जो एक अर्मेनियाई एनक्लेव था तथा जो 1990 के दशक में अजरबैजान से अलग हो गया था।
- ईसाई–बहुसंख्यक आर्मेनिया रूस के नेतृत्व वाले पूर्व सोवियत राज्यों के सैन्य गठबंधन में है, जिसका देश में स्थायी आधार है लेकिन उसने संघर्ष में वृद्धि की ईच्छा नहीं दिखाई है।
- तुर्की अजरबैजान का एक वफादार सहयोगी, एक मुस्लिम और तुर्क देश है, और उस पर सीरिया और लीबिया में लड़ाई में शामिल होने के लिए से भाड़े के सैनिकों को भेजने का आरोप है।

नागोर्नो–कारबाख

- नागोर्नो–करबाख एक विवादित क्षेत्र है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन ज्यादातर यह अर्तसाख गणराज्य (पूर्व में नागोर्नो–करबाख गणराज्य नाम दिया गया था) द्वारा शासित रहा है। एक वास्तविक रूप से स्वतंत्र राज्य जिसके पास आर्मेनियाई जातीय बहुमत था, जिसके आधार पर अजरबैजान सोवियत समाजवादी गणराज्य का हिस्सा बना।
- 1988 में काराबख आंदोलन के आगमन के बाद से अजरबैजान ने इस क्षेत्र पर राजनीतिक अधिकार का प्रयोग नहीं किया है।
- 1994 में नागोर्नो–काराबाख युद्ध की समाप्ति के बाद से, आर्मेनिया और अजरबैजान की सरकारों के प्रतिनिधि क्षेत्र की विवादित स्थिति के लिए ओएससीई मिन्स्क समूह द्वारा मध्यस्थता के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं।

संघर्ष –

- वर्तमान संघर्ष 1988 में शुरू हुआ, जब काराबाख अर्मेनियाई लोगों ने मांग की कि काराबाख को सोवियत अजरबैजान से सोवियत आर्मेनिया में स्थानांतरित किया जाए। 1990 के दशक की शुरुआत में संघर्ष एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल गया।

नागोर्नो–काराबाख युद्ध (1988–1994)

- नागोर्नो–काराबाख युद्ध, जिसे अर्मेनिया और नागोर्नो–काराबाख में अर्तसाख लिबरेशन युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, एक सशस्त्र संघर्ष था, जो 1980 के दशक से मई 1994 के अंत में दक्षिण–पश्चिमी अजरबैजान के नागोर्नो–करबाख के एन्क्लेव में बहुसंख्यक जातीय के बीच हुआ था।
- जैसे ही युद्ध आगे बढ़ा, अर्मेनिया और अजरबैजान, दोनों पूर्व सोवियत गणराज्यों ने खुद को करबख के पहाड़ी इलाकों में अघोषित युद्ध में उलझा दिया, अजरबैजान ने नागोर्नो–करबख में अलगाववादी आंदोलन को रोकने का प्रयास किया।

सीमा संघर्ष (1994–2016)

- 2008 अर्मेनियाई चुनावों के विरोध के बाद 4 मार्च को 2008 मेर्डाकर्ट संघर्ष शुरू हुआ।
- इसमें नागोर्नो–कराबाख युद्ध के बाद 1994 के युद्धविराम के बाद से नागोर्नो–कराबाख के विवादित क्षेत्र पर जातीय अर्मेनियाई और अजरबैजानी बलों के बीच सबसे भारी लड़ाई शामिल थी।
- अर्मेनियाई स्रोतों ने अजरबैजान पर अर्मेनिया में चल रही अशांति का फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अजरबैजानी स्रोतों ने आर्मेनिया को दोषी ठहराया।
- यह दावा करते हुए कि अर्मेनियाई सरकार आर्मेनिया में आंतरिक तनाव से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी।
- इस घटना के बाद, 14 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गोद लिए गए 7 के पक्ष में 39 के एक रिकॉर्ड वोट से संकल्प 62/243, अजरबैजान के कब्जे वाले क्षेत्रों से सभी अर्मेनियाई बलों की तत्काल वापसी की मांग।

2020 –

- जुलाई 2020 में तवाश के पास और झड़पें हुईं। तेरह एजेरिस, जिसमें एक नागरिक भी शामिल था, और पाँच अर्मेनियाई मारे गए थे।
- 16 सितंबर को एक मामूली सीमा झड़प में, एक अर्मेनियाई सैनिक मारा गया, पांच दिन बाद, एक अजरबैजान सैनिक मारा गया।
- 27 सितंबर को नागोर्नो–करबाख में गंभीर झड़पें हुईं, जिससे आर्मेनिया को मार्शल लॉ और गोलबंदी की घोषणा करनी पड़ी।
- उसी दिन, कई शहरों और क्षेत्रों में झड़पों के बाद कर्फ्यू की स्थापना के बाद अजरबैजान की संसद ने आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध की स्थिति घोषित की।
- हताहतों के मामले में, संघर्ष 2016 के बाद से सबसे खराब था और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खतरे का कारण बन गए, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने दोनों पक्षों को मेज पर लौटने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शत्रुता को फिर से शुरू करने की निंदा की।

टेलीविजन रेटिंग प्वाईंट्स

समाचार –

- मुंबई पुलिस ने कहा कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) इंडिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में हेराफेरी करके TRP (टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स) में हेराफेरी के मामले में पुलिस को एक घोटाले की तलाश है, जिसमें भारत में टेलीविजन दर्शकों को मापने का जनादेश है।

टीआरपी क्या है?

- टीआरपी यह दर्शाती है कि किसी विशेष अवधि के दौरान कितने लोगों ने, सामाजिक–आर्थिक श्रेणियों ने कितने चैनलों को देखा। यह एक घंटे, एक दिन या एक सप्ताह के लिए भी हो सकता है।
- भारत एक मिनट के अंतरराष्ट्रीय मानक का पालन करता है।
- डेटा आमतौर पर हर हफ्ते सार्वजनिक किया जाता है।

रेटिंग का महत्व –

- दर्शकों के माप डेटा के आधार पर, टेलीविजन पर विभिन्न कार्यक्रमों को रेटिंग दी जाती है।
- टेलीविजन रेटिंग दर्शकों के लिए निर्मित कार्यक्रमों को प्रभावित करती है।
- बेहतर रेटिंग एक कार्यक्रम को बढ़ावा देगी जबकि खराब रेटिंग एक कार्यक्रम को हतोत्साहित करेगी।
- गलत रेटिंग से उन कार्यक्रमों का उत्पादन होगा जो वास्तव में लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं जबकि अच्छे कार्यक्रमों को छोड़ दिया जा सकता है।

BARC क्या है? –

- यह एक उद्योग निकाय है जो विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों और प्रसारण कंपनियों के स्वामित्व में है, जिसका प्रतिनिधित्व द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवरटाइजर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और एडवरटाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है।
- यह 2010 में बनाया गया था, I–B मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए 10 जनवरी, 2014 को टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था और इन दिशानिर्देशों के तहत जुलाई 2015 में BARC को पंजीकृत किया था, ताकि भारत में टेलीविजन रेटिंग की जा सके।

टीआरपी की गणना कैसे की जाती है?

- BARC ने 45,000 से अधिक असहाय घरों में BAR–O–meter' स्थापित किया है।
- इन घरों को नई उपभोक्ता वर्गीकरण प्रणाली (एनसीसीएस) के तहत 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- एक शो देखते समय, घर के सदस्य अपने दर्शक आईडी बटन को दबाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं – घर के प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग आईडी होती है – इस प्रकार उस अवधि को कैप्चर करना जिसके लिए चैनल को देखा गया था और जिसके द्वारा उम्र एवं सामाजिक–आर्थिक समूह के आधार पर टीवी देखने की आदतों के आँकड़े प्राप्त होते हैं।

टीआरपी डेटा में कैसे धांधली हो सकती है?

- यदि ब्रॉडकास्टर्स उन घरों को ढूंढ सकते हैं जहां उपकरण स्थापित हैं, तो वे या तो अपने चैनल देखने के लिए उन्हें रिश्वत दे सकते हैं, या केबल ऑपरेटरों या मल्टी–सिस्टम ऑपरेटरों से कह सकते हैं कि जब टीवी स्विच किया जाता है तो उनका चैनल 'लैंडिंग पृष्ठ' के रूप में उपलब्ध हो।

SVAMITVA योजना

समाचार –

- प्रधानमंत्री ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के लिए SVAMITVA योजना के तहत संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण का शुभारंभ करेंगे।
- इस योजना को चार साल की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है और इसमें देश के लगभग छह लाख 62 हजार गाँव शामिल होंगे।
- कार्यक्रम वर्तमान में छह राज्यों – हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कार्यान्वित किया जा रहा है।

SVAMITVA योजना –

- SVAMITVA योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इसे अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था।
- इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव के गृहस्वामियों को अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना शामिल है।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) नोडल मंत्रालय है।
- राज्यों में, राजस्व विभाग/भूमि रिकॉर्ड विभाग नोडल विभाग होगा और राज्य पंचायती राज विभाग के समर्थन से इस योजना को आगे बढ़ाएगा।
- ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण आबदी क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा।

उद्देश्य –

- ग्रामीण भारत में नागरिकों को वित्तीय स्थिरता लाने के लिए उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए एक वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सक्षम करना।
- ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण।
- संपत्ति कर का निर्धारण, जो जीपी में सीधे उन राज्यों में जमा होता है, जहां यह विकसित होता है या फिर, राज्य के खजाने में जुड़ते हैं।
- सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और जीआईएस नक्शे का निर्माण जो किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है।
- जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना।
- संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करने के लिए।

महत्व –

- यह ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए ग्रामीणों द्वारा वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

निष्कर्ष –

- यह पहली बार है जब तकनीक के सबसे आधुनिक साधनों से जुड़े इस तरह के बड़े पैमाने पर अभ्यास लाखों ग्रामीण संपत्ति मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र स्टिल बर्थ रिपोर्ट

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र ने 'ए नेगलेक्टेड ट्रेजेडी – द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिलबर्थ' शीर्षक के स्टिलबर्थ पर पहली रिपोर्ट शुरू की।
- रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है।

स्टिलबर्थ

- स्टिलबर्थ का अर्थ है एक बच्चा जो गर्भावस्था के 28 सप्ताह में जीवन के कोई लक्षण नहीं रखता है।

मुख्य निष्कर्ष

- प्रत्येक 16 सेकंड में एक स्टिलबर्थ बेबी का जन्म होता हैं जिसका अर्थ है एक वर्ष के दौरान लगभग दो मिलियन शिशु जो कभी भी अपनी पहली सांस नहीं लेते हैं।
- 2019 में निम्न और मध्यम–मध्यम आय वाले देशों में 84 प्रतिशत स्टिलबर्थ पाए जाते हैं।
- स्टिलबर्थ उच्च आय देशों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं, जहां शिक्षा का एक माँ का शिक्षा का स्तर असमानता के सबसे महान कारकों में से एक है, और जातीय अल्पसंख्यकों को पर्याप्त गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी हो सकती है।
- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कोविड–19 महामारी संभावित रूप से अगले 12 महीनों में स्टिलबर्थ की संख्या में और वृद्धि का कारण बनेगी।
- 117 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में महामारी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं 50 प्रतिशत की कमी, आगामी वर्ष में लगभग 2,00,000 अतिरिक्त प्रसव के लिए जिम्मेदार हो सकती है।
- गर्भावस्था और प्रसव देखभाल की खराब गुणवत्ता, प्रसवपूर्व और अंतर्गर्भाशयी सेवाओं की कमी और कमजोर नर्सिंग और दाई का काम इनमें से अधिकांश घटनाओं के लिए जिम्मेदार है।

- रिपोर्ट बताती है कि महामारी से पहले भी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कुछ ही महिलाओं को समय पर प्राप्त होने वाली उच्च–गुणवत्ता वाली देखभाल मिली, जो आठ महत्वपूर्ण मातृ स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में सी–सेक्शन, मलेरिया की रोकथाम और गर्भावस्था उच्च रक्तचाप प्रबंधन इत्यादि थे में 2 प्रतिशत से कम केवल 50 प्रतिशत तक थी।
- 2000 से 2019 तक स्वास्थ्य सेवाओं में प्रगति के बावजूद, नवजात मृत्यु दर में 2.9 प्रतिशत की कमी और 59 से एक महीने की उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 4.3 प्रतिशत की तुलना में वार्षिक स्टिलबर्थ कमी दर सिर्फ 2.3 प्रतिशत थी।

आगे की राह –

- रिपोर्ट बताती है कि स्टिलबर्थ रेट को कम करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

समाचार –

- उच्चतम न्यायालय ने आठ राज्यों को अपने परिवारों के साथ 'तत्काल प्रत्यावर्तन' के लिए देखभाल घरों में रहने वाले बच्चों को 'उत्पादन' करने के अपने अनुरोध के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से जवाब मांगा।
- आठ राज्य – तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय हैं। इन राज्यों में संयुक्त रूप से देखभाल घरों में 1.84 लाख बच्चे हैं।
- यह संख्या केयर होम्स में रह रहे 70% से अधिक के बराबर है।
- इन राज्यों में संयुक्त रूप से देखभाल घरों में 1.84 लाख बच्चे हैं।

उच्चतम न्यायालय –

- न्यायालय ने किशोर अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे बच्चों पर ध्यान दें कि बच्चों को सबसे अच्छी रुचि, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं के साथ बाल देखभाल संस्थानों में रखा जाना चाहिए।
- अदालत ने आश्चर्य जताया कि क्या NCPCR शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की सुरक्षा, उनके माता–पिता की सहमति और उनकी आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना राज्यों को ऐसे सामान्य निर्देश जारी कर सकता है।

पृष्ठभूमि –

- एमिकस क्यूरी ने कहा कि NCPCR के निर्देश ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 का उल्लंघन किया है।
- महामारी एक बच्चे को घरेलू दुर्व्यवहार के लिए अधिक संवेदनशील बना देती है।

> - एमिकस क्यूरिया वह व्यक्ति है जो किसी ऐसे मामले का पक्षकार नहीं है, जो सूचना, विशेषज्ञता, या अंतर्दृष्टि प्रदान करके अदालत में सहायता करता है, जिसका उस मामले में असर पड़ता है। वाक्यांश एमिकस क्यूरिया लैटिन है।

महत्व –

- महामारी के दौरान देश भर के देखभाल घरों में बच्चों की स्थिति और कल्याण की निगरानी करने के लिए अदालत स्वतः संज्ञान ले रही है।

> - कानून में, स्यो मोटो किसी अन्य पार्टी से औपचारिक संकेत दिए बिना प्राधिकरण के एक अधिनियम का वर्णन करता है। इस शब्द को आमतौर पर पूर्व प्रस्ताव या पक्षकारों के अनुरोध के बिना एक न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई के लिए लागू किया जाता है।

कयर हाम–

- यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन बच्चों की देखभाल की जाती है जो अनाथ/परित्यक्त बच्चे/बच्चे हैं जो दलित / आर्थिक रूप से अस्थिर परिवारों से हैं।
- यदि कोई बच्चा है जो या तो एक एकल माता–पिता द्वारा पाला जा रहा है या ऐसे परिवार से आता है जो बच्चे को ठीक से पालने में सक्षम नहीं है, तो वह बच्चा देखभाल घर की सुविधाओं का लाभ उठा सकता है।

> **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग –**
> - एनसीपीसीआर एक वैधानिक निकाय है जो संसद के एक अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 द्वारा स्थापित किया गया है।
> - आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।
> - आयोग ने 5 मार्च, 2007 को परिचालन शुरू किया।
> - आयोग को सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत अनिवार्य किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान में सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकार के दृष्टिकोण और संयुक्त राष्ट्र के चिल्ड्रन कन्वेंशन के अनुरूप हैं।
> - जैसा कि आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है, बच्चे में 18 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति शामिल है।

आरटीआई पर रिपोर्ट

समाचार –

- सूचना का अधिकार (आरटीआई) की 15 वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए सतर्क नागरिक संगठन और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा एक रिपोर्ट कार्ड लाया गया है।
- केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में 2.2 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जो पारदर्शिता कानून के तहत अपील की अंतिम अदालतें हैं।

मुख्य निष्कर्ष –

- बढ़ते बैकलॉग को इस तथ्य से बढ़ा दिया गया है कि अधिकांश आयोग कम क्षमता पर काम कर रहे हैं।
- महाराष्ट्र में 59,000 से अधिक मामलों के साथ सबसे अधिक लंबित अपीलें थीं, इसके बाद उत्तर प्रदेश (47,923) और सीआईसी (35,653) थे।
- निपटान की वर्तमान दर पर, ओडिशा आयोग को सभी लंबित शिकायतों के निपटान में सात साल से अधिक का समय लगेगा।
- ओडिशा सिर्फ चार आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, जबकि राजस्थान में केवल तीन हैं।
- झारखंड और त्रिपुरा में कोई आयुक्त नहीं है।
- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) भी अगस्त से ही मुखिया है। CIC का कोई प्रमुख नहीं है, और केवल पांच आयुक्त हैं।
- कानून के तहत, प्रत्येक आयोग में एक प्रमुख और अधिकतम 10 आयुक्त होने चाहिए।
- विश्लेषण में यह भी पाया गया कि सरकारी अधिकारियों को कानून का उल्लंघन करने के लिए किसी भी सजा का सामना करना पड़ता है।

- 2019–20 में 16 आयोगों के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, रिपोर्ट में पाया गया कि केवल 2.2% मामलों में जुर्माना लगाया गया था, जिनका निपटान किया गया था।
- अप्रैल 2019 से जुलाई 2020 के बीच 16 आयोगों द्वारा निपटाए गए लगभग 90,000 मामलों में से 15,700 से अधिक मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 1,995 मामलों में जुर्माना लगाया गया।
- गुजरात 9,000 से अधिक कारण बताओ नोटिस के लिए जिम्मेदार है, लेकिन केवल 163 में दंड दिए गए हैं।
- यहां तक कि अपील/शिकायतों के बैकलॉग में लगातार वृद्धि हो रही है और वर्तमान में रिपोर्ट के अनुसार सीआईसी के मामले में 36,500 से अधिक मामले हैं।

परिणाम –

- आयोगों द्वारा योग्य मामलों में जुर्माना न लगाने से सार्वजनिक अधिकारियों को संकेत मिलता है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा कोई गंभीर परिणाम।
- यह आरटीआई कानून में निर्मित प्रोत्साहन के मूल ढांचे को नष्ट कर देता है और एक संस्कृति को बढ़ावा देता है।

सूचना का अधिकार –

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देता है।
- यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा की गई एक पहल है, जो नागरिकों को पहले अपीलीय प्राधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरणों की त्वरित खोज के लिए नागरिकों को आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के अलावा भारत सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी / खुलासे तक पहुँच प्रदान करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य –

- सूचना का अधिकार कानून का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को समाहित करना और वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए हमारे लोकतंत्र का काम करना है।
- स्पष्ट है कि एक सूचित नागरिक शासन के उपकरणों पर आवश्यक सतर्कता बरतने के लिए बेहतर है और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाता है।
- अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

केंद्रीय सूचना आयोग –

- अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के गठन के लिए जिम्मेदार अधिनियम अधिनियम के धारा 18 के तहत उस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है।
- इस धारा के तहत CIC में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, जो आयोग का प्रमुख होता है, और ऐसे केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या, जिन्हें आवश्यक समझा जा सकता है, लेकिन दस से अधिक नहीं।
- 26 अक्टूबर 2005 को, श्री वजाहत हबीबुल्लाह भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने।
- CIC के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त को सिवाय पदों के सृजन, पुर्नस्थापन और लेखन–बंद के नुकसान के मामलों में जिसके लिए इसे मंत्रालय की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता होती है, भारत सरकार के विभाग के पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
- आयोग के मामलों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होते हैं, जिन्हें सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य सूचना आयोग –

- राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC) के साथ किया जाता है, और राज्य सूचना आयुक्तों (SIC) को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है जिनकी संख्या 10 से अधिक नही हो सकती।
- आयोग और आयुक्त आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन होने के बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
- नियुक्ति समिति का नेतृत्व मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, जिसमें विधान सभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं।
- एससीआईसी/एसआईसी के रूप में नियुक्ति की योग्यता केंद्रीय आयुक्तों के लिए समान होगी।
- केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग के समान कर्तव्य होते हैं लेकिन केंद्रीय स्तर और न्यायालयों में।
- नागरिक न्यायालयों की शक्तियाँ सीआईसी के समान हैं – जैसे – सम्मन भेजना और शपथ लेना, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, सार्वजनिक रिकॉर्ड जारी करना आदि।

गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2020

समाचार –

- राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष गुजरात विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक – एक विवादास्पद कानून जिसे 'अशांत क्षेत्र अधिनियम' के रूप में जाना जाता है को मंजुरी दे दी विधेयक में अचल संपत्ति के स्थानांतरण तथा किरायेदारों के संपत्ति से बेदखल करने प्रावधानों से संबंधित कानून में संशोधन किए गए हैं।

अशांत क्षेत्र अधिनियम क्या है?

- अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत, एक जिला कलेक्टर किसी शहर या कस्बे के किसी विशेष क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में अधिसूचित कर सकता है।
- यह अधिसूचना आम तौर पर क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगों के इतिहास के आधार पर की जाती है।
- परेशान क्षेत्र में अचल संपत्ति का हस्तांतरण केवल कलेक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से खरीदार और संपत्ति के विक्रेता द्वारा किए गए आवेदन पर हस्ताक्षर करने के बाद हो सकता है।
- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कारावास और जुर्माने को आमंत्रित करता है।
- राज्य सरकार का दावा है कि इस अधिनियम का उद्धेश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जाँच करना है।

सरकार ने अधिनियम में संशोधन क्यों किया? –

- अधिनियम में संशोधन का विचार विधायकों और अन्य लोगों की उन शिकायतों के बाद आया था, जिन्होंने इसमें कानूनी खामियों का लाभ उठाकर अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर कर दिया था।

- यह तर्क दिया गया कि इससे संभावित रूप से एक विशेष इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो सकता है।
- अधिनियम के पहले संस्करण में, जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना था कि विक्रेता द्वारा एक शपथ पत्र के आधार पर, कि उसने अपनी मर्जी की संपत्ति बेची थी, और उसे संपत्ति का ऊचित बाजार मूल्य मिला है।
- असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों को धमकाने या 'अशांत' के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में अधिक कीमत का लालच देकर संपत्तियों को बेचने और खरीदने की खबरें थीं।
- यह बताया गया कि, इन तत्वों को स्थानान्तरण विलेख प्राप्त करके कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना भी स्थानान्तरण किया गया था।
- पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है, जिसमें डीए अधिनियम के तहत कलेक्टर की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।
- इसके परिणामस्वरूप इलाकों का क्लस्टरिंग या ध्रुवीकरण हो गया था।
- इस तरह की खामियों को दूर करने के लिए और अधिनियम के उल्लंघन के लिए सजा को बढ़ाने के लिए, संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था जो पिछले वर्ष जुलाई में गुजरात विधानसभा में पारित हुआ।

संशोधित अधिनियम में प्रमुख प्रावधान क्या हैं? –

- संशोधित अधिनियम कलेक्टर को यह पता लगाने के लिए और अधिक अधिकार देता है कि क्या किसी समुदाय विशेष के व्यक्तियों के 'ध्रुवीकरण' या 'अनुचित क्लस्टरिंग' की संभावना है, इस प्रकार क्षेत्र में जनसांख्यिकीय संतुलन में गड़बड़ी होती है। साथ ही, राज्य सरकार अब कलेक्टर द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा करने के लिए अधिकृत है।
- इन पहलुओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) या समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। नगर निगम क्षेत्रों में, SIT में संबंधित कलेक्टर, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त शामिल होंगे। नगर निगमों के अलावा अन्य क्षेत्रों में, SIT में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय नगर आयुक्त सदस्य होंगे।
- संशोधित अधिनियम राज्य सरकार को एक सलाहकार समिति बनाने में सक्षम बनाता है जो इसे डीए अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर सलाह देगी, जिसमें नए क्षेत्रों को अशांत क्षेत्रों की सूची में शामिल करना शामिल है।
- संशोधन ने मूल अधिनियम में एक प्रावधान जोड़ा है जो राज्य सरकार को पर्यवेक्षक को अधिनियम से संबंधित कलेक्टर के फैसले की समीक्षा करने का अधिकार देता है, भले ही उसी के खिलाफ कोई अपील दायर न की गई हो।
- कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों के हस्तांतरण के पंजीकरण की जांच करने के लिए, संशोधित अधिनियम में 'ट्रांसफर' शब्द का दायरा बढ़ाने का प्रावधान है, और इसमें बिक्री, उपहार, विनिमय और पट्टे के माध्यम से अशांत क्षेत्र में ऐसी संपत्ति पर अधिकार, शीर्षक या ब्याज का हस्तांतरण शामिल है।
- इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अधिनियम ने पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया है जिसके तहत कोई संपत्ति कलेक्टर की पूर्वानुमति के बिना अशांत क्षेत्रों को पंजीकृत नही की जा सकती है।
- संपत्ति के पुनर्विकास की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वह मालिक के उद्देश्य के लिए हो। लेकिन यदि मालिक नए लोगों को पुनर्विकास की गई संपत्ति पर लाने की योजना बना रहा है, तो उसे कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी।
- अधिनियम के प्रावधान किसी अशांत क्षेत्र में सरकार की पुनर्वास योजनाओं पर लागू नहीं होंगे, जहां यह विस्थापित लोगों का निवास करता है।
- सरकार के अनुसार, पहले केवल उन क्षेत्रों को देखा जाना था जिन्हें 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। हालाँकि, अब, सरकार किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र 'के रूप में अधिसूचित कर सकती है, जहाँ सांप्रदायिक दंगे की संभावना को देखती है, या जहाँ यह एक विशेष समुदाय के ध्रुवीकरण की संभावना को देखती है।

संशोधित अधिनियम में उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान क्या हैं? –

- अधिनियम के उल्लंघन के लिए सजा पहले छह महीने के लिए कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना थी।
- संशोधन ने सजा को तीन वर्ष कैद से बढ़ाकर पांच साल कर दिया है।
- जुर्माने की दर को बढ़ाकर 1 लाख रुपये या 10% जन्त्री दर (राज्य के विभिन्न हिस्सों में संपत्ति की कीमतों की तैयार लिसट) जो भी अधिक हो, किया गया है।

गुजरात में वर्तमान में डीए एक्ट किन क्षेत्रों में लागू है?

- डीए अधिनियम अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, हिम्मतनगर, गोधरा, कपडवंज और भरूच में लागू है।

संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी (UNRWA)

समाचार –

- भारत ने निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी (UNRWA) में एक मिलियन डॉलर का योगदान दिया है, जो कोविड–19 महामारी के कारण अत्यधिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- यह सहायता एजुकेशन, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के कार्यक्रमों और सेवाओं का समर्थन करेगी।

विवरण –

- फिलिस्तीनी के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है।
- भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएँ और आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने में UNRWA की गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखेगा।
- UNRWA को भारी बजटीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 5.6 मिलियन शरणार्थियों के भारी बहुमत के साथ, चल रही महामारी ने उनके रहने वाले क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की रीढ़ तोड़ दी है।
- भारत ने कोविड–19 स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण को दवाएं और अन्य आपूर्ति भी भेजी हैं।

UNRWA और भारत –

- भारत ने 2016 में UNRWA में अपना वार्षिक वित्तीय योगदान 1.25 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 2018 और 2019 में 5 मिलियन अमरीकी डालर कर दिया।
- इसने मई 2020 में एजेंसी को दो मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया था जो इस वर्ष के लिए कुल योगदान तीन मिलियन अमरीकी डालर तक दूर लाता है।

- 23 जून 2020 को आयोजित UNRWA के एक आभासी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान, भारत ने घोषणा की थी कि वह अगले दो वर्षों में UNRWA में 10 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान देगा।
- भारत–फिलिस्तीन विकास साझेदारी भारत वर्तमान में विकास संबंधी आठ परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है, जिनमें शामिल हैं–
  - बेथलहम में 215 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण
  - सूचना प्रौद्योगिकी पार्क
  - नेशनल प्रिंटिंग प्रेस
  - तुरथी–महिला सशक्तिकरण परियोजना
  - राजनयिक प्रशिक्षण संस्थान
  - फिलिस्तीनी क्षेत्रों में विभिन्न गवर्नरों में तीन स्कूल

UNRWA

- यह 1949 में महासभा द्वारा स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है और अपने पांच क्षेत्रों में UNRWA के साथ पंजीकृत कुछ 5.6 मिलियन फिलिस्तीन शरणार्थियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनिवार्य है।
- इसका मिशन जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद करना है, जिसमें पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी अपने पूर्ण मानव विकास क्षमता को प्राप्त करते हैं, उनकी दुर्दशा के लिए एक उचित और स्थायी समाधान लंबित है।
- UNRWA सेवाएं शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं, शिविर बुनियादी ढांचे और सुधार, संरक्षण, और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के बीच माइक्रोफाइनेंस को शामिल करती हैं।

परिभाषा –

- फिलिस्तीन के शरणार्थी 'ऐसे व्यक्ति हैं जिनके निवास का नियमित स्थान 1 जून 1946 से 15 मई 1948 की अवधि के दौरान फिलिस्तीन था, और जिन्होंने 1948 के संघर्ष के परिणामस्वरूप घर और आजीविका दोनों को खो दिया था।'

मूलवाद

समाचार –

- 3 नवंबर के चुनाव से पहले रिपब्लिकन सांसदों द्वारा व्यापक रूप से पुष्टि किए जाने की उम्मीद करने वाले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एमी कोनी बैरेट ने 'मूलवाद' को उनके कानूनी दर्शन के रूप में वर्णित किया है।

एमी कोनी बैरेट –

- बैरेट, को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा देश के 9–सदस्यीय शीर्ष न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाने वाला तीसरा न्यायाधीश माना जाता है – जहाँ न्यायिक रूप से जीवन की सेवा की जा सकती है।

विवरण –

- मूलवाद का अर्थ है देश के संविधान की 18 वीं सदी के संस्थापक नेताओं के इरादों के अनुसार बनाना।
- कानूनी दर्शन में, यह सिद्धांत बताता है कि विवादों को हल करते समय, न्यायाधीशों को संविधान की व्याख्या करनी चाहिए क्योंकि यह उस समय समझा गया था, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से सहमत हों या किसी मामले के परिणाम से असहमत हों या नहीं।
- मूलवादियों के अनुसार, संविधान का अर्थ उसके निर्धारण के समय, या तो प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के रूप में, या मसौदाकारों के इरादों के रूप में तय किया जाता है। अदालत का काम इस मूल अर्थ से चिपके रहना है।
- शब्द 'मूलवाद' 1980 के दशक में गढ़ा गया था, और तब से अमेरिकी परंपरावादियों के बीच लोकप्रिय है, जिन्होंने देश की संघीय अदालतों पर न्यायिक संयम को बढ़ावा देने की मांग की है।
- मूलवाद के अनुयायियों का मानना है कि चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए नए कानूनों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाया जाना चाहिए, न कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, जिसमें न्यायाधीश संविधान की नई व्याख्या करते हैं।

'लिविंग संविधान' सिद्धांत

- जिस कानूनी दर्शन को मूलवाद के विपरीत कहा जाता है वह 'जीवित संविधान' या 'आधुनिकतावाद' है।
- यह सिद्धांत, दिवंगत न्यायमूर्ति जिन्सबर्ग की पसंद से प्रभावित है, जिनका मानना है कि बदलती सामाजिक आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए संविधान को समय के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए।

कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020

समाचार –

- छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक दिन के सत्र में केंद्र की हाल ही में अधिसूचित कृषि विधानों को अमान्य करने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया।
- विधानसभा ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 पारित किया। यह राज्य सरकार को निम्न शक्ति प्रदान करता है –
  – सभी कृषि उपज बाजारों को विनियमित करने के लिए
  – डीम्ड बाजारों की एक नई अवधारणा प्रस्तुत करता है जिसमें शीत भंडार और साइलो शामिल हैं
  – राज्य नियंत्रण के तहत एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक स्थान की स्थापना का प्रावधान करता है
  – एक क्रेता को निरीक्षण के लिए अपने रिकॉर्ड और स्टॉक जमा करना अनिवार्य बनाता है
  – कानून के उल्लंघन के लिए छह महीने तक जेल अवधि का परिचय

विवरण –

- राज्य सरकार ने डीम्ड बाजार की अवधारणा पेश की है और इन पर राज्य एजेंसियों को नियंत्रण दिया है। डीम्ड बाजार इसमें कोल्ड स्टोरेज, साइलो, वेयरहाउस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म शामिल होंगे।
- संशोधन के साथ, राज्य सरकार किसी भी कॉर्पोरेट या निजी संस्था के प्रवेश को सीमित करने की उम्मीद करती है क्योंकि यह इन सभी कार्यों को नियंत्रित करेगा।
- यदि कोई निजी संस्था किसानों के साथ समझौता करती है, तो उसे अपने खातों और शेयरों को राज्य जांच के लिए जमा करना होगा।
- एक अन्य संशोधन ने राज्य सरकार को एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देने की शक्ति भी दी है जहां राज्य या किसी अन्य राज्य के किसान अपनी कृषि उपज खरीद या बेच सकते हैं। यह सीमाओं के बिना कृषि व्यापार के केंद्र के प्रावधान को बेअसर कर देता है।

- राज्य सरकार अधिसूचित कृषि उपज, किसान/विक्रेता को अपनी उपज स्थानीय बाजार के साथ–साथ राज्य के अन्य बाजारों और अन्य राज्यों के व्यापारियों को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेचने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना कर सकती है।

कृषि बिल क्यों पारित किए गए? –

- सरकार–प्रबंधन मंडियों के एकाधिकार को पूरा करने के लिए। यह किसानों को निजी खरीदारों को सीधे बेचने की अनुमति देने के लिए भी पारित हुआ।
- किसानों को संगठन के साथ लिखित अनुबंध में प्रवेश करने और उनके लिए उत्पादन करने के लिए एक कानूनी ढांचा देना।
- कृषि–व्यवसायों को खाद्य लेखों को स्टॉक करने की अनुमति देना। मनमाने तरीके से प्रतिबंध लगाने की सरकार की क्षमता को हटाने के लिए।

सामान्य अध्ययन – III

प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन

मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य (PMNCH) के लिए साझेदारी

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 29 सितंबर को आयोजित अकॉऊटेबिलीटी ब्रेकफास्ट 2020, कोविड–19 संकट के दौरान महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक जवाबदेही हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- इस आयोजन की मेजबानी द पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ (PMNCH), व्हाइट रिबन एलायंस (WRA) और एवरी वुमन हर चाइल्ड (EWEC) ने की थी।
- घटना हाल ही में 'लाईव्स इन द बैलेंस' कोविड–19 शिखर सम्मेलन के परिणामों पर बनी थी।
- अकॉऊटेबिलीटी ब्रेकफास्ट महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए कार्रवाई में बात करना है।

कोविड–19 महामारी के दौरान भारत सरकार की पहल –

- सरकार की आवश्यक सेवाओं के लिए इनकार ना करने की नीति, जैसे – प्रसूति, बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCAH), तपेदिक, कीमोथेरेपी, डायलिसिस और बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवा, कोविड स्थिति के बावजूद।
- सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में कोविड के लिए मुफ्त परीक्षण और उपचार और आयुष्मान भारत – पीएम जेएवाय बीमा पैकेज के तहत कवर की गई चिकित्सा शर्तों में कोविड का समावेश।
- सरकार अब गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं को सेवा से वंचित करने के लिए एक ज़ीरोटोलरेंस दृष्टिकोण का पालन कर रही है।
- 'पिछले वर्ष' 'सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)' पहल भी शुरू की गई थी।
- महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्रथाओं, जन्म साथी की पसंद, रेफरल परिवहन की पहचान और पोस्ट–मार्टम गर्भनिरोधक के आसपास सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए सरकार पूरे प्रसव और प्रसव के दौरान कई संपर्क बिंदुओं का उपयोग करने की कोशिश कर रही है।
- कुशल जन्म देखभाल के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम, 'भारत में पर्याप्त संख्या में नर्स चिकित्सकों को उपलब्ध करा रहा है'।
- मातृ और बाल स्वास्थ्य में सुधार और उनका अस्तित्व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केंद्रीय है। SDG लक्ष्य 3 में मातृ, नवजात और बाल मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान देना भी शामिल है।

प्रजनन मातृ नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCAH + A)

- इसे मातृ और बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रमुख हस्तक्षेपों को प्रभावित करने के लिए 2013 में शुरू किया गया था।
- RMNCH + एक रणनीति भारत में बाल अस्तित्व में सुधार के लिए जीवनचक्र में कवरेज बढ़ाने के लिए विषयगत क्षेत्रों में विभिन्न हस्तक्षेपों के बीच संबंधों को बढ़ावा देती है। रणनीति के भीतर 'प्लस' निम्न मुद्दों पर केंद्रित है –
  – समग्र रणनीति के भीतर किशोरावस्था को एक अलग जीवन स्तर के रूप में शामिल करना।
  – मातृ और बाल स्वास्थ्य को प्रजनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, किशोर स्वास्थ्य, एचआईवी, लिंग और पूर्व धारणा और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों जैसे अन्य घटकों से जोड़ना।
  – घर और समुदाय–आधारित सेवाओं को सुविधा–आधारित सेवाओं से जोड़ना।
- स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के विभिन्न स्तरों के बीच एक सतत देखभाल मार्ग बनाने के लिए, और समग्र परिणामों और प्रभाव के संदर्भ में एक योज्य प्रभाव लाने के लिए बीच–बीच में लिंकेज, रेफरल और काउंटर–रेफरल सुनिश्चित करना।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)

- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, जिसे लोकप्रिय रूप से सुरक्षीत मातृवंश (SUM) के रूप में जाना जाता है।
- यह मातृ और नवजात स्वास्थ्य सेवाओं की सुनिश्चित डिलीवरी पर केंद्रित है, जिसमें मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की व्यापक पहुंच है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर जाने वाली सभी गर्भवती महिलाएं/नवजात शिशु सुमन पहल के तहत दी जाने वाली मुफ्त सेवाओं के हकदार हैं।
- ग्लोबल स्ट्रैटेजी के तीन ओवररचिंग उद्देश्य जीवित, थ्राइव और ट्रांसफॉर्म हैं।

कट क्यू वायरस

समाचार –

- एक अध्ययन में, वैज्ञानिकों ने दो मानव सीरम नमूनों में कैट क्यू वायरस (CQV) के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति का उल्लेख किया है।

अध्ययन के बारे में –

- चीन में क्यूलेक्स मच्छरों और वियतनाम में सूअरों में कैट क्यू वायरस की उपस्थिति काफी हद तक बताई गई है।
- अध्ययन के लिए, 2014–2017 के दौरान तीव्र बुखार संबंधी बीमारी दिखाने वाले 1020 मानव सीरम नमूने एकत्र किए गए थे। इन नमूनों में से, बहुमत (806) कर्नाटक से एकत्र किए गए, इसके बाद महाराष्ट्र (116), केरल (51), मध्य प्रदेश (20) और गुजरात (27) शामिल हैं।
- हालांकि, इन सभी नमूनों को उसी समय में कोविड परीक्षण के अधीन होने पर CQV के लिए नकारात्मक पाया गया था।
- हालांकि, एंटीबॉडी सकारात्मकता को दो नमूनों में दर्ज किया गया था जो एंटीबॉडी की उपस्थिति के लिए परीक्षण किए गए थे। ये दोनों नमूने 2014 और 2017 में कर्नाटक से लिए गए थे।

यह अध्ययन क्यों किया गया?

- यह अध्ययन, भारत में क्यूलेक्स मच्छरों की इसी तरह की प्रजातियों के प्रसार द्वारा प्रेरित CQV के लिए नैदानिक परीक्षण विकसित करने के लिए किया गया था।

कैट क्यू वायरस क्या है?

- CQV के लिए, घरेलू सूअरों को प्राथमिक स्तनधारी मेजबान माना जाता है।
- वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी चीन में स्थानीय स्तर पर सूअर में दर्ज की गई हैं, जो इंगित करता है कि वायरस ने स्थानीय क्षेत्र में एक 'प्राकृतिक चक्र' का गठन किया है और इपके मच्छरों के माध्यम से सूअरों और अन्य जानवरों की आबादी में फैलने की क्षमता है।
- CQV सिम्बु सेरोग्रुप से संबंधित है तथा दोनों मनुष्यों और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन प्रजातियों को संक्रमित करता है।
- उत्तरी वियतनाम में अर्बोवायरस गतिविधि की निगरानी के दौरान मच्छरों से इसे 2004 में पहली बार अलग किया गया था।

इंसान कैसे संक्रमित हो सकत है?

- मच्छरों के माध्यम से मनुष्य संक्रमित हो सकता है।
- अन्य वायरस जो कि CQV के समान जीनस के हैं और मच्छरों के माध्यम से समान रूप से प्रेषित होते हैं, में कैशे वैली वायरस शामिल होता है जो मेनिन्जाइटिस का कारण बन सकता है, ला क्रॉसे वायरस जो कि पीडियाट्रिक एन्सेफलाइटिस का कारण बन सकता है, जेमिसन कैन्यन वायरस जो जैमस्टोन कैन्यन इन्सेफेलाइटिस और ग्वारो वायरस का कारण बनता है। बुखार की बीमारी का कारण बनता है।

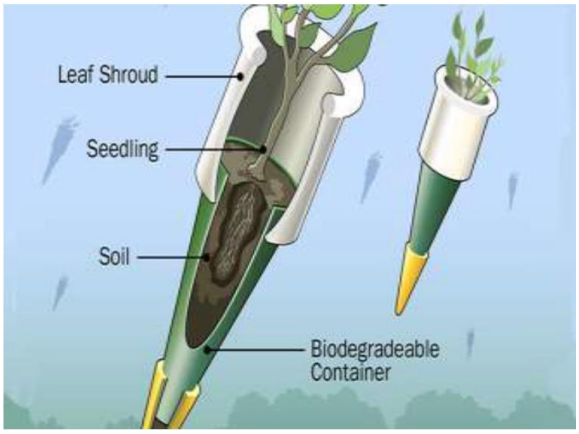

एरियल सीडिंग

समाचार –

- भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में एरियल सीडिंग करने के लिए ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी) के साथ भागीदारी की है।
- इस पहल का उद्देश्य विशाखापत्तनम और उसके आस–पास के हरित आवरण को बढ़ाना है।
- मिट्टी के कटाव, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाने के लिए यह पहल की गई है।

विवरण –

- 2 टन सीड बॉल के साथ दो UH3H हेलीकॉप्टर ने एरियल सीडिंग की।
- नौसेना के हेलीकॉप्टर कुल 50,000 बीज वाली गेंदों जिनका वजन लगभग 6.25 टन है जीवीएमसी द्वारा द्वारा पहचाने गए 5 स्थानों पर गिराएंगे।

एरियल सीडिंग क्या है?

- एरियल सीडिंग वृक्षारोपण की एक तकनीक है जिसमें बीज के गोले – मिट्टी, खाद, चारे और अन्य घटकों के मिश्रण से ढंके हुए बीज – हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन सहित हवाई उपकरणों का उपयोग करके जमीन पर छिड़के जाते है।

यह तकनीक कैसे काम करती है?

- मिट्टी या खाद, चारे और अन्य सामग्री के लेप (जो बीजों को हवा में फैलने के बजाय जमीन पर गिरने के लिए आवश्यक वजन प्रदान करता है) की मदद से जमीन पर गिरने वाले ड्रोन, सीड्स बॉल या सीड के छिलके को एक लक्षित क्षेत्र में फैलाया जाता है।

- इन छर्रों को तब अंकुरित किया जाएगा जब पर्याप्त वर्षा होती है, उनके भीतर मौजूद पोषक तत्व प्रारंभिक विकास में मदद करते हैं।

इस तकनीक के क्या फायदे हैं?

- कम से कम समय में एक बड़े क्षेत्र का कुशल कवरेज।
- एरियल सीडिंग उन क्षेत्रों में बीजारोपण की सुविधा प्रदान करता है जो अन्यथा पारंपरिक तरीकों से बीज के लिए असंभव होगा, जैसे कि भूमि जो कि गैर–क्रीक तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन है या जमीन की स्थिति बहुत अधिक गीली हो रही है।
- जब मौजूदा फसलें पहले से ही लगाई जाती हैं तो एरियल सीडिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- बीज के अंकुरण और वृद्धि की प्रक्रिया ऐसी होती है कि इसके छंटने के बाद इस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती – यही कारण है कि बीज छर्रों को रोपण के 'आग और भूल' तरीके के रूप में जाना जाता है।
- वे मिट्टी में जुताई और खुदाई की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं और बीजों को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे पहले से ही मिट्टी, पोषक तत्वों और सूक्ष्मजीवों से घिरे होते हैं।
- मिश्रण में अन्य वस्तुओं के साथ इन छर्रों का मिट्टी का खोल पक्षियों, चींटियों और चूहों से भी बचाता है।

Xoo 'Xanthomonas oryzaepvA Oryzae'

समाचार –

- सेंटर फॉर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CPMB) के वैज्ञानिकों ने उस तंत्र को उजागर किया है जिसके द्वारा Xoo (Xanthomonas oryzaepvA Oryzae) नामक जीवाणु होता है जो एक गंभीर जीवाणु का कारण बनता है।
- चावल में पत्ती ब्लाइट रोग, चावल के पौधे के साथ परस्पर क्रिया करता है और रोग पैदा करता है।

विवरण –

- अनुसंधान समूह उन कुछ अणुओं की पहचान करने और विकसित करने के लिए काम कर रहा है जो Xoo जीवाणु से या संक्रमित चावल सेल की दीवारों से प्राप्त होते हैं।
- टीम नई रोग नियंत्रण रणनीतियों का विकास कर रही है जो वे टीके के रूप में उपयोग कर सकती हैं जो चावल की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं और प्रदान करते हैं।
- रोगजनकों द्वारा बाद के संक्रमण से चावल के पौधों के लिए प्रतिरोध, सेल्यूज के साथ चावल का उपचार, Xoo द्वारा स्रावित एक कोशिका भित्ति एंजाइम चावल प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है और Xoo द्वारा चावल को बाद के संक्रमण से बचाता है।
- सेल्युलस प्रोटीन में एक विशिष्ट वैक्सीन की विशेषताएं होती हैं क्योंकि यह चावल की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का एक शक्तिशाली गुणकारी है। इस प्रोटीन के साथ चावल के पौधों का पूर्व उपचार, बाद के Xoo संक्रमण के खिलाफ चावल को प्रतिरोध प्रदान करता है।

Xanthomonas oryzaepvA oryzae / Xoo संक्रमण

- Xanthomonas oryzae pvA oryzae एक बैक्टीरियल पाथोवर है जो चावल, अन्य घास और सेज में गंभीर बिमारी का कारण बनता है।
- जीनस जैंथोमोनस, जिसमें ज्यादातर फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया शामिल हैं, Xanthomonadaceae परिवार के एक सदस्य है।
- इसे बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है।
- चावल के बैक्टीरियल ब्लाइट में महामारी की संभावना अधिक होती है और यह विशेष रूप से एशिया में समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में उच्च उपज देने वाली खेती के लिए विनाशकारी है।
- सेंटर फॉर प्लांट आणविक जीवविज्ञान, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
- सीपीएमबी भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से प्रारंभिक वित्तीय सहायता के साथ देश में निर्मित 7 केंद्रों में से एक है।
- वर्तमान में यह प्लांट आणविक जीवविज्ञान में देश के प्रमुख केंद्रों में से एक है।

अनुसंधान जनादेश –

- कृषि उपयोगी लक्षणों के लिए जीन का अलगाव।
- ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन।
- औषधीय पौधों से औषधीय महत्वपूर्ण यौगिकों का उत्पादन।
- जटिल लक्षणों को संबोधित करने के लिए जैव सूचना विज्ञान उपकरणों के जीनोम विश्लेषण और विकास।

मिशन –

- फसल पौधों की आनुवंशिक वृद्धि के लिए आणविक तंत्र को समझने में उपकरणों का अनुप्रयोग।
- आणविक जीवविज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में मानव संसाधन का विकास।
- उत्पाद / प्रक्रिया विकास के लिए उद्योग लिंकेज की स्थापना।

ट्रैक्टर के लिए उत्सर्जन मानदंड

समाचार –

- केंद्र सरकार ने निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंडों की प्रयोज्यता के लिए समय सीमा अगले साल तक बढ़ा दी है।

विवरण –

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंड जारी किए हैं जो अब अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 से लागू होंगे।
- ये मानदंड अक्टूबर से लागू होने थे।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (CMVR) में संशोधन को अधिसूचित किया है, जो इस वर्ष अक्टूबर से अगले वर्ष अक्टूबर तक ट्रैक्टर (TREM स्टेज– IV) के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने के लिए प्रयोज्यता तिथि को समाप्त कर रहा है।
- निर्माण उपकरण वाहनों के लिए, उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण की प्रयोज्यता 1 अप्रैल, 2021 से लागू होने का प्रस्ताव है।
- संशोधन अन्य मोटर वाहनों के उत्सर्जन मानदंडों के बीच भ्रम से बचने का भी प्रयास करता है, जिसमें बीएस के मानदंड हैं और जो कृषि मशीनरी, निर्माण उपकरण वाहनों और ऐसे अन्य उपकरणों के लिए हैं।

- कृषि संशोधन में कृषि मशीनरी (कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और संयुक्त हार्वेस्टर) और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग–अलग उत्सर्जन मानदंड शामिल हैं।
- कृषि ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों के लिए भारत स्टेज (CEV / TREM) IV और भारत स्टेज (CEV / TREM) V से TREM Stage – IV और TREM LVst – V से उत्सर्जन मानदंडों के नामकरण में भी बदलाव है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 –

- अधिनियम 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ। इसने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 को प्रतिस्थापित किया, जिसने पहले इस तरह के अधिनियमन मोटर वाहन अधिनियम, 1914 को प्रतिस्थापित किया।
- अधिनियम में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधन किया गया है।
- अधिनियम में ड्राइवर/कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों पर नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान, यातायात विनियमन, बीमा, देयता, अपराध और दंड, आदि के बारे में विधायी प्रावधान दिए गए हैं।
- अधिनियम के विधायी प्रावधानों का प्रयोग करने के लिए, भारत सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 बनाया।

भारत चरण उत्सर्जन मानक –

- बीएसईएस मोटर वाहन सहित संपीड़न इग्निशन इंजन और स्पार्क–इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन के लिए मानक और समय–सीमा निर्धारित की जाती है।
- यूरोपीय नियमों के आधार पर मानकों को पहली बार 2000 में पेश किया गया था।

बढ़त खराब ऋण

समाचार –

- फिच रेटिंग्स के अनुसार, कोविड–19 महामारी के आर्थिक पतन के कारण खराब ऋण और राइट–ऑफ बढ़ने के कारण भारतीय बैंकों को निकट अवधि में कठिन परिचालन वातावरण का सामना करना पड़ सकता है।
- यदि पुनर्गठन ऋण अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो बैंकों को खराब ऋणों की संख्या अधिक हो सकती है।

फिच रेटिंग्स –

- फिच रेटिंग वैश्विक पूंजी बाजारों के लिए क्रेडिट रेटिंग, कमेंट्री और अनुसंधान का एक अग्रणी प्रदाता है।
- यह एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह 'बिग थ्री क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों' में से एक है, अन्य दो मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है।
- यह 1975 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा नामित तीन राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सांख्यिकीय रेटिंग संगठनों में से एक है।

प्रमुख निष्कर्ष –

- 85 केंद्रीय बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय बैंकों ने वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2015 तक लगभग 85 बिलियन डॉलर की राशि लिखी, जिसमें से राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों ने लगभग 80% योगदान दिया।
- आर्थिक तनाव गहरा और अधिक व्यापक आधारित होना तय है।
- निष्पादन जोखिम अधिक रहता है।
- बैंकों को दिसंबर तक छोटे खुदरा ऋण और सूक्ष्म उद्यमों और एसएमई को ऋण सहित एक संकल्प योजना की पहचान और सहमति की आवश्यकता है।
- अधिकारियों को उम्मीद है कि जून 2021 तक बैंक संकल्प योजना लागू करेंगे।

उठाए गए कदम –

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को महामारी से प्रभावित ऋणों का एकमुश्त पुनर्गठन अभ्यास करने की अनुमति दी। यह अभ्यास खराब ऋण मान्यता और प्रावधान के संदर्भ में राहत प्रदान करेगा।
- सुरक्षोपायों का निर्माण RBI द्वारा सख्त समयसीमा के अनुसार किया जाता है, जो बतवतम 1,500 करोड़ से परे ऋण की विशेषज्ञ समिति द्वारा दंडात्मक प्रावधान और सख्त निगरानी प्रदान करता है।

खराब ऋण –

- एक स्ट्रेस्ड लोन (खराब ऋण) वह होता है जो प्रदर्शन नहीं कर रहा होता है (उदाहरण, 90 दिनों या उससे अधिक की गंभीर डील–डौल वाला ऋण) या संशोधित किया गया लोन (जैसे, पुनर्भुगतान अवधि, ब्याज दर या अन्य ऋण शर्तों में बदलाव)।
- ये वित्तीय संकट के संकेत हैं और डिफॉल्ट की संभावना को बढ़ाते हैं।
- एक तनावग्रस्त ऋण को चुकाए जाने की संभावना कम होती है।
- 90 दिनों की अवधि से पहले, उन्हें 'स्ट्रेस्ड एसेट्स' कहा जाता है।
- स्ट्रेस्ड एसेट्स = एनपीए. रिस्ट्रिक्टेड लोन. रिटेन ऑफ एसेट्स।

तनावग्रस्त आस्तियों के प्रकार –

- **उप–मानक परिसंपत्तियां** – यदि उधारकर्ता किश्त चुकाने में विफल रहता है, तो 90 दिनों के लिए मूलधन या मूलधन पर ब्याज एनपीए हो जाता है और इसे विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) कहा जाता है। यदि यह 12 महीने से कम या इसके बराबर अवधि के लिए एसएमए रहता है, तो इसे सबस्टैंडर्ड एसेट्स कहा जाता है।
- **संदिग्ध संपत्ति** – यदि उप–मानक संपत्ति 12 महीने या उससे अधिक के लिए बनी रहती है, तो इसे संदिग्ध संपत्ति कहा जाएगा।
- **लॉस्ट एसेट्स** – तीन साल से अधिक समय तक घटिया रहने के बाद भी अगर कर्ज नहीं चुकाया जाता है तो इसे लॉस एसेट कहा जाएगा।
- **लिखित संपत्ति** – लिखित संपत्ति वे हैं जिन पर बैंक या ऋणदाता उस पर उधारकर्ता का बकाया नहीं मानते हैं।

अनवरत जैविक प्रदूषक

समाचार –

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत लगातार कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) में सूचीबद्ध सात (7) रसायनों के संरक्षण को मंजूरी दी है।
- कैबिनेट ने अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत केंद्रीय विदेश मंत्री (एमईए) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमईएफसीसी) के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत रसायनों के अनुसमर्थन के लिए पहले से ही प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए घरेलू विनियमों के तहत विनियमित पीओपी के संबंध में प्रत्यायोजित किया।

विवरण –

- पीओपी की पहचान ऐसे रासायनिक पदार्थों से होती है जो पर्यावरण में बने रहते हैं, जीवित जीवों में जैव–संचय करते हैं, मानव स्वास्थ्य/पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण परिवहन (LRET) की संपत्ति रखते हैं।
- पीओपी के संपर्क में आने से कैंसर हो सकता है, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान, प्रतिरक्षा प्रणाली की बीमारियां, प्रजनन संबंधी विकार और सामान्य शिशु और बाल विकास में हस्तक्षेप हो सकता है।
- सदस्य देशों के बीच गहन वैज्ञानिक अनुसंधान, विचार–विमर्श और वार्ता के बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन के लिए विभिन्न अनुलग्नकों में पीओपी सूचीबद्ध हैं।
- रसायन विनियमन ने सात रसायनों के निर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात को प्रतिबंधित किया है – क्लोर्डेकोन, हेक्साब्रोमोबिपेनिल, हेक्सब्रोमोडिफेनिल ईथर और हेप्टैब्रोमोडिफेनलेथर (वाणिज्यिक ऑक्टा–बीडीई), टेट्राब्रोमोडिफेनिल ईथर और पेंटाब्रोमोडिफेनिल ईथर (वाणिज्यिक पेंटा–बीडीई), पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्सब्रोमोसायक्लोडोडेकेन, हेक्साक्लोरोबुटैडीन

स्टॉकहोम सम्मेलन –

- स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है, जिसे 2001 में हस्ताक्षरित किया गया और मई 2004 से प्रभावी किया गया।
- इसका उद्देश्य लगातार जैविक प्रदूषकों (पीओपी) के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना या प्रतिबंधित करना है।
- भारत ने 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि की थी।

प्रदूषण से संबंधित सम्मेलन और अन्य चल रही अन्य वार्ताएँ

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पहले सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशन
- लंबी दूरी की ट्रांसबाउंड्री वायु प्रदूषण पर सम्मेलन (सीएलआरटीएपी)
- खतरनाक कचरे के ट्रांसबाउंडरी आंदोलनों के नियंत्रण और उनके निपटान पर बातचीत के आधार पर बेसल कन्वेंशन

चल रही अन्य वार्ताएँ

- पारे (मरक्यूरी) पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के लिए अंतर सरकारी समझौता समिति के कार्य
  – को प्रभावी ढंग से पार सरकारी पैमाने से संबोधित किया जा सकता है।
- पारा के मानकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित वैश्विक लक्ष्य होना।
- सभी सरकारों को समान पंक्तियों के साथ समस्या से निपटना चाहिए।
- और पारा उत्सर्जन उपयोग पर इमारतों के लिए क्षमता स्तर को लागू करना।
- रासायनिक सुरक्षा पर अंतर सरकारी फोरम (IFCS)
- अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन (SAICM) के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण

अनवरत जैविक प्रदूषक

- लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी) / हमेशा के लिए रसायन (एफसी) कार्बनिक यौगिक हैं जो रासायनिक, जैविक और फोटोलिटिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पर्यावरणीय गिरावट के प्रतिरोधी हैं।
- उनकी दृढ़ता के कारण, पीओपी बायोकेम्युलेट मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों डालते है।
- कई पीओपी वर्तमान में कीटनाशक, सॉल्वैंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, और औद्योगिक रसायनों के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
- हालांकि कुछ पीओपी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं (जैसे ज्वालामुखियों से), अधिकांश कुल संश्लेषण के माध्यम से मानव निर्मित होते हैं।

आगे की राह –

- पीओपी का संरक्षण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के संबंध में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह नियंत्रण उपायों को लागू करने, अनजाने में उत्पादित रसायनों के लिए कार्य योजनाओं को विकसित करने और कार्यान्वित करने, रसायनों के भंडार के आविष्कारों को विकसित करने और समीक्षा करने के साथ–साथ अपनी राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना (एनआईपी) को अद्यतन करने के लिए पीओपी पर सरकार के संकल्प को भी इंगित करता है।
- अनुसमर्थन प्रक्रिया भारत को एनआईपी को अद्यतन करने में वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम करेगी।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

समाचार –

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मीत) ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत 16 आवेदकों को मंजूरी दी है।

विवरण –

- इस योजना के तहत स्वीकृत 16 कंपनियों से अगले पांच वर्षों में कुल 10.5 लाख करोड़ का उत्पादन होने की उम्मीद है।
- अनुमोदित घरेलू कंपनियों ने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन प्रस्तावित किया है, जबकि निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयव खंड के तहत अनुमोदित कंपनियों ने पीएलआई योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन प्रस्तावित किया है।
- अगले पाँच वर्षों में 10.5 लाख करोड़ रुपये के कुल उत्पादन में से लगभग 60 प्रतिशत निर्यात द्वारा योगदान दिया जाएगा।
- घरेलू वैल्यू एडिशन मौजूदा 15–20 प्रतिशत से बढ़कर फोन के मामले में 35–40 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए 45–50 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
- यह योजना भारत में निर्मित वस्तुओं के आधार वर्ष में वृद्धि की बिक्री पर 4 से 6 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान करेगी और आधार वर्ष (FY20) के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंडों के तहत कवर किया जाएगा।

कारण –

- घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में एक स्तर के खेल के प्रति–प्रतिस्पर्धा वाले देशों की कमी है।
- इस क्षेत्र में लगभग 5% से 11% की अयोग्यता होती है –
  – पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का अभाव
  – घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद की कमी
  – वित्त की उच्च लागत
  – गुणवत्ता शक्ति की अपर्याप्त उपलब्धता
  – लिमिटेड डिजाइन क्षमताओं और उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित
  – कौशल विकास में अपर्याप्तता

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की योजनाएं –

- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थान देने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स (एनपीई) 2019 पर राष्ट्रीय नीति की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, तीन योजनाएं जैसे उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), संवर्धन के लिए योजना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स (स्पेश) और मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्कीम (EMC 2.0) के विनिर्माण को अधिसूचित किया गया है।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) –

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ATMP इकाइयों सहित इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखती है।

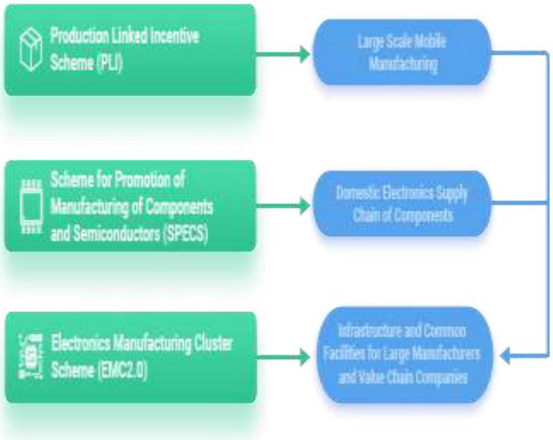

- INR 40,951 करोड़ तक के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन 5 वर्षों की अवधि में प्रदान किए जाएंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालक के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना।
- स्पेश का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के लिए विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।
- योजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के लक्ष्य निर्माण से घरेलू मांग को पूरा करने, मूल्यवर्धन बढ़ाने और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- आठ वर्ष की अवधि में इस योजना के तहत INR 3,285 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना (EMC 2.0)

- EMC 2.0 योजना इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए बुनियादी ढांचे के आधार को मजबूत करने और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला को गहरा करने का प्रयास करती है।
- कॉमन फैसिलिटी सेंटर, रेडी बिल्ट फैक्ट्री, शेड/प्लग एंड प्ले सुविधाओं जैसी उद्योग–विशिष्ट सुविधाओं का विकास न केवल आपूर्ति श्रृंखला जवाबदेही को मजबूत करेगा और आपूर्तिकर्ताओं के समेकन को बढ़ावा देगा बल्कि समय–समय पर बाजार में कमी और कम रसद लागत को भी कम करेगा।
- EMC 2.0, गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं के लिए सामान्य सुविधाओं और सुविधाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- INR 3,762 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन राशि 8 वर्ष की अवधि में वितरित की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 पर राष्ट्रीय नीति –

- इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 (NPE 2019) पर राष्ट्रीय नीति की दृष्टि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थान देने के लिए है ताकि देश में मुख्य घटकों को विकसित करने और उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम वातावरण बनाने के लिए क्षमताओं को प्रोत्साहित किया जा सके।

रूद्रम

समाचार –

- भारत परीक्षण ने रुद्रम नामक नई पीढ़ी की विकिरण–रोधी मिसाइल दागी। दुश्मन के रडार को मारने के लिए मिसाइल तैयार की गई है।
- संस्कृत नाम रुद्रम को परंपरा को ध्यान में रखते हुए दिया गया था, क्योंकि इसमें एआरएम (विकिरण रोधी मिसाइल के लिए संक्षिप्त नाम) अक्षर शामिल हैं और संस्कृत में शब्द का एक अर्थ 'दुखों का निवारण' है।

एंटी–रेडिएशन मिसाइल क्या है?

- एंटी–रेडिएशन मिसाइलों को विरोधी की रडार, संचार संपत्तियों और अन्य रेडियो आवृत्ति स्रोतों का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आमतौर पर उनकी वायु रक्षा प्रणालियों का हिस्सा हैं।
- ऐसे मिसाइल के नेविगेशन तंत्र में एक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली शामिल है – एक कम्प्यूटरीकृत तंत्र जो ऑब्जेक्ट की अपनी स्थिति में परिवर्तन का उपयोग करता है – जीपीएस के साथ युग्मित, जो उपग्रह आधारित है।
- मार्गदर्शन के लिए, इसमें एक 'निष्क्रिय होमिंग हेड' है – एक ऐसी प्रणाली जो प्रोग्राम के रूप में आवृत्तियों के एक विस्तृत बैंड पर लक्ष्य (रेडियो फ्रीक्वेंसी स्रोतों) को पहचान, वर्गीकृत और संलग्न कर सकती है।
- एक बार रुद्रम मिसाइल के निशाने पर होने के बाद, यह विकिरण के स्रोत को बीच में बंद करने पर भी सटीक रूप से प्रहार करने में सक्षम है।
- मिसाइल में फाइटर जेट से लॉन्च पैरामीटर्स के आधार पर 100 किमी से अधिक की ऑपरेशनल रेंज है।

रुद्रम का विकास कैसे हुआ?

- रुद्रम एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- डीआरडीओ ने लगभग आठ साल पहले इस प्रकार की एंटीरेड मिसाइलों का विकास शुरू किया था और फाइटर जेट्स के साथ इसका एकीकरण हुआ है।
- डीआरडीओ की विभिन्न सुविधाओं और आईएएफ और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के निर्माण का एक सहयोगी प्रयास रहा है।
- जबकि प्रणाली का परीक्षण सुखोई–30 एमकेआई से किया गया है, इसे अन्य लड़ाकू जेट विमानों से भी लॉन्च करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

प्रभाव आधारित चक्रवाती चेतावनी प्रणाली

समाचार –

- भारतीय मौसम विभाग जल्द ही एक गतिशील प्रभाव–आधारित चक्रवात चेतावनी प्रणाली शुरू करेगा।

विवरण –

- यह प्रतिवर्ष भारतीय तटों पर आने वाले चक्रवातों के कारण आर्थिक नुकसान और संपत्ति को नुकसान को कम करने में मदद करेगा।
- इस चक्रवात सीजन (अक्टूबर–दिसंबर) से गतिशील, प्रभाव–आधारित चक्रवात चेतावनी चालू हो जाएगी।

- नई प्रणाली में स्थानीय आबादी, बुनियादी ढांचे, बस्तियों, भूमि उपयोग और अन्य संबंधित तत्वों में फैक्टरिंग के लिए स्थान या जिले के अनुरूप चेतावनी तंत्र होंगे।
- सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियां इस तंत्र के तहत कार्टोग्राफिक, भूगर्भीय और जिलेवार जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों का व्यापक उपयोग करेंगी।

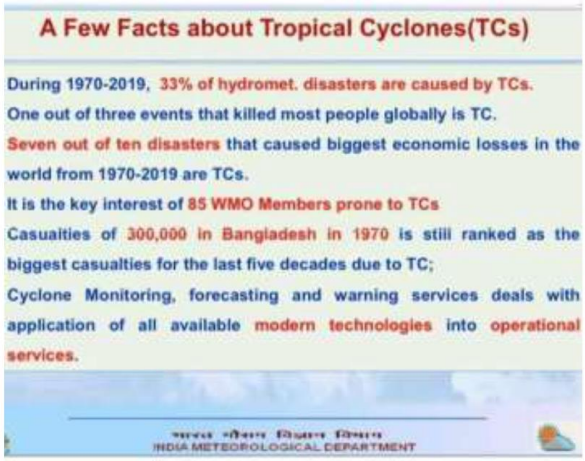

अन्य पहल –

- आईएमडी चक्रवात के मौसम के दौरान जीआईएस प्लेटफॉर्म पर 'पर्यवेक्षित और पूर्वानुमान चक्रवात ट्रैक और तीव्रता का एक इंटरैक्टिव प्रदर्शन प्रणाली' भी शुरू करेगा।

- नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने इस बीच, एक प्रोजेक्ट लिया – जिसे नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट (NCRMP) कहा जाता है – IMD और तटीय राज्यों की सरकारों के सहयोग से एक वेब–आधारित डायनामिक कंपोजिट रिस्क एटलस (वेब–DCRA) विकसित करना।

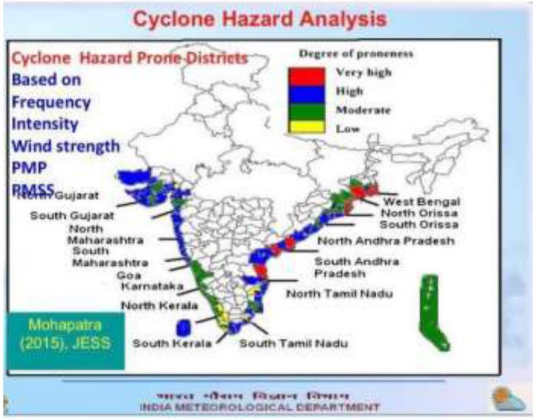

निष्कर्ष

- हाल के वर्षों में बेहतर प्रौद्योगिकी और उपग्रह–निर्देशित डेटा के उपयोग में वृद्धि के साथ, आईएमडी ने चक्रवातों का बेहतर पूर्वानुमान करने और समय पर चेतावनी जारी करने में कामयाबी हासिल की है।

बैंगलोर रोज प्याज और कृष्णपुरम प्याज

समाचार –

- सरकार 31 मार्च, 2021 तक बैंगलोर गुलाब प्याज और कृष्णपुरम प्याज के निर्यात की अनुमति देती है।
- बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई और श्रीलंका भारतीय प्याज के शीर्ष आयातक हैं।

पृष्ठभूमि –

- घरेलू बाजार में उच्च कीमतों और प्याज की कमी के मद्देनजर सरकार ने कटे हुए एवं पाउडर के रूप में प्याज को छोड़कर प्याज की सभी किस्मों के निर्यात (सितंबर 2019) पर प्रतिबंधित लगा दिया था।
- इसके निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 850 डॉलर प्रति टन निर्धारित किया गया था।
- यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रमुख राज्यों में बाढ़ के कारण घरेलू बाजार में कीमतों को नीचे लाने में मदद करेगा।
- इस वर्ष मार्च में MEP को हटा दिया गया था और प्याज को निर्यात के लिए स्वतंत्र किया गया था।

विवरण –

- कृष्णापुरम प्याज के लिए, निर्यातकों को आंध्र प्रदेश के बागवानी कडप्पा से एक प्रमाण पत्र लेना होगा।
- बैंगलोर रोज प्याज के लिए, निर्यातकों को कर्नाटक के बागवानी आयुक्त से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

बेंगलूरु में उगाया जाने वाला प्याज –

- बैंगलोर में और कर्नाटक में बैंगलोर के आसपास उगाया जाने वाला प्याज उगता है। इसे 2015 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला।
- गुलाब प्याज की खेती भारत में किसी अन्य स्थान पर नहीं की जाती है।
- बैंगलोर गुलाब का प्याज भारत में शायद ही कभी उपयोग किया जाता है, लेकिन मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अन्य देशों में बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है।
- इन प्याज की तीखी संपत्ति उन्हें अचार में इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त बनाती है।

कृष्णापुरम प्याज –

- यह एक किस्म है जो विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उगाई जाती है।
- स्पाम यह किस्म विशेष रूप से हांगकांग, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में निर्यात उद्देश्यों के लिए उगाई जाती है, और भारत में उनके छोटे आकार और तीखेपन के कारण उपयोग नहीं की जाती है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)

- DGFT भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति या एक्जिम नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- DGFT भारत में एक सरकारी संगठन है जो देश के भारतीय आयातकों और भारतीय निर्यातकों के लिए एक्जिम दिशानिर्देशों और सिद्धांतों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। 1991 से पहले, आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक (सीसीआई और ई) के रूप में जाना जाता था।
- DGFT राज्य सरकारों और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य सभी विभागों के साथ समन्वय में अपने कार्य करता है।

DGFT के कार्य

- देश के डीजीएफटी क्षेत्रीय कार्यालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और दिशानिर्देशों को लागू करके भारत की एक्जिम नीति या विदेश व्यापार नीति को लागू करता है।
- भारतीय निर्यातक और आयातकों के लिए आयातक आयातक कोड संख्या प्रदान करना। IEC नंबर भारत में आयात और निर्यात के उद्देश्य से व्यापारियों या निर्माताओं द्वारा आवश्यक एक 10–अंकीय कोड है।
- DGFT IEC कोड्स आयात निर्यात व्यापार संचालन को पूरा करने के लिए अनिवार्य हैं और कंपनियों को भारत में उनके आयात/निर्यात, भारतीय सीमा शुल्क, निर्यात संवर्धन परिषद आदि पर लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।
- DGFT भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय संधियों के अनुसार भारत से या भारत से सटे देशों में माल के पारगमन की अनुमति या विनियमन करता है।
- पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना।
- निर्यात नीति अनुसूची 2 में मुफ्त निर्यात की अनुमति देना।
- डीजीपीटी भी डीईपीबी दरों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- मानक इनपुट–आउटपुट मानदंडों को सेट करना भी DGFT द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- ITC–HS कोड्स में नए कोड के किसी भी परिवर्तन या सूत्रीकरण या परिवर्धन को भी DGFT (विदेश व्यापार महानिदेशालय) द्वारा किया जाता है।

न्यूनतम निर्यात मूल्य –

- एमईपी वह मूल्य है जिसके नीचे एक निर्यातक को भारत से वस्तु का निर्यात करने की अनुमति नहीं है।
- देश में बढ़ती घरेलू खुदरा/थोक मूल्य या उत्पादन व्यवधानों को देखते हुए MEP लगाया जाता है। MEP व्यापार के लिए एक तरह का मात्रात्मक प्रतिबंध है।
- एमईपी को छोटी अवधि के लिए लगाए जाने का इरादा है और स्थितियों में बदलाव होने पर इसे हटा दिया जाता है।
- एमईपी को हटाने से किसानों / निर्यातकों को बेहतर और पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है और इससे देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मदद मिलेगी।
- आम तौर पर, MEP थोपना आवश्यक वस्तुओं जैसे आलू, प्याज, चावल, खाद्य तेल आदि तक सीमित है।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

समाचार –

- पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ने हाल ही में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा सरकारों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है।
- कार्य योजना दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीन वर्षों से प्रभावी है।

झलकियाँ –

- सर्दियां आने पर प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका है।
- डीजल जनरेटर (DG) सेट का उपयोग अब दिल्ली और NCR शहरों नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव में नहीं किया जा सकता है।
- एकमात्र अपवाद, आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले DG सेट हैं।
- प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण धूल और औद्योगिक उत्सर्जन के साथ–साथ कचरे के जलने की जाँच के लिए रात की गश्त शुरू करेंगे।
- मैकेनाइज्ड स्वीपिंग और सड़कों पर पानी का लगातार छिड़काव (धूल जमने के लिए) को निर्देशित किया गया है।

GRAP -

- GRAP को 2016 में तैयार किया गया था और 2017 में अधिसूचित किया गया था।
- GRAP केवल एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है।
- जीआरएपी, जिसे पहली बार 2017 में दिल्ली–एनसीआर में लागू किया गया था, में बढ़ती बस और मेट्रो सेवाएं शामिल हैं।
- इस योजना में औद्योगिक, वाहन और दहन उत्सर्जन से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा साल भर की जाने वाली कार्रवाई शामिल नहीं है।
- योजना प्रकृति में वृद्धिशील है – इसलिए, जब वायु की गुणवत्ता 'खराब' से 'बहुत खराब' हो जाती है, तो इसके अनुभागों के तहत सूचीबद्ध उपायों का पालन करना होगा।

- यदि वायु गुणवत्ता गंभीर चरण में पहुंचती है, तो GRAP के तहत प्रतिक्रिया में स्कूलों को बंद करने और ऑड–ईवन रोड–स्पेस राशन योजना को लागू करने जैसे चरम उपाय शामिल हैं।
- जीआरएपी ईपीसीए से अपना अधिकार प्राप्त करता है। ईपीसीए सभी एनसीआर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित करता है, और कॉल किया जाता है कि किन कार्यों को किस शहर में लागू किया जाना है।

महत्व –

- जीआरएपी पूरे दिल्ली–एनसीआर क्षेत्र के लिए एक कदम–दर–कदम योजना बनाने में सफल रहा है, और कई एजेंसियों – सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण, नगर निगम, भारत मौसम विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, और अन्य को इसमें शामिल कर रहा है।
- ईपीसीए और जीआरएपी द्वारा तीन प्रमुख निर्णय बदरपुर में थर्मल पावर प्लांट को बंद करना है, शुरुआत में समय सीमा निर्धारित करने से पहले बीएस–VI ईंधन को दिल्ली लाना, और दिल्ली–एनसीआर में ईंधन के रूप में पेट कोक पर प्रतिबंध।

GRAP के अंर्तगत उठाए गए कदम –

GRAP गंभीर + या आपातकाल
(48 घंटे के लिए, 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पीएम 2.5 से अधिक या 500 माइक्रोन/घन मीटर पीएम 10 से अधिक के तहत)

- दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोकना (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर)
- निर्माण कार्यों को बंद करना
- निजी वाहनों के लिए सम/विषम योजना शुरू करना।
- स्कूलों को बंद करने सहित किसी भी अतिरिक्त कदम का फैसला करने के लिए टास्क फोर्स

गंभीर

(250 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर PM 2.5 से अधिक या 430 माइक्रोग्राम/घन मीटर PM10 से अधिक)

- बंद ईंट भट्टों, गर्म मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर
- कोयले से उत्पादन को कम करने के लिए प्राकृतिक गैस से बिजली उत्पादन को अधिकतम करना
- अंतर दरों के साथ सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करें
- सड़क की लगातार यंत्रीकृत सफाई और पानी का छिड़काव

बहुत खराब

(PM 2.5 121–250 µg/घन मीटर या PM10 351–430 µg/घन मीटर)

- डीजल जनरेटर सेट का उपयोग बंद कराना
- पार्किंग शुल्क को तिगुना या चौगुना करना
- बस और मेट्रो सेवाओं में वृद्धि
- अपार्टमेंट के मालिक को सर्दियों के दौरान इलेक्ट्रिक हीटर प्रदान करके सर्दियों में जलती हुई आग को हतोत्साहित करना।
- श्वसन और हृदय की बिमारी वाले लोगों को बाहर ना निकलने की सलाह देना।

गरीब से मध्यम –

(61–120 µg/घन मीटर PM2.5 या 101–350 µg / घन मीटर PM10)

- कचरा जलाने पर भारी जुर्माना
- ईंट भट्टों और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण नियमों को बंद/लागू करना
- भारी यातायात और पानी के छिड़काव के साथ सड़कों पर मशीनीकृत सफाई।

पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण

- EPCA का नेतृत्व सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के सदस्यों सहित किया जाता है।
- यह 1998 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किया गया था।
- शरीर प्रदूषण की निगरानी करता है, और कई प्रदूषण संबंधी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करता है।

राष्ट्रीय कामधेनु अयोग

समाचार –

- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग (आरकेए) ने दिवाली पर भारत में 11 करोड़ परिवारों में 33 करोड़ 'गोमाता दिया' लगाने के लिए 'कामधेनु दीपावली अभियान' नाम से देशव्यापी अभियान शुरू किया।

विवरण –

- अभियान गाय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देगा और देश में गायों के संरक्षण में मदद करेगा।
- गाय के गोबर पर आधारित दीयों, मोमबत्तियों, धुप, अगरबत्ती, शुभ–लब्ध, स्वस्तिक, दीवार के टुकड़े, सामरानी, हवन समाग्री, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियाँ को बढ़ावा देगा।
- यह पहल अयोध्या में 3 लाख एवं वाराणसी में 1 लाख दियों को जलाने के साथ शुरू की गई।
- इस पहल को मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

महत्व –

- अभिनव उत्पादों को बनाने के लिए गाय के गोबर के उपयोग से हजारों गाय आधारित उद्यमियों और के लिए व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे किसानों।
- गाय–गोबर उत्पादों के उपयोग से स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनेगा।
- गौ–केंद्रित अर्थव्यवस्था भी अपना विनम्र योगदान देकर आत्मानिर्भर भारत लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है।
- चीन निर्मित दीयों को अस्वीकार करने से अभियान मेक इन इंडिया अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा।
- गो–पालक, युवा, महिलाएं, स्वयं सहायता समूह और अन्य हितधारक किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न गाय–पंचगव्य उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने के लिए आरकेए लगातार प्रयास कर रहा है।

तुरंत ध्यान देना क्यों जरूरी है?

- भले ही भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत में औसत दूध की पैदावार दुनिया के औसत का केवल 50% है।

- कम उत्पादकता मुख्य रूप से आनुवंशिक स्टॉक में गिरावट, खराब पोषण और अवैज्ञानिक प्रबंधन के कारण है।
- इस प्रवृत्ति को उलट दिया जाना चाहिए एवं गाय तथा गाय आधारित कृषि एवं गाय आधारित उद्योग के बारे में लोकप्रिय धारणा बनना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब समाज के सामाजिक और आर्थिक कायाकल्प के लिए तुरंत सही किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय कामधेनु अयोग

- सरकार ने आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर पशुपालन को व्यवस्थित करने और नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए और गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध और मवेशियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' का गठन किया है।
- गायों और उनकी संतानों के विकास और संरक्षण के लिए 2019 में इसकी स्थापना की गई थी।
- केंद्र सरकार को गायों की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण, सतत विकास और आनुवांशिक उन्नयन के लिए उपयुक्त कार्यक्रम विकसित करने में मदद करने के लिए अयोग एक उच्च शक्ति वाली स्थायी सर्वोच्च सलाहकार संस्था है।
- आयोग मौजूदा कानूनों, नीतियों की समीक्षा करेगा और साथ ही उन्नत उत्पादन और उत्पादकता के लिए गाय के धन के इष्टतम आर्थिक उपयोग के लिए सुझाव देगा, जिससे उच्च कृषि आय और डेयरी किसानों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता हो सके।
- इसका उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों, किसान उत्पादक कंपनियों और डेयरी उद्योग के साथ–साथ अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय के माध्यम से किसानों के दरवाजे पर उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रबंधन प्रथाओं का प्रसारण करना है।
- राष्ट्रीय कामधेनु आयोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगा।

विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट – आईएमएफ

समाचार –

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को इस वर्ष बड़े पैमाने पर 10.3 प्रतिशत के अनुबंध का अनुमान है।

विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट से विवरण –

- वैश्विक विकास इस साल 4.4 प्रतिशत की वृद्धि और 2021 में वापस 5.2 प्रतिशत तक उछल जाएगा।
- चीन को 8.2 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान है।
- अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2020 में 5.8 प्रतिशत और अगले वर्ष 3.9 प्रतिशत बढ़ने का अनुबंध है।
- 2020 में 1.9 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर दिखाने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में चीन एकमात्र देश है।
- जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान (अनुमानित) ठंडे क्षेत्रों (यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया) के लिए कुछ हद तक छोटे हैं, इनकी संभावना कम है क्योंकि इनमें कई प्रकार के नुकसान शामिल नहीं हैं (समुद्र के स्तर में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं, बुनियादी ढांचे को नुकसान रूस में पर्माफ्रोस्ट के विगलन से) और दुनिया के अन्य हिस्सों में बड़े आर्थिक व्यवधानों से नकारात्मक वैश्विक स्पिलओवर।

भारत –

- भारत में 2021 में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ वापसी करने की संभावना है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ने दूसरी तिमाही में उम्मीद से कहीं अधिक गंभीर अनुबंध किया।
- 2019 में, भारत की विकास दर 4.2 प्रतिशत थी।
- IMF के अनुसार, ग्लोबल वार्मिंग से भारत को सबसे अधिक नुकसान होने की संभावना है।
- भारत के लिए, जलवायु परिवर्तन शमन–निष्क्रियता से शुद्ध लाभ–सकल घरेलू उत्पाद का 21–80 तक 60–80 प्रतिशत तक होगा।

विश्व बैंक –

- हाल ही में, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट के अपने नवीनतम अंक में कहा है कि भारत की जीडीपी इस वित्तीय वर्ष में 9.6% तक अनुबंधित होने की उम्मीद है।
- 25 वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 25% की गिरावट आई थी, जो कि भारत में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही है।
- ब्वदजंपद विश्व बैंक ने कहा कि वायरस के प्रसार और रोकथाम के उपायों ने आपूर्ति और मांग की स्थितियों को बुरी तरह बाधित किया है भारत।

आर्टेमिस अकॉर्ड्स

समाचार –

- नासा ने चन्द्रमा पर जाने संबंधित नए नियम जारी किए हैं, जिसमें चंद्र सतह पर 'नो फाइटिंग या लिटरिंग' और अपोलो 11 के ट्रेंक्युलीटी बेस जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर कोई अतिचार नही करने के आदेश है।
- अंतरिक्ष संस्थान ने 1967 के बाहरी अंतरिक्ष समझौते एवं अन्य समझौतों के आधार पर अपने आर्टेमिस चंद्र लैंडिंग कार्यक्रम के लिए नई गाईडलाईन्स जारी की है।
- अब तक इस पर आठ देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। ये आठ देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात एवं युनाईटेड किंगडम है।
- अमेरिका चांद पर मनुष्य भेजने वाला एकमात्र देश है, जिसने 1969 से 1972 के दौरान 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारा है।

नियमों की सूची

- सभी को शांति से आना चाहिए।
- निजता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और सभी लॉन्च की गई वस्तुओं को पहचानने और पंजीकृत करने की आवश्यकता है।
- सभी सदस्य अंतरिक्ष यात्री आपात स्थितियों से सहमत हैं।
- अंतरिक्ष प्रणाली सार्वभौमिक होनी चाहिए ताकि सभी के उपकरण संगत हों, और वैज्ञानिक डेटा साझा किया जाना चाहिए।
- ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित किया जाना चाहिए, और किसी भी परिणामी अंतरिक्ष कबाड़ को ठीक से निपटाया जाना चाहिए।
- रोवर्स और अन्य अंतरिक्ष यान अपने मिशनों को दूसरों के बहुत करीब होने से ख़तरे में नहीं डाल सकते।

- हिंसा करने वालों को स्थान छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।

आर्टेमिस अकॉर्ड्स

- अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग के लिए 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले आदमी को आर्टीमिस कार्यक्रम के माध्यम से उतारेगा।
- आर्टेमिस एकॉर्डस सिद्धांतों के लिए एक साझा दृष्टिकोण का वर्णन करेगा, जो 1967 के बाहरी अंतरिक्ष संधि में शामिल था, एक सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण बनाने के लिए जो मानवता के लिए अन्वेषण, विज्ञान और व्यावसायिक गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है।

1967 बाहरी अंतरिक्ष संधि –

- बाहरी अंतरिक्ष संधि, औपचारिक रूप से चंद्रमा और अन्य आकाशीय निकायों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को संचालित करने वाली सिद्धांतों की एक संधि है जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का आधार बनाती है।
- 27 जनवरी 1967 को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ ने यह संधि की तथा यह 10 अक्टूबर 1967 को लागू हुई।

बाहरी अंतरिक्ष संधि के मुख्य बिंदु –

- यह अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने पर रोक लगाता है।
- यह केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा और अन्य सभी खगोलीय पिंडों के उपयोग को सीमित करता है।
- यह स्थापित करता है कि अंतरिक्ष सभी देशों द्वारा अन्वेषण और उपयोग के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन कोई भी देश बाहरी अंतरिक्ष या कोई भी खगोलीय पिंड पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है।
- बाहरी अंतरिक्ष संधि अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियों, अंतरिक्ष में सैन्य विनाश, या अंतरिक्ष के हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, इसके साथ ही अंतरिक्ष में बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों की नियुक्ति भी करती है।

AZD7442

समाचार –

- स्वीडिश–ब्रिटिश ड्रग दिग्गज ने हाल ही में कहा था कि यह कोविड–19 उपचार के लिए नवीनतम मानव परीक्षणों में विकसित एक एंटीबॉडी संयोजन था।

यह थेरेपी क्या है?

- AZD7442, दो लंबे समय तक चलने वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (LAAB) का संयोजन है।
- एस्ट्राजेनेका ने लंबे समय तक कोविड–19 संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से अपनी स्वामित्व तकनीक का उपयोग करके इसे विकसित किया।
- एस्ट्राजेनेका के अनुसार, LAABs प्राकृतिक एंटीबॉडी की नकल करते हैं, और LAABs का एक संयोजन रोगनिरोधी एजेंट के रूप में टीकों का 'पूरक' हो सकता है। इसका अर्थ है कि इसका उपयोग या तो उन लोगों पर किया जा सकता है जिनके लिए कोई टीका उचित नहीं है या इसे उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में दिया जा सकता है।

यह कब आया?

- स्वस्थ व्यक्तियों में संयोजन की सुरक्षा और सहनशीलता जैसे पहलुओं का आकलन करने के लिए इस संयोजन के लिए मानव परीक्षणों का पहला चरण अगस्त में शुरू हुआ था।
- अगले कुछ हफ्तों में, AZD7442 अमेरिका में और बाहर की साइटों पर 6,000 से अधिक प्रतिभागियों में चरण 3 नैदानिक परीक्षणों में आगे बढ़ेगा।

क्या यह अन्य प्रायोगिक उपचारों के समान है?

- यह LAAB संयोजन रेजिनरॉन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित प्रायोगिक चिकित्सा के समान है – एक कॉकटेल जिसके द्वारा ट्रम्प की कोविड–19 बिमारी का इलाज किया गया है।
- एली लिली एक और कंपनी है जिसने एक एंटीबॉडी उपचार पर काम किया है।
- रिजेनरॉन और लिली दोनों ने कथित रूप से इन उपचारों के लिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन से आपातकालीन प्राधिकरण की मांग की है।

यह भारत के लिए कैसे प्रासंगिक है?

- भारत दुनिया में कोविड–19 मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या के लिए जिम्मेदार है।
- भारत ने यह पता लगाना जारी रखा है कि वह अपने प्राथमिकता समूहों को शॉट्स की आपूर्ति कैसे करेगा, एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि वह 2020 तक इस एंटीबॉडी कॉकटेल की 1,00,000 खुराक तक आपूर्ति करने के लिए तैयार हो जाएगा।
- भारत के बायोफर्मासिटिकल उद्योग के लिए इस तरह के उपचारों को कंपनी से समझौतों और तकनीकी हस्तांतरण के साथ पुनः पेश करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की चिकित्सा इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश की दवाओं की सूचि में जुड़ सकती है और संक्रमित लोगों का प्रभावी ढंग से इलाज कर सकती है। बशर्ते कि भारत किसी भी स्थानीय परीक्षण से पता चले कि कॉकटेल इसके लायक है।

केंद्र द्वारा 1.10 लाख करोड़ रुपये का ऋण

समाचार –

- केंद्र जीएसटी संग्रह में कमी को दूर करने के लिए राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपये तक उधार लेगा।

पृष्ठभूमि –

- जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था, तो राज्यों को जीएसटी रोलआउट के पहले पांच वर्षों में अपनी अंतिम कर प्राप्तियों पर 14 प्रतिशत वृद्धिशील राजस्व का वादा किया गया था।
- यह विलासिता और पाप के सामान पर उपकर या अधिभार के माध्यम से किया जाना था, लेकिन पिछले वित्त वर्ष से अर्थव्यवस्था में मंदी के साथ इस गिनती पर संग्रह कम हो गया है।
- कर का कम संग्रह उन राज्यों के बजटों को परेशान कर रहा है जिन्होंने जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने पर बिक्री कर या वैट जैसे स्थानीय करों को लागू करने का अधिकार छोड़ दिया था।
- कमी के लिए, बाजार से उधार लेने का प्रस्ताव किया गया था।

विवरण –

- जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जारी करने के एवज में उधार ली गई राशि को राज्यों को बैक–टू–बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा।
- भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर उधार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- यह राशि राज्य सरकारों की पूंजी प्राप्तियों के रूप में और इसके वित्तीय घाटे के वित्तपोषण के हिस्से के रूप में परिलक्षित होगी।
- यह ब्याज की अंतर दरों से बचाएगा जो अलग–अलग राज्यों को उनके राज्य विकास ऋण के लिए चार्ज किया जा सकता है और एक प्रशासनिक रूप से आसान व्यवस्था होगी।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य सरकारी (राज्य + केंद्र) ऋण पर इस कदम से नहीं बढ़ेगा।
- जिन राज्यों को विशेष विंडो से लाभ मिलता है, उनके लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सुविधा से काफी कम राशि उधार लेने की संभावना है।

अन्य उपाय –

- कारों और अन्य लक्जरी वस्तुओं और तंबाकू उत्पादों पर अधिभार 28 प्रतिशत की उच्चतम जीएसटी दर के शीर्ष पर 12 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक भिन्न होता है। यह जून 2022 में समाप्त होने वाला था। इसे अब 2022 से आगे बढ़ा दिया गया है।
- उधार ली गई राशि पर ब्याज उपकर पर पहला शुल्क होगा, जो पाँच वर्षों के बाद एकत्र किया जाता है। अगला शुल्क उस मूल राशि की ओर 50 प्रतिशत पर होगा जो उधार ली गई है, यानी 1.10 लाख करोड़ रुपये और फिर शेष 50 प्रतिशत कोविड–19 प्रभावित मुआवजे की ओर होगा।

जीएसटी जारी –

- जीएसटी संरचना के तहत, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत स्लैब के तहत कर लगाया जाता है। उच्चतम कर स्लैब के ऊपर, लक्जरी, सिन और डिमेरिट माल पर उपकर लगाया जाता है और उसी से प्राप्त आय का उपयोग राज्यों को किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।
- अगस्त 2019 के बाद से उपकर लगाने से राजस्व में कमी के बाद राज्यों को जीएसटी मुआवजे का भुगतान एक मुद्दा बन गया।
- केंद्र को 2017–18 और 2018–19 के दौरान एकत्रित अतिरिक्त उपकर राशि में डुबकी लगानी थी।
- केंद्र ने 2019–20 में जीएसटी मुआवजे के रूप में 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए थे। हालांकि, 2019–20 के दौरान उपकर की राशि 95,444 करोड़ रुपये थी।
- 2018–19 में मुआवजा भुगतान राशि 69,275 करोड़ रुपये और 2017–18 में 41,146 करोड़ रुपये थी।
- चालू वित्त वर्ष के अप्रैल–जुलाई के दौरान, राज्यों के कारण कुल मुआवजा 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

स्वास्थ्य बीमा शिखर सम्मेलन

समाचार –

- इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं से रोग–विशिष्ट उत्पादों को विकसित करने का आग्रह किया और पॉलिसीधारकों को निवारक देखभाल प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया।

मुख्य विशेषताएं –

- मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा एक स्वास्थ्य बीमा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- IRDAI अध्यक्ष ने कहा, बीमा कंपनियां विभिन्न रोगों से बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जागरूक पॉलिसी धारकों को बनाने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों को एक साथ ला सकती हैं।
- उन्होंने यह भी कहा कि बीमा कंपनियों ने अब तक टेरीटरी केयर एवं हॉस्पिटलाईज़ेशन पर ध्यान केंद्रित किया है जबकि अब प्राईमरी, सेकेंडरी एवं प्रिवेंटीव केयर के क्षेत्रों में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- प्त्क।प् ने बीमा कंपनियों से छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य बीमा की पर्याप्त गुंजाइश है, के बाजारों का दोहन करने का आग्रह किया।

कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री

- बीमा कंपनियों ने स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच रोगों के इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल होने पर भी जोर दिया।
- 1895 में स्थापित, नई दिल्ली स्थित, एक गैर–सरकारी, लाभ–रहित, उद्योग–प्रधान और उद्योग–प्रबंधित संगठन है।
- भारत, विकासशील उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए काम करता है।
- यह एक सदस्यता–आधारित संगठन है, और सदस्यता निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से मिलकर बनी है, जिसमें भारत में एसएमई और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और क्षेत्रीय संघ शामिल हैं।

विवरण –

- स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को जनता की आवश्यकता के आधार पर मधुमेह, हृदय या गुर्दे से संबंधित मुद्दों जैसे अभिनव रोग–विशिष्ट उत्पादों के साथ बाहर आना चाहिए।
- इस तरह के फोकस्ड प्रोडक्ट्स के तहत, बीमा कंपनियां अपने पॉलिसीधारकों को विभिन्न रोगों के प्रति जागरूक करने के लिए मेडिकल विशेषज्ञों को एक साथ ला सकती हैं।
- वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा का एक बड़ा हिस्सा 40–50 वर्ष की आयु समूह द्वारा खरीदा जाता है और बीमा कंपनियों को युवा जनसंख्या को आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए।
- स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए युवा आबादी को आकर्षित करने का एक अन्य तरीका स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के हिस्से के रूप में आउट पेशेंट देखभाल है।
- बीमा कंपनियां परिवार के चिकित्सक, वार्षिक स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य बीमा योजना के हिस्से के रूप में टीकाकरण की अवधारणा को पेश कर सकती हैं।
- स्वास्थ्य बीमाकर्ता को देश में मध्यम और छोटे उद्योगों या अनौपचारिक क्षेत्र का दोहन करना चाहिए।
- IRDAI ने बीमा कंपनियों से छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में उन बाजारों के दोहन का आग्रह किया जहां स्वास्थ्य बीमा की पर्याप्त गुंजाइश है।
- बीमा कंपनियों ने बीमारियों के इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल रखने के लिए स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग करने पर भी जोर दिया जा सकता है।

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण –

- IRDAI एक स्वायत्त, वैधानिक निकाय है जो भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित करता और बढ़ावा देता है।
- यह बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा गठित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा पारित संसद का एक अधिनियम है।
- एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है, जहां यह 2001 में दिल्ली से चला गया।
- IRDAI एक 10 सदस्यीय निकाय है, जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य शामिल हैं।

चीन से गैर–जरूरी आयात पर मानदंड

समाचार –

- भारत के विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए एयर कंडीशनर (सभी प्रकार) और रेफ्रिजरेंट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इस कदम के साथ, भारत ने चीन से गैर–जरूरी आयात पर और कड़े नियम बनाए हैं।

मुख्य विशेषताएं –

- इस कदम का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बड़ा बढ़ावा देना है।
- सरकार, स्थानीय निर्माताओं को उत्पादन और बिक्री में कदम रखना चाहती है, जो कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप है।
- उनमें से सभी (एसी और रेफ्रिजरेटर) को 'मुक्त' से 'निषिद्ध' श्रेणी में ले जाया गया है।
- देश ने पहले टेलीविजन सेटों के आयात को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया था और आयातकों को DGFT से लाइसेंस लेने के लिए कहा था।
- भारत में एयर कंडीशनर का घरेलू बाजार बहुत बड़ा है और माना जाता है कि यह लगभग 5–6 बिलियन डॉलर का है।

- व्यापार निदेशालय (डीजीटीआर) के महानिदेशक ने घरेलू निर्माताओं द्वारा शिकायतों की झड़ी के बाद चीन, मलेशिया और वियतनाम से कोलीन क्लोराइड आयात पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

पृष्ठभूमि –

- 2019–20 में, भारत ने 469 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के एयर–कंडीशनर का आयात किया। ये मुख्य रूप से चीन और थाईलैंड से थे।
- चीनी आयात 241 मिलियन अमरीकी डालर का था और थाईलैंड के लोग 189 मिलियन अमरीकी डालर के आसपास थे। विंडो एयरकंडिशनर का आयात लगभग 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- अप्रैल–अगस्त की अवधि में, चीन से भारतीय आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 27 प्रतिशत घटकर 21.58 बिलियन डॉलर हो गया है।

महत्वपूर्ण जानकारी –

- भारत ने अगस्त में देश में रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं पर आयात रोक लगाई थी।
- आर्टिलरी गन, लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर, असॉल्ट राइफल, कोरवेट, रडार, व्हीकल आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल (एएफवी), ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और अन्य हाई टेक्नोलॉजी हथियार जैसे कुछ आइटम हैं जिन्हें अब विदेशों से आयात नहीं किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सभी उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ाना है।

विदेश व्यापार महानिदेशक

- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एजेंसी है, जो भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के बारे में कानूनों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
- भारत के सभी निर्यातकों और आयातकों का पूर्ण खोज डेटाबेस उपलब्ध कराता है।
- महानिदेशक केंद्र सरकार को विदेश व्यापार नीति तैयार करने की सलाह देते हैं और उस नीति को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- आम तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सदस्य ने 30 या उससे अधिक वर्षों के लिए विदेश व्यापार के महानिदेशक के पद पर नियुक्ति की है।
- भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में महानिदेशक एक संलग्न कार्यालय का प्रमुख होता है।
- महानिदेशक भारत सरकार का पदेन अतिरिक्त सचिव होता है।

'स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट'

समाचार –

- संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में 'जलवायु रिपोर्ट का राज्य' जारी किया।

झलकियाँ –

- दो मिलियन मौतें, आर्थिक नुकसान में $ 3.6 ट्रिलियन और पिछले 50 वर्षों में 11,000 आपदाएं, चरम मौसम की स्थिति के कारण हुईं।
- '2020 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज' ने कहा कि वे संख्या दर्ज आपदाओं की संख्या में पांच गुना वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप चरम मौसम और जलवायु की घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता और गंभीरता में वृद्धि हुई है।
- जलवायु–बाढ़ से होने वाली आपदाएं (दावानल, बाढ़) दुनिया के हर कोने में जीवन और आजीविका को नष्ट कर रही हैं।
- कोविड–19 ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य और आर्थिक संकट को उत्पन्न किया, जिससे उबरने में कई साल लगेंगे।
- यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन सदियों से मानव जीवन, पारिस्थितिक तंत्र, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के लिए आने वाले और बढ़ते खतरे को जारी रखेगा।

रिपोर्ट की मुख्य बातें –

- 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या 50% बढ़ सकती है।
- बाढ़, तूफान, सूखा और जंगल की आग जैसी आपदाओं से 108 मिलियन से अधिक प्रभावित हुए थे।
- पिछले 50 वर्षों में मौतों की औसत संख्या में 50 साल की कमी आई है।
- विश्व मौसम संगठन के केवल 40% हिस्से में मल्टी–हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि महामारी से संबंधित मंदी वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2020 तक 4.4% कम कर देगी।

सिफारिशं –

- रिपोर्ट ने कुछ रणनीतिक सिफारिशें की हैं –
  – प्रारंभिक चेतावनी सूचना प्रणाली पर निवेश पर ध्यान केंद्रित करना।
  – कम विकसित अफ्रीकी देशों में निवेश करने के लिए।
  – वित्त प्रवाह पर नजर रखने के लिए।
  – प्रारंभिक चेतावनियों के लिए स्थायी वित्तपोषण सुनिश्चित करना।
- 3 मिलियन वर्षों में ग्रीन हाउस गैसें अपने उच्चतम स्तर पर हैं।
- सभी देशों को अपने उत्सर्जन को 2010 के स्तर से 45% कम करना चाहिए। यह ग्लोबल हीटिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का एकमात्र तरीका है।
- 2050 तक केवल 70 देशों ने कार्बन तटस्थता के लिए सहमति व्यक्त की है।

जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट लैंसेट

समाचार –

- लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि भारत में जीवन प्रत्याशा 59.6 वर्ष से बढ़कर 1990 में 2019 में 70.8 वर्ष हो गई है।
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर, ने कहा कि भारत में 'स्वस्थ जीवन प्रत्याशा' में वृद्धि उतनी नाटकीय नहीं हुई है क्योंकि 'लोग बीमारी और विकलांगता के साथ अधिक वर्षों से जी रहे हैं'।

प्रमुख निष्कर्ष – ग्लोबल परिदृश्य

- क्रोनिक बीमारियों का मौजूदा वैश्विक संकट और उच्च रक्तचाप, तम्बाकू के उपयोग और वायु प्रदूषण जैसे अत्यधिक रोके जाने वाले जोखिम कारकों में वृद्धि को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की विफलता ने आबादी को छोड़ दिया है।
- कोविड–19 जैसी तीव्र स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता।
- भारत सहित लगभग हर देश में देखा जाने वाला मुख्य सुधार संक्रामक रोगों में गिरावट और पुरानी बीमारियों में अधिक वृद्धि है।
- जबकि दुनिया के कई हिस्सों ने टीकाकरण और बेहतर चिकित्सा देखभाल के माध्यम से संक्रामक रोगों को नियंत्रित किया है, कुछ देश अभी भी इन महामारियों के प्रबंधन के लिए संघर्ष करते हैं।
- पुरानी बीमारी और मोटापे, उच्च रक्त शर्करा और बाहरी वायु प्रदूषण सहित संबंधित जोखिम कारकों में वैश्विक वृद्धि के साथ कोविड–19 की पारस्परिक क्रिया ने पिछले 30 वर्षों में कोविड–19 मौतों को बढ़ाते हुए एक तूफान खड़ा कर दिया है।
- दक्षिण एशिया क्षेत्र में, गैर–संचारी रोग (एनसीडी) अब बीमार स्वास्थ्य, विकलांगता या प्रारंभिक मृत्यु के कारण आधे से अधिक वर्षों में योगदान करते हैं, जो 30 साल पहले संक्रामक, मातृ, नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों का प्रभुत्व था।

भारतीय परिदृश्य –

- भारत ने 1990 के बाद से एक दशक से अधिक जीवन प्रत्याशा हासिल की है।
- भारत में मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें कमी आ रही है।
- कार्डियोवैस्कुलर रोग पहले नंबर पांच पर हुआ करते थे, और अब यह नंबर एक है, और कैंसर की दर बढ़ रही है।
- भारत में 58 प्रतिशत रोग का बोझ गैर–संचारी रोगों के कारण है, जो 1990 में 29 प्रतिशत था।
- एनसीडी के कारण समय से पहले होने वाली मौतों की संख्या 22 से 50 प्रतिशत तक दोगुनी हो गई है।
- पिछले 30 वर्षों में भारत में स्वास्थ्य हानि बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदानकर्ता एनसीडी थे जैसे कि इस्केमिक हृदय रोग, सीओपीडी, मधुमेह, स्ट्रोक और मस्कुलोस्केलेटल विकारों का एक समूह।
- 2019 में, भारत में मृत्यु के लिए शीर्ष पांच जोखिम कारक वायु प्रदूषण थे (अनुमानित 1.67 मिलियन मौतें, उच्च रक्त का योगदान) दबाव (1.47 मिलियन), तंबाकू का उपयोग (1.23 मिलियन), खराब आहार (1.18 मिलियन), और उच्च रक्त शर्करा (1.12 मिलियन)।

2022 तक ट्रांस वसा मुक्त भारत

समाचार –

- सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से एक वर्ष आगे 2022 तक भारत ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
- कोविड महामारी के कारण दुनिया के सामने आने वाली अभूतपूर्व चुनौतियों के कारण भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा और स्थिरता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इस वर्ष का मुख्य फोकस खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से ट्रांस–वसा का उन्मूलन है।

झलकियाँ –

- ट्रांसफैट, जो आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेलों जैसे कि वनस्पती, लघुकरण और मार्जरीन में मौजूद है, का प्रमुख योगदान है।
- भारत में गैर–संचारी रोगों में वृद्धि।
- ट्रांस–फैट हृदय रोगों (सीवीडी) के लिए एक परिवर्तनीय जोखिम कारक है।
- कोविड–19 के दौरान सीवीडी जोखिम कारक को खत्म करना विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि सीवीडी से पीड़ित लोगों में मृत्यु दर पर प्रभाव डालने वाली गंभीर स्थिति होने की संभावना होती है।

ईट राइट इंडिया आंदोलन

- एफएसएसएआई द्वारा ईट राइट इंडिया आंदोलन, पर्यावरण की दृष्टि से सभी के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया।
- यह सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने जनादेश का एक हिस्सा है।
- यह खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र में सुधार करेगा और हमारे नागरिकों की स्वच्छता और स्वास्थ्य को अच्छा करेगा।

अन्य पहलें –

- फिट भारत आंदोलन, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन और पर्यावरण मंत्रालय के अन्य प्रयासों के साथ भारतीयों के स्वास्थ्य में सुधार और पर्यावरण को ठीक करेगा।
- सरकार ने स्कूलों के लिए 'ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज' भी शुरू किया जो एक पोस्टर और फोटोग्राफी प्रतियोगिता है और इसका उद्देश्य स्वस्थ आहार आदतों को बढ़ावा देना है।

ट्रांस वसा क्या हैं?

- ट्रांस वसा, या ट्रांस–फैटी एसिड, असंतृप्त वसा का एक रूप है।
- वे प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों में आते हैं।
- प्राकृतिक, या जुगाली करनेवाला, ट्रांस वसा मांस और डेयरी में जुगाली करने वाले जानवरों, जैसे कि मवेशी, भेड़ और बकरियों से होता है। वे स्वाभाविक रूप से तब बनते हैं जब इन जानवरों के पेट में बैक्टीरिया घास को पचाते हैं।
- इन प्रकारों में आम तौर पर डेयरी उत्पादों में वसा का 2–6% और बीफ और मेमने (1, 2) में वसा का 3–9% शामिल होता है।
- डेयरी प्रदार्थों और मांस खाने वालों को चिंता की की आवश्यकता नहीं है।
- हालांकि, कृत्रिम ट्रांस वसा – अन्यथा औद्योगिक ट्रांस वसा या आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वसा के रूप में जाना जाता है – जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।
- ये वसा तब होते हैं जब वनस्पति तेलों को कमरे के तापमान पर ठोस रहने के लिए रासायनिक रूप से बदल दिया जाता है, जो उन्हें अधिक लंबा जीवन देता है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020

समाचार –

- भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2020 में 107 देशों में 94 वें स्थान पर है और 'गंभीर' भूख श्रेणी में बना हुआ है।
- पिछले साल, भारत की रैंक 117 देशों में से 102 थी।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स का विवरण –

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए एक उपकरण है।
- स्कोर चार घटक संकेतकों के मूल्यों पर आधारित हैं –
  1. अल्पपोष्ण (अपर्याप्त कैलोरी सेवन के साथ जनसंख्या का हिस्सा)
  2. बाल कुपोषण
  3. बाल स्टंटिंग
  4. बाल मृत्यु

- **बाल कुपोशण** – ऐसे बच्चे हैं जिनकी ऊंचाई कम होती है, जो तीव्र कुपोषण को दर्शाते हैं।
- **बाल स्टंटिंग** – पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो कुपोषण को दर्शाते हैं।
- **बाल मृत्यु दर** – पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर।

- चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर, जीएचआई 100–बिंदु पैमाने पर भूख निर्धारित करता है जहां 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर (भूख नहीं) है और 100 सबसे खराब है। प्रत्येक देश के GHI स्कोर को गंभीरता से वर्गीकृत किया जाता है, निम्न से अत्यंत खतरनाक तक।

झलकियाँ –

- बांग्लादेश (रैंक 75), म्यांमार (रैंक 78) और पाकिस्तान (रैंक 88) भी 'गंभीर' श्रेणी में हैं, लेकिन भारत से उच्च स्थान पर हैं।
- 73 वें स्थान पर नेपाल और 64 वें स्थान पर श्रीलंका 'मध्यम भूख' श्रेणी में हैं।
- चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत सहित सत्रह देशों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर पांच से कम अंक के साथ शीर्ष रैंक साझा की।
- कुल 107 देशों में से केवल 13 देश भारत से बदतर हैं, जिनमें रवांडा (97), नाइजीरिया (98), अफगानिस्तान (99), लाइबेरिया (102), मोजाम्बिक (103), चाड (107) जैसे देश शामिल हैं।
- बांग्लादेश, भारत, नेपाल, और पाकिस्तान ने दिखाया कि कुपोषण गरीब परिवारों के बच्चों, जिनमें आहार की विविधता में कमी, मातृत्व शिक्षा और घरेलू गरीबी के निम्न स्तर शामिल हैं, अत्यधिक है।

भारत –

- गरीब कार्यान्वयन प्रक्रियाओं, प्रभावी निगरानी की कमी, कुपोषण से निपटने में मौन दृष्टिकोण और बड़े राज्यों द्वारा खराब प्रदर्शन, निम्न रैंकिंग के कारण हैं।

- भारत की 14 प्रतिशत आबादी अल्पपोषित है।
- भारत में पांच से कम उम्र के बच्चों के बीच 37.4 प्रतिशत स्टंटिंग दर और 17.3 प्रतिशत की बर्बादी दर दर्ज की गई।
- पांच प्रतिशत मृत्यु दर 3.7 प्रतिशत थी।
- भारत ने जन्म–मृत्यु या आघात, नवजात संक्रमण, निमोनिया और दस्त से होने वाली मौतों में कमी के कारण बड़े पैमाने पर कम–से–कम मृत्यु दर (1991 से 2014 तक की अवधि) का अनुभव किया।
- समय से पहले जन्म और कम जन्म के कारण बाल मृत्यु दर, विशेष रूप से गरीब राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी।
- समय से पहले जन्म और निम्न जन्म की रोकथाम भारत में पांच–मृत्यु दर को कम करने की क्षमता के साथ एक प्रमुख कारक के रूप में पहचानी जाती है।

- भारत की रैंकिंग में समग्र परिवर्तन देखने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है।

महामारी के कारण भूख को रोकने के लिए पांच उपाय –

- पौष्टिक, सुरक्षित और सस्ती आहार तक पहुंच की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना।
- गर्भावस्था, शैशवावस्था और बचपन में मातृ एवं शिशु पोषण में सुधार।
- बच्चे को बर्बाद करने के शुरुआती पता लगाने और उपचार के लिए फिर से सक्रिय और स्केल–अप सेवाएं।
- कमजोर बच्चों के लिए पौष्टिक और सुरक्षित स्कूल भोजन का प्रावधान रखें।
- पौष्टिक आहार और आवश्यक सेवा तक पहुंच की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करें।

निष्कर्ष –

- भूख और अल्पपोषण केवल कैलोरी के प्रावधान से तय नहीं किया जा सकता है।
- सभी हितधारकों को संतुलित स्वस्थ आहार बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो जलवायु के अनुकूल हो, सस्ती हो और सभी के लिए सुलभ हो।

भारत को पहलो 'सेवियर सिबलिंग'

समाचार –

- भारत की पहली 'सेवियर सिबलिंग' काव्या सोलंकी एक साल की हो गई हैं।
- काव्या वो बच्ची है जिसे अपने बड़े भाई अभिजीत की जान बचाने के लिए आईवीएफ के जरिए बनाया गया था।
- थैलीसीमिया से जूझ रहे अभिजीत को काव्या से बोन मैरो मिली और पिछले छह महीन से उसकी हालत ठीक है।
- भारत में अपनी तरह का यह पहला मामला है।

सेवियर सिबलिंग या रक्षक सहोदर –

- सेवियर सिबलिंग उन शिशुओं को संदर्भित करता है जो किसी भाई–बहन को अंगों, अस्थि मज्जा या कोशिकाओं के दाता के रूप में सेवा करने के लिए बनाए जाते हैं।
- सेवियर सिबलिंग के गर्भनाल रक्त या रक्त से स्टेम सेल का उपयोग थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे गंभीर रक्त विकारों के उपचार के लिए किया जाता है।

विवरण –

- अभिजीत के माता–पिता को बच्चे के इलाज के लिए अंतिम उपाय के रूप में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्हें आवश्यक एचएलए (मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन) मैच नहीं मिला।
- प्रत्यारोपण के लिए एचएलए दाताओं के मिलान की अनुपलब्धता के कारण, अभिजीत के माता–पिता ने एचएलए मिलान के साथ आईवीएफ का विकल्प चुना।
- पूर्व–आनुवांशिक परीक्षण के कई दौर से गुजरने के बाद, अपने माता–पिता द्वारा अदृश्य निषेचन (आईवीएफ) के माध्यम से काव्या को जन्म दिया गया, ताकि वह अपने बड़े भाई के लिए एक दाता बन सके।

HLA (मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन)

- एचएलए प्रणाली या कॉम्प्लेक्स संबंधित प्रोटीन का एक समूह है जो मनुष्यों में प्रमुख हिस्टोकोम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स (एमएचसी) जीनोमोम प्लेक्स द्वारा एन्कोड किया जाता है।
- ये कोशिका–सतह प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार हैं।
- HLA जीन अत्यधिक पोलीमॉर्फिक होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास कई अलग–अलग एलील हैं, जो उन्हें अनुकूली प्रतिरक्षा को ठीक करने की अनुमति देते हैं।
- अंग प्रत्यारोपण में कारकों के रूप में उनकी ऐतिहासिक खोज के परिणामस्वरूप, कुछ जीनों द्वारा एन्कोड किए गए प्रोटीन को एंटीजन के रूप में भी जाना जाता है।

थैलेसीमिया –

- थैलेसीमिया एक विरासत में मिला (यानी, माता–पिता से बच्चों को जीन के माध्यम से पारित) रक्त विकार है जिसमें शरीर रक्त की लाल कोशिकाओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से हीमोग्लोबिन को नही बना पाता है।
- जब पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं और वे कम समय तक चलती हैं, इसलिए रक्तधारा में यात्रा करने वाले कम स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं।
- लाल रक्त कोशिकाएं शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाती हैं। ऑक्सीजन एक प्रकार का भोजन है जिसका उपयोग कोशिकाएँ कार्य करने के लिए करती हैं।
- जब पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो शरीर की अन्य सभी कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिससे व्यक्ति को थका हुआ, कमजोर या सांस की कमी महसूस हो सकती है। यह एक स्थिति है जिसे एनीमिया कहा जाता है।
- थैलेसीमिया वाले लोगों में हल्के या गंभीर एनीमिया हो सकते हैं। गंभीर एनीमिया अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और मृत्यु हो सकती है।

इन–विट्रो निषेचन (आईवीएफ) –

- आईवीएफ निषेचन की एक प्रक्रिया है जहां एक अंडे को शरीर के बाहर शुक्राणु के साथ, इन विट्रो ('ग्लास') में संयुक्त किया जाता है।
- आईवीएफ एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीक है जिसका उपयोग बांझपन उपचार और गर्भकालीन सरोगेसी के लिए किया जाता है।

विश्व वन्यजीव कोष द्वारा खाद्य उपभोग रिपोर्ट

समाचार –

- वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने 'बेंडिंग द कर्व – द रिस्टोरेटिव पावर ऑफ प्लेनेट–बेस्ड डाइट्स' रिपोर्ट प्रकाशित की है।
- रिपोर्ट में 147 देशों और छह क्षेत्रों में भोजन की खपत के पैटर्न और 75 देशों में राष्ट्रीय आहार दिशानिर्देश (NDGs) का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
- प्रत्येक देश और क्षेत्र के लिए, विभिन्न पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकेतकों पर आहार के प्रभावों का मूल्यांकन किया गया था।

निम्न आहार पैटर्न का मूल्यांकन किया गया –

- **वर्तमान आहार** – वर्तमान में किसी देश के नागरिकों द्वारा खाया जाने वाला औसत आहार

- **राष्ट्रीय आहार संबंधी दिशा–निर्देश** – प्रत्येक देश से संबंधित सरकारी विभाग द्वारा दिए गए आहार संबंधी दिशानिर्देश
- **फ्लेक्सिटेरियन** – प्लांट–आधारित, लेकिन मांस सहित मध्यम पशु–स्रोत भोजन की खपत के लिए अनुमति देता है।
- **पेसचेरियन** – मांस की जगह दो–तिहाई मछली और समुद्री भोजन और एक तिहाई फल और सब्जियां।
- **शाकाहारी** – मांस को दो–तिहाई फलियां और एक तिहाई फल और सब्जियों से बदलना।
- **शाकाहारी** – सभी पशु–स्रोत खाद्य पदार्थों को दोतिहाई फलियां और एक तिहाई फल और सब्जियों के साथ बदलना।

मुख्य निष्कर्ष –

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव को मौजूदा खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए तत्काल और स्थानीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
- अस्वास्थ्यकर भोजन के कारण कम और मध्यम आय वाले देशों में समय से पहले मृत्यु, कम खपत के साथ–साथ अति–खपत एक उभरती हुई चिंता है।
- भोजन की खपत के पैटर्न व्यापक रूप से भिन्न होते हैं और सबसे बड़ी असमानता की विशेषता हो सकती है।
- सबसे अमीर और गरीब देशों में विभिन्न खपत पैटर्न देखे जाते हैं, यूरोपीय देशों में अफ्रीकी देशों की तुलना में लगभग 600 ग्राम प्रति दिन अधिक भोजन (1,800 ग्राम/दिन) का सेवन किया जाता है।
- हालांकि कम पोषण और मोटापा लगभग सभी देशों को प्रभावित करते हैं, अन्य देशों की तुलना में सबसे गरीब देशों में कम वजन वाले लोगों की दर 10 गुना अधिक है। सबसे अमीर देशों में अधिक वजन/मोटापे से ग्रस्त लोगों की दर पांच गुना तक अधिक है।
- भारत को आहार में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि स्वस्थ और ग्रह–अनुकूल आहार में बदलाव के कारण जैव विविधता में कमी हो सकती है और व्यापक रूप से वृद्धि हुई खपत हो सकती है।
- भारत को अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले फलों, सब्जियों और डेयरी की खपत बढ़ानी होगी।
- कुछ देशों में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी देखी जा सकती है, जबकि अन्य में वृद्धि देखी जा सकती है। कुछ देशों को वर्तमान आहार को मौलिक रूप से बदलने की आवश्यकता होगी, जबकि अन्य को पारंपरिक आहार पैटर्न पर काम करने और अधिक पश्चिमी आहार के विरोध करने की आवश्यकता हो सकती है।
- तीन में से एक व्यक्ति या तो बहुत कम या बहुत अधिक खाता है।
- वर्तमान खपत पैटर्न दुनिया भर में संतुलित नहीं है।

समय की आवश्यकता –

- पौधा–आधारित आहार समय की आवश्यकता हो सकती है।
- कुछ देशों को पशु–स्रोत खाद्य पदार्थों की अपनी खपत को कम करने की आवश्यकता होगी, दूसरों को उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।
- बदलाव न केवल किसी भी भोजन की अधिक खपत को रोककर मानव स्वास्थ्य में सुधार करेगा, बल्कि अब तक हुए जैविक नुकसान को भी उलट देगा और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार करेगा।
- आहार को अधिक पौधा–आधारित करने से कार्बन उत्सर्जन में 30 प्रतिशत, वन्यजीवों का नुकसान में 46 फीसदी, कृषि भूमि का उपयोग में 41 प्रतिशत और अकाल मृत्यु में 20 प्रतिशत की कमी आएगी।

ग्रह आधारित आहार प्रभाव और कार्रवाई कैलकुलेटर –

- WWF ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसे प्लैनेट–बेस्ड डाइट्स इम्पैक्ट एंड एक्शन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है।
- इसके साथ, कोई भी उनके उपभोग की गणना कर सकता है और पर्यावरण पर उसके आहार से होने वाले प्रभावों का पता लगा सकता है।
- मंच राष्ट्रीय स्तर के प्रभावों को भी दर्शाता है।
- यह दुनिया में कहीं भी रहने वाले लोगों को यह पता लगाने में मदद करेगा कि क्या उनका आहार उनके साथ–साथ उनके पर्यावरण के लिए भी अच्छा है।
- मंच में एक अनूठा उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को 13 विभिन्न खाद्य समूहों के कैलोरी इंटेक के आधार पर आहार को अनुकूलित करने की अनुमति देता है।

भारत का लिंग अनुपात

समाचार –

- सी। रंगराजन (पूर्व अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद) और जेके सतिया (प्रोफेसर एमेरिटस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ) का तर्क है कि युवाओं में प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं के साथ–साथ लिंग समानता मानदंडों के पहुंचाने की तत्काल आवश्यकता है। ।

विवरण –

- ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत में प्रजनन क्षमता घट रही है।
- सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) सांख्यिकीय रिपोर्ट (2018) ने कुल प्रजनन दर (टीएफआर) का अनुमान लगाया, वर्ष 2018 में, मौजूदा पैटर्न पर, एक माँ को होने वाले बच्चों की संख्या 2.2 है।
- उर्वरता में गिरावट जारी रहने की संभावना है और अनुमान है कि 2.1 का प्रतिस्थापन यातो पहले ही आ चुका होगा या जल्द ही आ जाएगा।
- लेकिन एसआरएस रिपोर्ट में सबसे अधिक परेशान करने वाले आंकड़े जन्म के समय लिंगानुपात के लिए हैं। जन्म के समय जैविक रूप से सामान्य लिंगानुपात 1,050 पुरुषों की तुलना में 1,000 महिलाओं या 950 महिलाओं का 1,000 पुरुषों पर होता है।
- SRS रिपोर्ट बताती है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है, जो 2011 में 906 से घटकर 2018 में 899 हो गया।
- संभवतः केरल और छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों में बेटे को प्राथमिकता दी जाती है।
- यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 ने भारत में जन्म के समय लिंगानुपात को 910 के रूप में अनुमानित किया, चीन को छोड़कर विश्व में सबसे कम।

- यह चिंता का कारण है क्योंकि इस प्रतिकूल अनुपात के परिणामस्वरूप पुरुषों और महिलाओं की संख्या में व्यापक असंतुलन होगा और इसके अनिवार्य प्रभाव शादी की व्यवस्था के साथ–साथ महिलाओं को होने वाली अन्य परेशानियों पर भी पड़ेगा।

सुझाव –

- महिला शिक्षा और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने से अनुपात में सुधार करने में मदद मिलती है।
- लिंग–पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के परिणामस्वरूप पुत्र की वरीयता की जटिलता को देखते हुए, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी कार्यों को पूरक बनाने की आवश्यकता है।
- महिलाओं और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पर रोलआउट अभियान, महिलाओं की सुरक्षा कोशिकाओं को बनाना, सार्वजनिक रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- परिवहन प्रणाली, साइबर–क्राइम सेल बनाना कुछ अन्य पहल हैं जिन्हें लेने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष –

- प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं के साथ–साथ लिंग इक्विटी मानदंडों की खेती करने के लिए युवा लोगों तक पहुंचने की तत्काल आवश्यकता है।
- यह जनसंख्या की गति के प्रभाव को कम कर सकता है और जन्म के समय सामान्य लिंग–अनुपात तक पहुंचने की दिशा में प्रगति को तेज कर सकता है। भारत का जनसंख्या भविष्य इस पर निर्भर करता है।

नमूना पंजीकरण प्रणाली –

- एसआरएस, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर और अन्य प्रजनन क्षमता और राष्ट्रीय और उप–मृत्यु दर के विश्वसनीय अनुमान प्रदान करने के लिए एक जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। स्तरों।
- यह रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा लाया जाता है।

कुल उपजाऊ दर (टोटल फर्टिलीटी रेट) –

- एक जनसंख्या का TFR उन बच्चों की औसत संख्या है जो अपने जीवनकाल में किसी महिला से जन्म लेंगे।
- उसे अपने जीवनकाल के दौरान सटीक वर्तमान आयु संबंधी प्रजनन दर (ASFRs) का अनुभव करना होगा।
- उसे अपने प्रजनन जीवन के अंत तक प्रसव प्रक्रिया से जीवित बच कर निकलना होगा।

यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड –

- यूएनएफपीए एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।

वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड प्रदूषण –

समाचार –

- 1980 और 2016 के बीच नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) का मानव उत्सर्जन 30 प्रतिशत बढ़ा है।
- यह एक ग्रीनहाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की तुलना में 300 गुना अधिक शक्तिशाली है।
- इस शोध को अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल (INI) और ग्लोबल क्लाइमेट प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर अर्थ, वर्ल्ड क्लाइमेट अनुसंधान कार्यक्रम के सहयोगी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आयोजित किया गया था।
- अनुसंधान प्राकृतिक और मानवजनित (मानव निर्मित) दोनों स्रोतों को जोड़ता है।

नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)

- नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी पर मनुष्यों के स्थायी अस्तित्व के लिए एक खतरनाक गैस है।
- ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीनहाउस गैसों के बीच हमारे वातावरण में CO_2 और मीथेन के बाद इसकी तीसरी सबसे अधिक सांद्रता है।
- N_2O वातावरण में 125 वर्ष तक रह सकती है।

मुख्य निष्कर्ष –

- इसके (N_2O) वैश्विक एकाग्रता का स्तर 1750 में 270 भागों प्रति बिलियन (पीपीपी) से बढ़कर 2018 में 331 पीपीबी हो गया – 20 प्रतिशत की छलांग।
- मात्रा पिछले पांच दशकों में मानव उत्सर्जन के कारण अधिक हुई है।
- अध्ययन में N_2O के 21 प्राकृतिक और मानवीय स्रोतों का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि कुल उत्सर्जन का 43 प्रतिशत मानव स्रोतों से आया है।
- N_2O ओजोन परत के लिए भी एकमात्र बचा हुआ खतरा है, क्योंकि यह वायुमंडल में लंबे समय तक जमा रहता है, जैसे CO_2 ।
- यह इस तथ्य के अतिरिक्त है कि 'अभी, हमारे उत्सर्जन प्रक्षेपवक्र सबसे खराब स्थिति परिदृश्य की अपेक्षा अधिक है।'
- N_2O उत्सर्जन में वृद्धि का मतलब है कि वायुमंडल पर जलवायु का बोझ गैर–कार्बन स्रोतों से भी बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं का प्रमुख ध्यान वर्तमान में कार्बन, इसके उत्सर्जन और शमन पर केंद्रित है।

जलवायु संकट और वैश्विक खाद्य सुरक्षा –

- इसमें पाया गया कि पिछले चार दशकों में N_2O उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आया, जिसका मुख्य कारण नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का उपयोग है।
- जानवरों के लिए भोजन और फीड की बढ़ती मांग वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को और बढ़ाएगी। जिस तरह से हम लोगों को खिला रहे हैं और जलवायु को स्थिर कर रहे हैं, उसके बीच संघर्ष है।
- अधिकांश N_2O उत्सर्जन भारत, चीन और ब्राजील जैसे उभरते देशों से आया है।

निष्कर्ष –

- नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रथाओं और प्रौद्योगिकियां हैं। यूरोप में औद्योगिक और कृषि नीतियों ने ऐसे उत्सर्जन को काफी कम कर दिया।
- फिर भी, यूरोप में और साथ ही विश्व स्तर पर और प्रयासों की आवश्यकता होगी।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से कम वायु और जल प्रदूषण के सह–लाभ भी हैं।
- स्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन पर 2019 संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने वाले देशों में N_2O उत्सर्जन को धीमा करना संभव है।
- भारत ने INI की मदद से चौथे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में अपनाए गए पहले नाइट्रोजन संकल्प का नेतृत्व किया था।

1880 के बाद सबसे गर्म सितंबर

समाचार –

- संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन या एनओएए के अनुसार, 2020 का सितंबर 1880 के बाद से सबसे गर्म सितंबर था।
- सितंबर में औसत वैश्विक तापमान 1.75 डिग्री फारेनहाइट (° F) – डिग्री सेल्सियस का 0.97 (° C) – 20 वीं शताब्दी के औसत से ऊपर 59.0° F (15.0° C) था।

विवरण –

- सितंबर का तापमान सितंबर 2015 और 2016 दोनों के लिए औसत वैश्विक तापमान को एक °F (0.02 °C) से 0.04 तक बढ़ा देता है, जो पहले रिकॉर्ड पर सबसे गर्म सितंबर में से था।
- वर्ष–दर–वर्ष (जनवरी–सितंबर 2020) औसत वैश्विक तापमान रिकॉर्ड 20 वीं सदी के औसत से 1.84° F (1.02 ° C) अधिक होकर दूसरा सबसे गर्म वर्ष था। 2016 में यह केवल 0.07 ° F अधिक था।

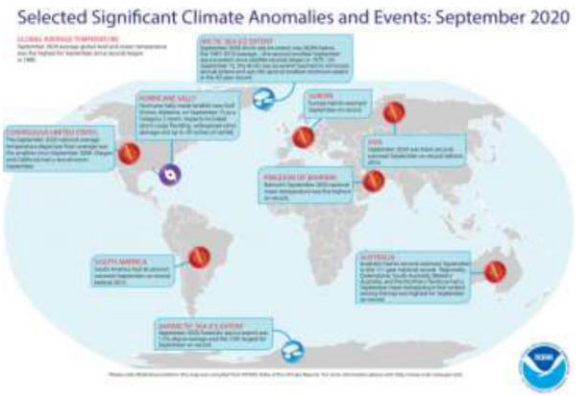

- आर्कटिक समुद्री बर्फ निम्नतम स्तर पर है। नासा और नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर द्वारा उपग्रह डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि 2020 की आर्कटिक समुद्री बर्फ की न्यूनतम सीमा – वर्ष के अस्थायी समुद्री बर्फ के आवरण का सबसे छोटा क्षेत्र – संभवतः 15 सितंबर तक पहुंच गया, दूसरी सबसे कम सीमा थी (2012 के बाद)।
- यह दुनिया के कुछ हिस्सों के लिए अब तक का एक रिकॉर्ड–हॉट–टू–डेट रहा है – यूरोप, एशिया और मैक्सिको की खाड़ी में रिकॉर्ड पर सबसे गर्म जनवरी–सितंबर अवधि थी, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में उनका दूसरा स्थान था। किसी भी भूमि या महासागरीय क्षेत्र में वर्ष–दर–वर्ष तापमान रिकॉर्ड नहीं किया गया था।

भारत का पहला क्लाउड इनोवेशन सेंटर

समाचार –

- डिजिटल नवाचार के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए, नीति आयोग ने हाल ही में Amazon Web Services (AWS) के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर (CIC) की स्थापना की घोषणा की – जो भारत में अपनी तरह का पहला है।
- क्लाउड इनोवेशन सेंटर (CIC) AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम का हिस्सा है।
- यह भारत का पहला AWS CIC है, जो दुनिया भर में 12 वां है, और पहला AWS CIC है जो राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक चुनौतियों का सामना करेगा।
- CIC ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के AWS सार्वजनिक क्षेत्र के क्लाउड इनोवेशन केंद्रों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया।
- केंद्र कृषि, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास के क्षेत्रों में नवाचार को गति देने का काम करेगा।

मुख्य विशेषताएं –

- सीआईसी कार्यक्रम सरकारी एजेंसियों, गैर–लाभकारी और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वे दबाव की चुनौतियों पर एक साथ आएं, डिजाइन सोच को लागू करें, नए विचारों का परीक्षण करें और AWS की प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता का उपयोग करें।
- कोई भी गैर–लाभकारी, शिक्षा या सरकारी संगठन एक चुनौती पर काम करने के लिए आवेदन कर सकता है।
- दुनिया भर में सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन क्लाउड प्रौद्योगिकी का उपयोग तेज और फुर्तीले तरीके से करने, समस्याओं का समाधान करने और नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं को बदलने के लिए करते हैं।
- क्लाउड इनोवेशन सेंटर्स (CIC) प्रोग्राम को चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को साथ लाकर, सार्वजनिक क्षेत्र में नवाचार के लिए उत्प्रेरक के रूप में तैयार किया गया है।
- भारत में स्थानीय उद्यम, स्टार्टअप, शोधकर्ता और विश्वविद्यालय AWS क्लाउड पर प्रोटोटाइप का प्रयोग और निर्माण करेंगे, और सामाजिक नवाचार में तेजी लाने के लिए समर्पित वैश्विक CIC समुदाय के साथ योगदान करेंगे।

महत्व –

- AWS के साथ नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर (CIC) भारत में सरकारी हितधारकों, स्टार्टअप्स और स्थानीय संगठनों को एक साथ लाएगा ताकि समस्याओं को हल करने के लिए नए दृष्टिकोणों का निर्माण किया जा सके।

आगे की राह

- भारत परिवर्तनकारी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का लाभ उठाने की उम्मीद कर रहा है, और देश में डिजिटल नवाचार में तेजी लाने के लिए वैश्विक अनुभवों को साझा करने के लिए तत्पर है।

नया अंतरिक्ष केंद्र

समाचार –

- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन को जर्मनी के रामस्टीन में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना है। केंद्र अंतरिक्ष अवलोकन के लिए एक समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करेगा है।
- नया अंतरिक्ष केंद्र उपग्रहों के संभावित खतरों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा और इसे रक्षात्मक उपायों के लिए कमांड सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकता है।

विवरण –

- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के अनुच्छेद 5 के आधार पर केंद्र की स्थापना की जा रही है।
- नाटो भी अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक थिंक टैंक स्थापित करने की परिकल्पना करता है। जर्मनी में कालकर और फ्रांस में टूलूज को संस्था के लिए संभावित स्थान माना जा रहा है।

> - फ्रांस के राष्ट्रपति ने पिछले साल जुलाई में एक सैन्य अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना की घोषणा की।
> - उन्होंने कहा कि रसद, निगरानी और संचार के लिए उपग्रहों पर बढ़ती निर्भरता, और सैन्य शक्तियों के विकास के साथ एंटी–सैटेलाइट सिस्टम का परीक्षण, अंतरिक्ष युद्ध के लिए एक नया थियेटर बन सकता है।
> - उपग्रह प्रणालियों पर हमले संचार नेटवर्क और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को कमजोर कर सकते हैं और साथ ही साथ जमीन पर काफी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।

- अमेरिका, रूस, चीन और भारत ने हाल के वर्षों में एंटी–सैटेलाइट सिस्टम विकसित किया है।
- लगभग 2,400 उपग्रहों में से अब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ 60% नाटो सदस्यों या इन देशों में स्थित कंपनियों के हैं।

नाटो का अनुच्छेद 5

- लेख संगठन को सामूहिक रक्षा कार्रवाई करने का अधिकार देता है। यह उपाय मानदंड प्रदान करता है जिसके तहत नाटो रक्षात्मक हो सकता है।
- नाटो द्वारा सीरिया संकट, रूस–यूक्रेन संकट और अमेरिका पर 26/11 हमले जैसी स्थितियों में अनुच्छेद 5 को लागू किया गया है।
- लेख में कहा गया है कि उत्तरी अमेरिका या यूरोप में नाटो देशों में से एक या अधिक के खिलाफ एक सशस्त्र हमले को उन सभी के खिलाफ हमला माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 पर आधारित इस परिदृश्य के तहत, अनुच्छेद 5 को लागू किया जा सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि किसी सदस्य को आत्मरक्षा में कार्य करने का अधिकार है और वह आगे आने वाले दलों पर हमला करने में सहायता करेगा। लेख सदस्य देशों को ऐसी स्थितियों में सशस्त्र बलों का उपयोग करने की भी अनुमति देता है। हालांकि, यह केवल उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा को बहाल करने और बनाए रखने के हित पर किया जाएगा।
- नोट – भारत को संधि पर हस्ताक्षर करना बाकी है।

आईएनएस कवरत्ती

समाचार –

- पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत (ASW) जहाज INS कवारत्ती ने विशाखापत्तनम में नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना में कमीशन किया।

कवरत्ती –

- यह एक छोटा युद्धपोत है। वे आमतौर पर तटीय गश्त और मिसाइल बोट और फास्ट अटैक क्राफ्ट के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

विशेषताएं –

- जहाज को चार डीजल इंजनों द्वारा 25 समुद्री मील से अधिक गति प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया है और इसमें 3,400 से अधिक समुद्री मील की दूरी पर धीरज है।
- 3,300 टन के विस्थापन के साथ, कवरत्ती की लंबाई 109.1 मीटर है और बीम पर 13.7–मी मापता है।
- कवरत्ती, अपने पूर्ववर्तियों की तरह 'फर्स्ट' का भी दावा करता है, जैसे रेल–कम हेलो ट्रैवर्सिंग सिस्टम, फोल्डेबल हैंगर दरवाजा।
- कवरत्ती में एक सामान्य बेड़ा घुड़सवार गियर बॉक्स और डीजल इंजन हैं, जो जहाज को बहुत कम विकिरणित पानी के नीचे का शोर देते हैं।
- कवरत्ती का लगभग 90% हिस्सा स्वदेशी है और जहाज परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध की स्थिति में लड़ने के लिए 'अच्छी तरह से सुसज्जित' है।

हाइलाइट्स/विशेषताएँ

- यह 'प्रोजेक्ट 28' के तहत चार स्वदेशी–निर्मित एएसडब्ल्यू में से एक है या नौसेना के कामोर्ता–श्रेणी के कोरवेट हैं। यह वर्तमान में नौसेना के साथ सेवा में ASWs का एक वर्ग है।
- 'प्रोजेक्ट 28' को 2003 में मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना के तहत अन्य तीन युद्धपोत आईएनएस कामोर्ता (2014 में कमीशन), आईएनएस कदमत (2016) और आईएनएस किल्टान (2017)।
- INS कावारत्ती में 90% तक स्वदेशी सामग्री है। इसे बनाने के लिए कार्बन कंपोजिट के उपयोग को भारतीय जहाज निर्माण में प्राप्त एक सराहनीय उपलब्धि के रूप में वर्णित किया गया है।'
- युद्धपोत को नौसेना के इन–हाउस संगठन, नौसेना डिजाइन निदेशालय (डीएनडी) द्वारा डिजाइन किया गया है।
- इस बीच, कोलकाता के गार्डन रिसर्च शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने इसे बनाया है।
- इसमें अत्याधुनिक हथियार और एक सेंसर है जो शत्रुतापूर्ण पनडुब्बियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। यह लंबी दूरी की तैनाती के लिए एक अच्छा जहाज भी है।
- इसने जहाज पर लगे अपने सभी प्रणालियों के समुद्री परीक्षण को पूरा कर लिया है और इसलिए, इसे युद्ध के लिए तैयार मंच के रूप में कमीशन किया जाएगा।
- INS कवरत्ती का नाम पुराने INS कावारत्ती से लिया गया है, जो अर्नला श्रेणी की मिसाइल कार्वेट थी जिसे 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान संचालित किया गया था।

प्रोजेक्ट 28/कामोर्ता–वर्ग कार्वेट

- कामोर्ट–क्लास कोरवेट वर्तमान में भारतीय नौसेना के साथ सेवा में मौजूद पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों का एक वर्ग है।
- वे भारत में निर्मित होने वाली पहली एंटी–सबमेरिन वारफेयर स्टिल्थ कॉरवेट हैं।
- परियोजना 28 को 2003 में 12 अगस्त 2005 को शुरू होने वाले प्रमुख जहाज आईएनएस कामोर्ता के निर्माण के साथ 2003 में मंजूरी दी गई थी।
- परियोजना का उद्देश्य भारत में युद्धपोत निर्माण उद्योग के स्थानीयकरण और विकास को बढ़ाना था।
- लक्षद्वीप द्वीपसमूह में द्वीपों के नाम पर लाशों का नाम रखा गया है।

- इस वर्ग के कोरवेट के प्लेटफॉर्म और प्रमुख आंतरिक प्रणालियों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- कामोर्ट क्लास कोरवेट का उद्देश्य पूर्ववर्ती और कोर क्लास कार्वेट द्वारा कोर–क्लास कार्वेट को सफल बनाना है।

नया अंग खोजा

समाचार –

- नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने प्रोस्टेट कैंसर पर एक शोध के दौरान मानव गले में एक नए अंग की खोज की है।
- नीदरलैंड्स कैंसर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने लार ग्रंथियों के एक सेट की पहचान गले के ऊपरी हिस्से में की है और उन्हें 'ट्यूबरियल लार ग्रंथियों' नाम दिया है।
- यह खोज कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

लार ग्रंथियां –

- स्तनधारियों में लार ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं जो नलिकाओं की प्रणाली के माध्यम से लार का उत्पादन करती हैं। मनुष्य की तीन जोड़ी प्रमुख लार ग्रंथियां (पैरोटिड, सबमांडिबुलर और सबलिंगुअल) हैं और साथ ही सैकड़ों छोटी लार ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियों को सीरस, 'लेष्म या सेरोमस (मिश्रित) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

विवरण –

- अब तक, यह नासोफरीनक्स क्षेत्र – नाक के पीछे का क्षेत्र – सूक्ष्म, लार ग्रंथियों के अलावा कुछ भी नहीं होने के बारे सोचा गया था।
- नई खोजी गई ग्रंथियां औसतन लंबाई में लगभग 1.5 इंच (3. 9 सेंटीमीटर) की होती हैं और यह उपास्थि के एक टुकड़े के ऊपर स्थित होती हैं जिसे टॉरस ट्यूबरियस कहा जाता है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, ग्रंथियां संभवतः नाक और मुंह के पीछे के ऊपरी गले को चिकना और नम करती हैं।
- अब तक, मनुष्यों में तीन ज्ञात बड़ी लार ग्रंथियां थीं – एक जीभ के नीचे, एक जबड़े के नीचे और एक जबड़े के पीछे, गाल के पीछे।
- नए अंग की खोज की गई जब वैज्ञानिक पीएसएमए पीईटी–सीटी तकनीक का उपयोग करके प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे थे – सीटी स्कैन और पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी (पीईटी) का संयोजन – जो लार ग्रंथि के ऊतकों का पता लगाने में अच्छा है। इस तकनीक में, एक रेडियोधर्मी 'ट्रेसर' को उस रोगी में इंजेक्ट किया जाता है जो प्रोटीन पीएसएमए से बांधता है, जिसे प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं में ऊठाया जाता है।
- सिर और गर्दन में कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी का उपयोग करने वाले डॉक्टर मुख्य लार ग्रंथियों से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें खाने, बोलने या निगलने में कठिनाई हो सकती है। हालाँकि, इस मामले में, नई खोजी गई ग्रंथियां विकिरण की चपेट में आ रही थीं क्योंकि डॉक्टरों को मानव शरीर में उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। इस प्रकार, नई खोज से कैंसर रोगियों के लिए कम दुष्प्रभाव हो सकते हैं।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020

समाचार –

- स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वायु प्रदूषण के बाद शिशु मृत्यु (1,16,000) का बोझ 67,900 (नाइजीरिया), 56,500 (पाकिस्तान), 22,900 (इथियोपिया) और 1,200 (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो) के बाद सबसे अधिक है।

मुख्य निष्कर्ष –

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2019 में दुनिया में सबसे ज्यादा पीएम 2.5 एक्सपोजर दर्ज किया।
- भारत के बाद नेपाल और नाइजर था।
- भारत शीर्ष 10 देशों में से एक है, जिसमें सबसे अधिक ओजोन जोखिम है।
- पिछले 10 वर्षों में भारत में ओजोन एकाग्रता में 17% की वृद्धि हुई है। विश्व स्तर पर ओजोन का जोखिम 47.3 भाग प्रति बिलियन से बढ़कर 49.5 भागों प्रति बिलियन हो गया है।
- भारत में उच्च वायु प्रदूषण के कारण सबसे अधिक शिशु मृत्यु हुई थी।
- वायु प्रदूषण 87 स्वास्थ्य जोखिम कारकों में से मौत का चौथा सबसे बड़ा जोखिम है।

झलकियाँ –

- अमेरिका स्थित स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ने शिशु स्वास्थ्य पर उच्च वायु प्रदूषण के प्रभाव का विश्लेषण करने वाली पहली ऐसी रिपोर्ट जारी की।
- यह अनुसंधान और साक्ष्य के बढ़ते शरीर पर आधारित है जो गर्भावस्था के दौरान माताओं को प्रदूषित हवा के संपर्क में आने का संकेत देता है जो जन्म के समय 2,500 ग्राम से कम वजन वाले शिशुओं के लिए बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है या जो गर्भधारण के 38 से 40 के विपरीत 37 सप्ताह में पैदा हुए थे।
- कम वजन और समय से पहले जन्म कम श्वसन पथ के संक्रमण, दस्त, अन्य गंभीर संक्रमणों के साथ–साथ मस्तिष्क क्षति और रक्त विकारों के एक उच्च जोखिम से जुड़ा होता है, पीलिया जो संभावित रूप से घातक हो सकता है।
- ऐसा माना जाता है कि वायु प्रदूषण एक गर्भवती महिला, उसके विकासशील भ्रुण, या दोनों तम्बाकू धूम्रपान के समान मार्ग के माध्यम से प्रभावित हो सकता है।
- वैश्विक रूप से वायु प्रदूषण के कारण होने वाली सभी नवजात मृत्यु के कारण, घरेलू वायु प्रदूषण में लगभग 64% का योगदान है। बाकी बाहरी वायु प्रदूषण के कारण थे।
- घरेलू वायु प्रदूषण (80%) के कारण होने वाली मौतों का उच्चतम प्रतिशत उप–सहारा क्षेत्र में होने का अनुमान था। निम्नतम उच्च आय वाले क्षेत्रों (2% से कम) में था।

- लंबे समय तक बाहरी और घरेलू वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से स्ट्रोक, दिल का दौरा, मधुमेह, फेफड़ों के कैंसर, पुरानी फेफड़ों की बीमारियों और पिछले साल भारत में नवजात रोगों से 1.67 मिलियन से अधिक वार्षिक मौतें हुईं, जिससे वायु प्रदूषण सभी स्वास्थ्य जोखिमों के बीच मौतों का सबसे बड़ा जोखिम कारक बन गया।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण से कोविड–19 संक्रमण और मृत्यु दोनों की अधिक संख्या हो सकती है।
- साक्ष्य तेजी से बताते हैं कि उच्च वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड–19 से अधिक गंभीर परिणामों का अनुभव होने की संभावना है।
- कोविड–19 महामारी से पहले भी, भारत ने पुरानी सांस और अन्य बीमारियों का भारी बोझ उठाया था और भारत ने लंबे समय तक उच्च जोखिम का भी अनुभव किया है।
- वायु प्रदूषण से मानव शरीर की प्रतिरक्षा को भी प्रभावित होते देखा गया है, जो निमोनिया जैसे श्वसन संक्रमण के प्रति व्यक्ति को अधिक संवेदनशील बनाता है।

एन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) 2020 की वार्षिक स्थिति

समाचार –

- एन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ((एएसईआर) 2020 (रूरल) वेव 1 – पहला फोन आधारित सर्वेक्षण है – जो कोविड–19 के प्रकोप के बीच में आया है।
- एएसईआर 2020 का आयोजन 26 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया था।
- सर्वेक्षण में 118,838 परिवारों को शामिल किया गया, जहां पांच से 16 साल की उम्र के बच्चों के माता–पिता को फोन किया गया।
- कुल मिलाकर, 8,963 शिक्षकों की प्रतिक्रियाएँ भी सर्वेक्षण में दर्ज की गईं।

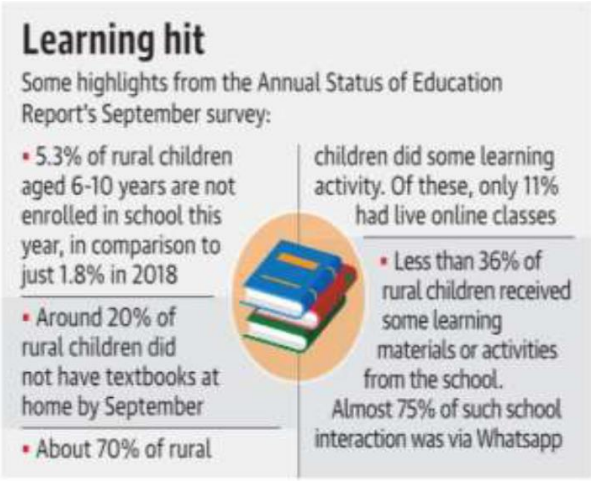

लक्ष्य –

- रिपोर्ट का उद्देश्य भारत के प्रत्येक जिले और राज्य के लिए बच्चों के नामांकन और बुनियादी सीखने के स्तर का विश्वसनीय आकलन प्रदान करना है।

एएसईआर में निम्न क्षेत्र शामिल हैं –

- बच्चों का नामांकन
- बच्चे वर्तमान में नामांकित नहीं हैं
- घरेलू संसाधन
- घर पर सीखने का समर्थन
- शिक्षण सामग्री तक पहुंच

मुख्य निष्कर्ष –

- ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए गए लगभग 50% शिक्षकों ने प्रशिक्षण के किसी भी रूप को प्राप्त नहीं किया और 68.8% ने संक्षिप्त निर्देशों के आधार पर पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- एएसईआर 2018 के आंकड़ों की तुलना में, एएसईआर 2020 के डेटा निजी से सरकारी स्कूलों में, सभी ग्रेडों और लड़कियों और लड़कों के बीच नामांकन में एक छोटी सी पारी दिखाते हैं।
- सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कों का अनुपात 2018 में 62. 8% से बढ़कर 2020 में 66.4% हो गया।
- इसी अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कियों का अनुपात 70% से बढ़कर 73% हो गया।
- एएसईआर 2020 बताता है कि 2018 में 5.5 प्रतिशत बच्चे वर्तमान में 2020–21 स्कूल वर्ष के लिए नामांकित नहीं हैं। यह अंतर सबसे कम उम्र के बच्चों (6 से 10 वर्ष की उम्र) में सबसे तेज है, संभवतः इसलिए कि उन्होंने नहीं किया है अभी तक स्कूल में प्रवेश सुरक्षित है। जबकि 2018 में इस आयु वर्ग के 1.8 प्रतिशत बच्चों का नामांकन नहीं किया गया था, जो कि 5.3 प्रतिशत हो गया है।
- नामांकित बच्चों में, 61.8 प्रतिशत परिवारों में रहते हैं, जिनके पास कम से कम एक स्मार्टफोन है।
- लगभग 75 प्रतिशत बच्चों ने कहा कि उन्हें परिवार के सदस्यों से सीखने का समर्थन मिला है, जिनमें बड़े भाई–बहन खेल रहे हैं महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं।

एएसईआर सर्वेक्षण –

- यह एक वार्षिक सर्वेक्षण (शिक्षा गैर–लाभ प्रथम द्वारा प्रकाशित) है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक जिले और राज्य के बच्चों के नामांकन और बुनियादी सीखने के स्तर का विश्वसनीय अनुमान प्रदान करना है।
- एएसईआर भारत के सभी ग्रामीण जिलों में 2005 से हर साल आयोजित किया जाता है। यह भारत में सबसे बड़ा नागरिक नेतृत्व वाला सर्वेक्षण है।
- यह भारत में उपलब्ध बच्चों के सीखने के परिणामों के बारे में जानकारी का एकमात्र वार्षिक स्रोत भी है।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम

समाचार –

- कैबिनेट ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी।

मुख्य विशेषताएं –

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 दिसंबर 2020 से से 30 नवंबर 2021 तक इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2020–21 के दौरान आगामी गन्ना सीजन 2020–21 के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत विभिन्न गन्ना आधारित कच्चे माल से प्राप्त उच्च इथेनॉल मूल्य तय करने को मंजूरी दी है।

- साथ ही, सी हैवी गुड़, बी हैवी गुड़ से प्राप्त इथेनॉल की कीमतों में वृद्धि की गई है। मूल्य में वृद्धि लगभग 2 से 3 प्रति लीटर थी। इसके अतिरिक्त, तेल कंपनियों को इथेनॉल की खरीद करते समय परिवहन शुल्क और GST का भुगतान करना होगा।
- गन्ना किसानों की कठिनाई को कम करने में योगदान देने में, इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को पारिश्रमिक मूल्य गन्ना किसान के बकाया को कम करने में मदद करेगा।

पृष्ठभूमि –

- सरकार इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम को लागू कर रही है जिसमें OMCs पेट्रोल को 10% तक इथेनॉल के साथ बेचती है।
- इस कार्यक्रम को अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में विस्तारित किया गया है।
- ऐसा तेल आयात से भारत की ऊर्जा निर्भरता को कम करने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके अलावा, ईबीपी कार्यक्रम के तहत इथेनॉल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को अपनाया गया था।
- 2018 में, पहली बार, भारत सरकार ने उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर इथेनॉल की प्रशासित कीमत को अधिसूचित किया।

गन्ना विशिष्ट क्यों है?

- किसानों को भुगतान करने के लिए चीनी उद्योग की क्षमता कम होने से गन्ना किसानों का बकाया बढ़ गया है।
- इस प्रकार, भारत सरकार ने गन्ना किसानों की सहायता के लिए गन्ने से प्राप्त इथेनॉल की कीमतों में वृद्धि की है।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम –

- इथेनॉल मिश्रित मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम जनवरी, 2003 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात निर्भरता को कम करने की मांग की गई थी।
- कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार ने 2022 तक 10% सम्मिश्रण लक्ष्य और 2030 तक 20% का लक्ष्य रखा है।
- तेल विपणन कंपनियां भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के आधार पर इथेनॉल आधारित पेट्रोल बेचने के लिए बाध्य हैं।

योजना एवं कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं को सारांश

कोविड महामारी के बाद विश्व –

- विश्व अर्थव्यवस्था ने 2020 में कोविड–19 महामारी के कारण एक बड़े संकट का अनुभव किया। यह 1930 के महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका है।

बारबेल रणनीति –

- मार्च 2020 में वापस, कोविड–19 के बारे में बहुत कम जाना गया था कि चीन के वुहान में एक बड़ा प्रकोप हुआ था, और अचानक उत्तरी इटली में इससे बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी। ऐसे संकेत भी थे कि यह तेजी से दूसरे देशों में फैल रहा है।
- दुनिया भर की सरकारों द्वारा परामर्शी महामारी विशेषज्ञों ने व्यापक मूल्यांकन प्रदान किया। कुछ ने झुंड प्रतिरक्षा की वकालत की।
- जबकि अन्य लोगों ने लाखों लोगों की मृत्यु की भविष्यवाणी की।
- जब तक कि कुछ कठोर नहीं हुआ, भारतीय नीति–निर्माता, परिणामस्वरूप, अत्यधिक अनिश्चितता के तहत निर्णय ले रहे थे, जबकि यह जानते हुए कि 1.35 बिलियन लोगों के साथ बाद में सही तरीके से संभव नहीं होगा।
- केंद्र सरकार ने वित्तीय बाजारों में प्रचलित 'बारबेल' रणनीति का चयन किया – यानी कि जानकारी के बेयसियन अपडेट के साथ कदम–दर–कदम आगे बढ़ते हुए सबसे खराब–संभव परिणाम के लिए पहले बचाव किया जाए।
- प्रारंभिक कुल लॉकडाउन, इसलिए, सबसे खराब संभावित परिणामों के खिलाफ बचाव के रूप में देखा जाना चाहिए। यह कुछ विशेषज्ञों की सलाह से उछला था जिन्होंने तर्क दिया था कि एक मजबूत प्रारंभिक लॉकडाउन एक प्रारंभिक चरण में महामारी को रोक सकता है (यह उपलब्ध जानकारी नहीं दी गई एक अनुचित विचार नहीं था)। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस प्रारंभिक लॉकडाउन ने उपकरण, संगरोध और परीक्षण क्षमता के मामले में एक बड़े पैमाने पर चिकित्सा प्रतिक्रिया की व्यवस्था करने के लिए भी जगह दी।
- समय बीतने के साथ–साथ केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था के कदम–दर–कदम जानकारी के साथ–साथ औसत दर्जे की क्षमता को भी अनलॉक किया।
- हुआ। लॉकडाउन और अन्य प्रतिक्रियाएं तेजी से स्थानीय सरकारों के लिए छोड़ दी गईं।
- आर्थिक प्रतिक्रिया में समान बारबेल रणनीति का उपयोग किया गया था। लॉकडाउन चरण के दौरान भारतीय आर्थिक प्रतिक्रिया समाज के सबसे कमजोर वर्गों और (जैसे मध्यम और छोटे उद्यमों) को एक तकिया प्रदान करने की दिशा में अधिक उन्मुख थी। यह खाद्य उपलब्धता, जन धन खातों में नकद हस्तांतरण, सरकार द्वारा छोटे उद्यमों को ऋण की गारंटी, अधिस्थगन और वित्तीय समय सीमा को स्थगित करने पर जोर देता है।
- अक्टूबर की शुरुआत में ज्यादातर अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ, अब एक उचित मांग उत्तेजना के लिए एक मामला है जिसमें बुनियादी ढांचा निवेश केंद्र–चरण में ले जा रहा है। राजकोषीय घाटे के चौड़ीकरण के बावजूद मौद्रिक और राजकोषीय दोनों क्षेत्र इस धक्के के लिए मौजूद हैं।
- मांग – चालित मुद्रास्फीति एक प्रमुख मुद्दा नहीं है क्योंकि लगभग सभी मूल्य वृद्धि सराहना के कारण होती है और एक चालू खाता अधिशेष विदेशी मुद्रा भंडार (सितंबर के अंत में यूएस $545 बिलीयन पर खड़े) खिला रहा है, एक विस्तारवादी मौद्रिक गतिरोध के प्रसारण की अनुमति देने के लिए जगह है भारत की वित्तीय प्रणाली पर राज करने के लिए।

कोविड–पश्चात् दुनिया में अनुकूलन

- कोविड–19 महामारी पीढ़ियों में सबसे बड़ा वैश्विक व्यवधान है। इस संकट से उभरने वाली कोविड–पश्चात् दुनिया कोविड–पूर्व दुनिया का हल्का–बदला संस्करण नहीं होगी, बल्कि इस नई दुनिया की अपनी भू–राजनीति, आपूर्ति श्रृंखला, टेक्नोलॉजिकल नवाचार, संस्थागत संरचनाएं, उपभोक्ता वरीयता और इसी तरह होगी। ये सभी कारक कई, अप्रत्याशित तरीकों से बातचीत करेंगे। इसलिए, इस बारे में भव्य भविष्यवाणियां करना बहुत मुश्किल है कि कोविड–पश्चात् दुनिया कैसे कार्य करेगी।

- कठोर–योजनाबद्ध प्रतिक्रिया में निवेश करने के बजाय, दो चीजों में निवेश करना बेहतर है – लचीलापन (फ्लेक्सीबिलीटी) और लचीलापन (रिसीलियंस)।
- कृषि क्षेत्र में हुए सुधारों ने किसानों को अपनी उपज बेचने की सुविधा दी है, जबकि आपूर्ति श्रृंखला में शामिल लोग 'जमाखोर' कहे जाने के डर के बिना निवेश कर सकते हैं। यह कृषि क्षेत्र और कृषि से संबंधित उद्योगों को जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ता स्वाद और इतने पर बदलने के लिए अपनी गतिविधियों को अनुकूलित करने के लिए होगा। भारत के पास खेती योग्य भूमि का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, एक कारण यह है कि यह कृषि में एक निर्यात ऊर्जाघर नहीं होना चाहिए।
- इसी तरह, दर्जनों केंद्रीय श्रम कानूनों को आंतरिक रूप से सुसंगत कोड में घटा दिया गया है। एक तरफ वे सुरक्षा और काम की परिस्थितियों से संबंधित कानूनों को मजबूत करते हैं, दूसरी तरफ वे नियोक्ताओं को अधिक लचीलेपन की अनुमति देते हैं।
- फिर, यह एक अप्रत्याशित, उभरती हुई कोविड पश्चात् दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है जहां अर्थव्यवस्था को बदलती परिस्थितियों के अनुसार कार्यबल को कुशलतापूर्वक पुनर्निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए।
- हाल ही में द्विपक्षीय नेटिंग और ट्रेड फाइनेंस फैक्टरिंग से संबंधित अन्य सुधारों की घोषणा भी सीधे वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई है।
- लंबी अवधि के पोस्टकोविड ढांचे के अन्य घटक लचीलेपन पर जोर है।
- यह 'आत्मनिर्भर भारत' या आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को समझने की कुंजी है।
- आत्मनिर्भरता का मुख्य विचार यह है कि भारत को अपनी आंतरिक शक्तियों का लाभ उठाकर अधिक लचीला बनना चाहिए। इसे अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के बारे में भी दृढ़ होना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत सरकार ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) से बाहर रहने का फैसला किया।
- जैसा कि यह महसूस किया गया कि व्यापार व्यवस्था राष्ट्रीय हित के लिए नहीं थी। इसी तरह, भारत की विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी दवा उद्योग को आपूर्ति लाइनों के साथ महत्वपूर्ण आयातित इनपुट में बहुत अधिक निर्भर होना पाया गया, जिसे आसानी से बाधित किया जा सकता है (जैसा कि हाल ही में महामारी के दौरान हुआ था)। इसलिए, इनपुट उत्पादन को भारत में वापस लाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है।
- आगे देखते हुए, अप्रत्याशित समस्याओं और उत्तरोत्तर समस्याओं के लचीले जवाब के बाद – कोविड पश्चात् दुनिया को दो और क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता होगी।
- दोनों मामलों में, एक पुरातन कठोर प्रणाली इक्कीसवीं सदी की जरूरतों से निपटने में असमर्थ है। कुछ सुधार अब प्रशासनिक सुधारों, ऑनलाइन अनुप्रयोगों के उपयोग और अयोग्य सरकारी निकायों के युक्तिकरण पर किए जा रहे हैं। न्यायपालिका के साथ साझेदारी में इसी तरह का प्रयास, 36 मिलियन लंबित मामलों के साथ कानूनी प्रक्रिया को उन्नत करने के लिए किया जाना चाहिए। इस तरह की बहस सुधार के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आगे बढ़ने के लिए एक गैर–पक्षीय राष्ट्रीय सहमति बनाने में मदद कर सकती है।

निष्कर्ष –

- एक 'बारबेल रणनीति' के आधार पर, भारत की आर्थिक और स्वास्थ्य प्रतिक्रिया विभिन्न उपायों के क्रम और जोर देने के मामले में अन्य देशों की तुलना में कुछ हद तक अलग है।
- चक्र अभी पूरी तरह से चला नही है, लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अनलॉक हो जाती है, बुनियादी ढांचा निवेश का उपयोग करके मांग को उत्तेजित करने की ओर जोर जाएगा।
- हालाँकि, दीर्घावधि प्रतिक्रिया का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड के बाद के अवसरों और समस्याओं से निपटने के लिए अधिक लचीला बनाना है।

अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार –

- कोविड–19 के कारण दुनिया को अभूतपूर्व आघात और आर्थिक गतिविधियों के अचानक रोकने के साथ, ऐसी उम्मीदें हैं कि उत्पादन का स्थायी नुकसान हो सकता है। भारत में, महामारी की स्थिति अभी भी विकसित हो रही है, सभी एजेंसियों द्वारा विकास पूर्वानुमान लगभग–10% के मध्य के पूर्वानुमान के साथ नकारात्मक रहे हैं। हालांकि, कोई आधिकारिक पूर्वानुमान नहीं हैं, बाद में, भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि जीडीपी 9.5% से सिकुड़ेगी।
- पूर्व–कोविड–19 स्थिति, जीडीपी वृद्धि 2019–20 में भी पहले ही मंदी के दौर में थी। इसने 4.1% की वृद्धि दर्ज की है, जो एक दशक में सबसे कम थी।
- राजकोषीय स्थिति केंद्र सरकार के साथ लगातार दो साल तक FRBM (संशोधन) अधिनियम 2018 में पलायन खण्ड को लागू करने के साथ और भी अनिश्चित थी, जो सरकारों को अधिनियम में निर्दिष्ट की तुलना में 0.5% अधिक राजकोषीय घाटे को चलाने की अनुमति देती है।
- केंद्रीय बजट 2020–21 में 2019–20 के लिए राजकोषीय घाटा 3.8% और 2020–21 के लिए 3.3% का सुझाव दिया गया।
- सरकारी खातों के नियंत्रक से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 2019–20 के लिए भी राजकोषीय घाटा 3.8% के अनंतिम अनुमान के मुकाबले 4.6% रहने की उम्मीद है।
- राज्य सरकारों की ओर से, अधिकांश अध्ययनों से पता चलता है कि राज्यों में राजकोषीय स्थिति केवल राज्यों के उच्च विचलन के बावजूद 2015–16 के बाद से खराब हो गई है।
- 2019–20 की अंतिम तिमाही में, जीडीपी की वृद्धि दर 3.1% थी और 2020–21 की पहली तिमाही में –23.9% की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई।
- जबकि स्वयं द्वारा महामारी इस तरह की तीव्र मंदी का नेतृत्व नहीं कर सकती थी, यह भारत में पहली तिमाही में अपनाए गए सबसे कठोर लॉकडाउन के कारण है, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियों में अचानक रोक लगी है।
- धीरे–धीरे गतिविधियों के खुलने के साथ सितंबर 2020 के अंत से कुछ आशा दिखी।
- अब, नीति प्रतिक्रियाएं और विकास पर इसका प्रभाव कुछ ऐसा है जो देखने में दिलचस्प हो सकता है।
- आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दरों में तेजी से कमी की है और बाजार में अधिक तरलता को भी पंप किया है।
- RBI ने ऋण मोचन और अन्य उपाय जैसे कि राज्य सरकारों को बढ़ते हुए तरीके और साधन अग्रिम (WMA), ऋण गारंटी योजनाएं कई अन्य क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के बीच ऋण प्रतिबंध समिति को पेश किये है।

- मौद्रिक नीति के मोड़ के साथ, हाल की अवधि में मौद्रिक नीति संचरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की, जो बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा थे।
- पैकेज चार एल के बारे में बात करता है – लैंड (भूमि), लेबर (श्रम), लिक्वीडीटी (तरलता) और लॉ (कानून), इन सभी क्षेत्रों में अधिक संरचनात्मक सुधारों के साथ। पैकेज का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है और MSMEs, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, प्रवासी श्रमिकों, नागरिक उड्डयन, रक्षा, ऊर्जा, आवास और सामाजिक क्षेत्र को सहायता प्रदान करना है जो महामारी के साथ–साथ लॉकडाउन से भी प्रभावित हैं।
- प्रधानमंत्री ने इस पैकेज के पांच स्तंभों का भी सुझाव दिया और वे हैं – अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड।
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, खाद्य सुरक्षा, एमजीएनआरईजीएस के तहत ग्रामीण रोजगार, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना जैसे व्यापक हस्तक्षेप शामिल हैं।
- पैकेज में तरलता उपायों के तहत प्रदान किए गए मौद्रिक प्रोत्साहन शामिल हैं जो 8.01 लाख करोड़ रुपये के हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में समर्थन की सीमा का सुझाव है कि भारत का हस्तक्षेप जापान और अमेरिका को छोड़कर अधिकांश देशों के लिए व्यापक और तुलनात्मक है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्रेडिट गारंटी, खाद्य सुरक्षा, नौकरी, गरीबी–विरोधी कार्यक्रम (PMGKY), आदि से कई हस्तक्षेप शामिल हैं।
- हालांकि, इस पैकेज के संबंध में एक आलोचना यह है कि इस पैकेज की राजकोषीय लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15% है क्योंकि उनमें से अधिकांश मौद्रिक प्रोत्साहन और क्रेडिट गारंटी शामिल हैं। यह बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन की मांग के खिलाफ खड़ा है जिसे जीडीपी वृद्धि में तेज संकुचन शामिल करने के लिए फ्रंट–लोड किए जाने की आवश्यकता है।

स्व–रिलायंस इंडिया –

- सरकार द्वारा 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जारी की गई थी। नीति के मुख्य उद्देश्य थे –
  - (ए) मध्यम अवधि में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को 12–14% तक बढ़ाना
  - (बी) 2022 तक GDP में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना
  - (सी) विनिर्माण डोमेस्टिक्स मूल्य संवर्धन और विनिर्माण में तकनीकी गहराई के निर्माण में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार पैदा करना।
- भारत की औद्योगिक नीति में वर्षों से शामिल है, और समय की आवश्यकताओं के आधार पर प्रासंगिक परिवर्तन पेश किए गए हैं।
- स्वतंत्रता के समय, संसाधन बाधाओं का निर्धारण किया गया था जहां संसाधनों को आवंटित किया गया था, और पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था। विकास को सार्वजनिक क्षेत्र का नेतृत्व करना था, ताकि भविष्य के लिए एक ध्वनि औद्योगिक बनाया जा सके।
- औद्योगिक नीति 1991 एक चुनौती के जवाब में थी, और एक से संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित परिवर्तन किए गए थे।
- **राज्य** – एक उदार और वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के लिए विनियमित अर्थव्यवस्था, समय के साथ, नीति मंडलियों पर हावी होने वाली सोच यह थी कि सरकार, क्षेत्रों में सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय, प्रतिस्पर्धा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक सूत्रधार की भूमिका निभानी चाहिए।

कोविड–19 के कारण पुर्नविचार

- यह सोच कि सरकार को निवेश के निर्देशन में अपनी भूमिका को कम करना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में बाजार की शक्तियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कोविड–19 महामारी के प्रकाश में एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
- इस दृष्टिकोण के जोखिम इस तथ्य के कारण सामने आए हैं कि भारत न केवल चिकित्सा आपूर्ति, उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स के लिए, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायन जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी कुछ देशों पर निर्भर है।
- सरकार ने आत्मनिर्भर भारत आंदोलन की भी घोषणा की है। इसके पीछे का विचार आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए कई उपायों और प्रोत्साहनों के माध्यम से आर्थिक क्षमताओं और क्षमताओं का पुनर्निर्माण करना है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण घटकों के आयात पर।
- आमतौर पर, एक औद्योगिक नीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी, विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा जैसे विभिन्न नीति उपकरण शामिल होते हैं।
- पूंजी की अधिमानी पहुंच, सार्वजनिक खरीद की गारंटी, और उत्पादन, और आयात–निर्यात निर्णयों पर सरकार से आदेश कोविड–पश्चात् दुनिया में एक औद्योगिक नीति के अनुसरण घटक हो सकते हैं।

कोविड पश्चात् विश्व में निम्न घटक होना चाहिए –

- दुनिया के लिए 'मेक इन इंडिया' नारे को विश्व स्तर के गुणवत्ता मानकों से परिभाषित करने की आवश्यकता। उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख चालक है। वर्षों से, भारत में मानकों और तकनीकी विनियमन पारिस्थितिकी तंत्र ने वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल नहीं रखा है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजारों के साथ–साथ घरेलू उत्पादकों के लिए भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो सस्ते या घटिया आयात का सामना कर रहे हैं। घरेलू मानक और तकनीकी विनियमन पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं के साथ संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिशा में किए जाने वाले कुछ उपाय निम्नलिखित हैं –
  - ए. यदि आवश्यक हो तो निकायों को स्थापित उद्योग संचालित मानकों का उपयोग करके उद्योग को स्वैच्छिक मानकों के निर्माण और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - बी. मानकीकरण (आईएसओ), अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) और अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे निकायों की स्थापना में अंतरराष्ट्रीय मानकों की पहचान विशेषज्ञों की नियमित भागीदारी एवं कोडेक्स।
  - सी. घरेलू, निजी क्षेत्र की भागीदारी के परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना।
- बुनियादी ढांचे में सुधार और रसद लागत को कम करना, जो आपूर्ति पक्ष से काम करेगा और इस प्रकार उत्पादन लागत को कम करने में मदद करेगा।
- विश्व स्तर पर भारतीय विनिर्मित उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना।
- व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) एक अन्य प्रमुख क्षेत्र है जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

ए. वास्तविक ईओडीबी को राज्य सरकारों और जिला प्राधिकरणों के संचालन में झूठ बोलना चाहिए, जहां व्यापार किया जाता है। राज्य सरकारों को प्रतिस्पर्धात्मकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिला स्तर पर ईओडीबी की तर्ज पर जिलों को रैंक करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है संघवाद बेहतर परिणामों के लिए अग्रणी है।

बी. नियामक प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक संस्थागत तंत्र होना चाहिए, जो नए नियमों का एक उद्देश्य मूल्यांकन प्रदान करेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य उद्योग पर विनियामक अनुपालन के समग्र बोझ में पर्याप्त शुद्ध कमी को प्राप्त करना होगा।

सी. स्थिर और पूर्वानुमेय नीति शासन व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाता है, और यह ईओडीबी के केंद्र में भी है।

- भारत में उद्योग की तकनीकी उन्नति ने कई अन्य विनिर्माण देशों के साथ तालमेल नहीं रखा है। उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपग्रेड करने और वैश्विक और भारतीय नवप्रवर्तकों से भारतीय उद्योग में प्रौद्योगिकी के आसानी से हस्तांतरण के लिए भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करने की एक मजबूत आवश्यकता है। उद्योग 4.0 अवसर प्रदान करता है, जैसे कि उत्पादकता में वृद्धि, कम अपशिष्ट और बढ़ी हुई दक्षता लेकिन गोद लेने की लागत और संभावित नौकरी के नुकसान के बारे में भी चिंताएं हैं। डिजिटलीकरण का समर्थन करने और उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुंच को आसान बनाने के उपाय उद्योग को वैश्विक स्तर पर छलांग लगाने और पकड़ने में मदद करेंगे।

  ए. डिजिटलीकरण विघटनकारी प्रौद्योगिकियों की अगली लहर के लिए आधार बनाता है, और भारत एक अभूतपूर्व गति से डिजिटलीकरण कर रहा है। डिजिटलीकरण को अपनाने से राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना, मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था और कृषि, स्मार्ट शहरों, परिवहन सेवाओं, लॉजिस्टिक्स, अनटाइटी डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि सहित क्षेत्रों में उन्नत तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए बाजार पहुंच को आसान बनाने जैसे उपायों के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है।

  बी. तकनीकी प्राप्ति के माध्यम से उत्पादकता में निरंतर वृद्धि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए मौलिक है। जबकि नवाचार और प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास पर जोर महत्वपूर्ण है, माल के उत्पादन के लिए कई स्मार्ट प्रौद्योगिकी और सेवाओं को कहीं और विकसित किया गया है और इसका विकास भी जारी रहेगा। इन उन्नत और स्मार्ट तकनीकों को प्राप्त करने और आगे के विकास के लिए आर्थिक समझ है।

- यह पहले कुछ रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान करके किया जा सकता है जहां अधिग्रहण के लिए प्रौद्योगिकियों को लक्षित किया जा सकता है। प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण का समर्थन करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ एक प्रौद्योगिकी तैनाती कोष बनाया जा सकता है।
- नए पोस्ट–कोविड 19 आर्थिक स्थितियों और वास्तविकताओं के लिए व्यवसाय तैयार करने वाले उपायों को लागू करना।

  ए. फर्मों को व्यापार करने के वैकल्पिक साधनों के लिए झारना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं, वेब उपस्थिति में सुधार, सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन, ग्राहक सेवा कार्यों को ऑनलाइन बढ़ाने और ईकॉमर्स में संलग्न होना।

  बी. व्यापारिक सहायता संगठन जैसे चैंबर ऑफ कॉमर्स और सेक्टर एसोसिएशन व्यवसायों के बीच मध्यस्थ होने की भूमिका निभा सकते हैं। वे फर्मों को एक साथ ला सकते हैं और व्यापार का मिलान कर सकते हैं। अवसर, जो बदले में खरीदारों/विक्रेताओं दोनों के लिए लागत को कम कर सकते हैं और पैमाने की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं।

सरकार द्वारा हाल ही में कोविड–19 महामारी के मद्देनजर इस दिशा में किए गए उपाय

- सरकार ने उपर्युक्त मानकों के आसपास विभिन्न उपायों को किया है।
- यह अभी भी प्रगति पर एक काम है क्योंकि कोविड–19 का आर्थिक प्रभाव अभी भी घरेलू और वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहा है।
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना

  ए. मेक इन इंडिया 2.0 लाइन मंत्रालयों के परामर्श से 15 चैंपियन क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल और अपेरल्स, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, चमड़ा और जूते आदि के घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

  बी. मोबाइलों और इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में कई उत्पादन जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अधिक क्षेत्रों को उपयुक्त रूप से प्रोत्साहन देने वाले उद्योग के लिए माना जाएगा।

  सी. चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) सेलुलर मोबाइल हैंडसेट और वाहन के संचालन में है। नीति आयोग ने PMP के कार्यान्वयन के लिए LED लाइट्स, नेटवर्क उत्पाद, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्युटिकल ड्रग्स और मानव निर्मित फाइबर की पहचान की है।

  डी. उद्योग के परामर्श से बीस क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।

  ई. मेक इन इंडिया और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, डीपीआईआईटी ने अपनी सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया के लिए वरीयता) उन परिवर्तनों के साथ जो अधिक से अधिक घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देंगे के साथ संशोधित किया है।

  एफ. आयात वृद्धि, सस्ते आयात और घरेलू विनिर्माण का समर्थन करने के मुद्दे को हल करने के लिए, सरकार ने हाल के महीनों में विभिन्न आयात प्रतिबंधों को प्रभावित किया है। प्रतिबंध से अलग है (i) मूविंग आइटम फॉर्म तिवउ फ्रीय पाम तेल, पामोलिन, टायर, टीवी सेट जैसे प्रतिबंधित श्रेणीय (ii) आयात निगरानी प्रणालीय (iii) मुख्य रूप से मटर, उड़द दाल, आदि जैसे कृषि उत्पादों के लिए आयात कोटा तय करना (iv) प्रयोगशाला परीक्षण के लिए नमूनों का यादृच्छिक चयन, जैसे खिलौने, गुड़िया आदि।

- घरेलू विनिर्माण, निवेश और प्रौद्योगिकी संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करना

  ए. भारत सरकार की यह लगातार कोशिश रही है कि वह एक सक्षम और निवेशक–अनुकूल एफडीआई नीति लागू करे। एफडीआई नीति को अधिक निवेशक–अनुकूल बनाने, इसे राष्ट्रीय हित के साथ संरेखित करने और देश में निवेश की बाधा में बाधा डालने वाली नीतिगत बाधाओं को दूर करने का इरादा किया गया है।

बी. सरकार एफडीआई को आकर्षित करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए काम कर रही है, विशेष रूप से विदेशी कंपनियों के लिए जो अपने विनिर्माण आधार में विविधता लाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए देख रहे हैं। फोकस देशों के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दो–गुना दृष्टिकोण अपनाया गया हैय (प) भारत में अपने निवेश ध विस्तार योजनाओं को जानने के लिए एक से एक बैठकें आयोजित करना और जहाँ कहीं भी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना हैय और (पप) उनके मौजूदा परिचालनों के संदर्भ में मुद्दों को हल करना।

सी. सरकार ने भारत में निवेश को सुगम बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए भारत सरकार के एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) और परियोजना विकास प्रकोष्ठों (पीडीसी) द मंत्रालयों ध विभागों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ईजीओएस का उद्देश्य नीतिगत स्थिरता के साथ–साथ विभिन्न विभागों ध मंत्रालयों, निवेश सहायता और सुविधा से समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करना होगा।

- प्रशासनिक मंत्रालयों में पीडीसी निवेश योग्य परियोजनाओं की एक पाइपलाइन बनाएंगे।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स

ए. सरकार ने कार्यान्वयन के तहत लगभग 44 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के साथ 111 लाख करोड़ रुपये (टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार) की परियोजनाओं को कवर करने वाली एक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) का अनावरण किया है।

बी. सरकार एक राष्ट्रीय रसद नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जिसका उद्देश्य रसद लागत में उल्लेखनीय कमी लाना है।

निष्कर्ष –

- वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की हिस्सेदारी अन्य तुलनात्मक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। उपरोक्त उपायों में आपूर्ति–श्रृंखला लचीलापन, पीएमपी और पीएलआई योजनाओं को कई उत्पादों में शामिल करना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और गुणवत्ता की दिशा में निरंतर अभियान और घरेलू क्षमता को बढ़ावा देना भारत के लिए जीवीसी में अपनी छाप छोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) द्वारा निर्मित आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण केंद्रों में विविधता लाने के लिए बनाए गए अवसर का लाभ उठाने में भी सक्षम होगा। इस प्रकार, परिणाम केवल घरेलू सीमाओं के भीतर सीमित नहीं होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा दोहराए गए 'मेक इन इंडिया' के सपने को दुनिया के लिएश साकार करने की भी सुविधा प्रदान करेंगे।

रोजगार के लिए SANKALP –

- कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों का उल्टा प्रवास, कई राज्यों के जनांकिकीय लाभांश के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती प्रस्तुत करता है।
- उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ, लाखों प्रवासी श्रमिकों की संख्या लाखों में होने की उम्मीद है, स्थानीय रोजगार प्रदान करने के लिए उनके गृह राज्यों की तैयारियों को परखा जा रहा है।
- इस चुनौती के मद्देनजर, कई राज्यों की सरकारों ने विस्तृत व्यवस्था की घोषणा की है। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में रिटर्नर्स और उनके कौशल के स्तर को पंजीकृत करना और नौकरी के अवसरों को टालना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी घोषणा की गई है।
- यह स्पष्ट है कि रोजगार के अवसरों की शीघ्र पहचान और जिलों के स्तर पर कौशल आवश्यकताओं की आशंका के लिए जमीनी स्तर पर पर्याप्त क्षमता का निर्माण एक परिणाम केंद्रित कौशल प्रशिक्षण प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत में 487 लाख श्रमिक हैं और हर महीने दस लाख से अधिक श्रमिक शामिल होते हैं।
- हालांकि, लगभग दो–तिहाई भारतीय नियोक्ताओं की रिपोर्ट है कि वे श्रमिकों को सही कौशल के साथ खोजने के लिए संघर्ष करते हैं।
- विश्व आर्थिक मंच की मानव पूंजी विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 122 देशों की सूची में 78 वें स्थान पर है।
- हाल के वर्षों में कौशल विकास कार्यक्रम चलाने वाले कम से कम 20 सरकारी विभागों के साथ, भारत को इससे बेहतर काम करना चाहिए।
- कौशल विकास का परिणाम, शिक्षा के विपरीत, नियोक्ताओं और समाज के साथ भिन्न होता है।
- कौशल विकास में निवेश पर वापसी प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के अवसरों और काम की दुनिया के लिए एक चिकनी संक्रमण के लिए आसान पहुंच पर निर्भर करता है। इसलिए, कौशल प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मौजूदा और संभावित मांग, प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं और नियोक्ताओं का एक एकीकृत दृष्टिकोण रखना चाहिए।
- भारत की जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक और संसाधन विविधता को ध्यान में रखते हुए, पारिस्थितिक तंत्र जैसे स्थान पर रखना एक लंबे समय तक चलने वाली परियोजना बनी रहेगी।

संकल्प –

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वर्ल्ड बैंक समर्थित कार्यक्रम – SANKALP (कौशल विकास और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता) को बढ़ावा देने के लिए, कौशल और योजना के कार्यान्वयन के विकेंद्रीकरण के लिए रोल आउट किया गया है।
- वर्तमान में, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण नीति और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और कई संस्थानों द्वारा सहायता प्राप्त है।
- राज्यों के स्तर पर, उनके कौशल विकास के प्रबंधन के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्य कौशल विकास मिशन (SSDM) शुरू किए गए थे।
- अधिकांश राज्यों ने कौशल विकास का प्रबंधन करने के लिए नामित जिला समितियों (आमतौर पर डीएससी कहा जाता है, लेकिन राज्यों में अलग–अलग अपीलों द्वारा जाना जाता है) का निर्माण किया है।
- DSCs विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय सरकारी अधिकारियों से बने है।
- इसके अलावा, डीएससी स्थानीय चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी संगठनों आदि का सह–चुनाव भी कर सकते है।

- डीएससी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी आर्थिक रूपरेखा, बाजार की स्थितियों और संस्थागत बुनियादी ढांचे के आधार पर जिला मानव संसाधनों के लिए व्यवहार्य कौशल प्रशिक्षण और रोजगार तक पहुंच की योजना बनाए।
- DSCs से अपेक्षा की जाती है कि वह सप्लाईमैंड मिसमैच को कम करे, समाज के सभी हाशिए के वर्गों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करे, श्रम प्रवास के मुद्दों का प्रबंधन करे और मजबूत निगरानी प्रदान करे।

कृषि – अर्थव्यवस्था का उद्धारकर्ता –

- कोविड के बाद के युग में कृषि विकास को बनाए रखने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, कृषि और कृषि–प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे का होना महत्वपूर्ण है।
- सरकार ने जल्द ही खेतों में कृषि कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए किसान–हितैषी योजनाओं, सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहनों को शुरू किया।
- सहकर्मी देशों के बीच, भारतीयों को वित्त वर्ष 2020 21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट के साथ सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। गंभीर स्थिति ने पहले कभी नहीं देखी गई मंदी को प्रेरित किया।
- हालांकि, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज सेक्टर लगातार चमकते हुए 3.4 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ के साथ एकमात्र चमकदार स्पॉट के रूप में उभरे।
- कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के नाते, कृषि ही वह मुख्य क्षेत्र है जो रोजगार पैदा करता है जिससे कि आर्थिक प्रसार का पूरा दायरा आगे बढ़ता है।
- पहिये को घुमाने के लिए, कृषि को सबसे पहले कृषि आदानों, बीजों, मशीनरी आदि के निर्माण और परिवहन के लिए आराम मिलता था। कृषि वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित आपूर्ति श्रृंखलाओं को जगह में सुरक्षात्मक उपायों के साथ काम करने और संचालित करने की अनुमति थी।

सरकारी योजनाएं –

- संकटकाल के दौरान कमजोर आबादी की देखभाल के लिए एक विशेष योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नकद और भोजन सहायता, जिनमें ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे, को भी पीएम–केयर फंड से बाहर किया गया था।
- आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत विभिन्न संस्थागत तंत्रों के माध्यम से छोटे किसानों के लिए ऋण सहायता सुनिश्चित की गई।
- नाबार्ड रुपये के अतिरिक्त पुनर्वित्त समर्थन का विस्तार कर रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों की फसली ऋण आवश्यकता के लिए 30,000 करोड़, जो कि छोटे और ऋण के लिए मुख्य स्रोत हैं सीमांत किसान।
- लगभग 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड रुपये की ऋण सीमा के साथ स्वीकृत किए गए थे। 25,000 ब्याज की रियायती दर पर संस्थागत ऋण तक पहुंच प्राप्त करने के लिए लगभग 2.5 करोड़ किसानों को लगभग 2.0 लाख करोड़ रुपये के क्रेडिट प्रवाह से कवर किए जाने की संभावना है। तीन करोड़ से अधिक किसानों द्वारा तीन महीने के ब्याज उपार्जन और ऋण स्थगन का लाभ उठाया गया।
- अपने गृह राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की आजीविका के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक विशेष रोजगार योजना शुरू की। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 'के रूप में नामित, इस योजना को छह सबसे अधिक प्रभावित राज्यों, अर्थात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों में एक मिशन मोड पर लागू किया गया था। श्रमिक ग्रामीण आवास से लेकर ग्रामीण मंडियों, ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक शौचालयों तक 25 सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के काम में लगे हुए थे।
- इस योजना ने टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी काम किया। अभियान के लिए शुरू में छह पहचाने गए राज्यों में कुल 25,000 रिटर्न प्रवासी श्रमिकों को चुना गया था।
- प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए, सरकार ने 'पीएम श्रमिक सेतु पोर्टल' और 'पीएम श्रमिक सेतु ऐप' लॉन्च किया है जो नौकरी चाहने वालों को उनके कौशल के अनुसार भावी नियोक्ताओं से जोड़ने में मदद करते हैं। नौकरियां केंद्र या राज्य द्वारा संचालित योजनाओं में प्रदान की जाती हैं जो ज्यादातर ग्रामीण विकास और सहायक कार्यों से संबंधित हैं। लाभ और नौकरी की पेशकश का लाभ उठाने के लिए श्रमिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश में, अधिकांश प्रवासी श्रमिकों की संख्या वाले राज्यों में से एक, ने 1.25 करोड़ प्रवासी कामगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू किया गया, जो आजीविका की चुनौती का सामना कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी बनाकर स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार ने पहले से ही अपनी विशेषज्ञता/व्यापार के अनुसार रोजगार प्रदान करने के लिए श्रमिकों के कौशल का मानचित्रण किया है।
- रोजगार योजनाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अतिरिक्त हैं जो अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। कई श्रमिकों को संलग्न करने के लिए, सरकार ने इसका परिव्यय इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश –

- कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, कृषि अवसंरचना निधि की शुरुआत की गई, जो पहले कृषि आपूर्ति श्रृंखला में एक कमजोर कड़ी रही है।
- एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड किसानों को उनके गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम करेगा। कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित करने में यह बुनियादी ढांचा एक लंबा रास्ता तय करेगा।
- इस योजना के तहत, बैंक और वित्तीय संस्थान किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व–सहायता समूहों, किसान क्रेडिट और सहकारी समितियों और व्यक्तिगत किसानों, कृषि–उद्यमियों और स्टार्टअप को ऋण प्रदान करेंगे।
- सभी ऋणों में 2 करोड़ रुपये की सीमा तक प्रति वर्ष तीन प्रतिशत का ब्याज सबवेंशन होगा। और सबवेन्शन अधिकतम सात साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।
- चुकौती के लिए एक अधिस्थगन न्यूनतम छह महीने और अधिकतम दो साल के अधीन हो सकता है। चार साल में ऋणों का वितरण 30,000 करोड़ रुपये की मंजूरी से शुरू होगा। चालू वर्ष में 10,000 करोड़ रु तथा बाकि अगले तीन वित्तीय वर्षों में ।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पहले ही सहमत शर्तों पर ऋण के वितरण के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह निधि कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक खेती की परिसंपत्तियों के निर्माण को उत्प्रेरित करेगी, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट, पैक हाउस, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयों, राईपिंग चैंबर, आदि।
- कटाई के बाद की इन संरचनाओं से किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि वे उच्च मूल्यों पर भंडारण और बिक्री कर सकेंगे, अपव्यय को कम कर सकेंगे और प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में वृद्धि कर सकेंगे।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़े कदम में, भारतीय रेलवे ने किसानों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष किसान रेल योजना को लॉन्च किया है। यह खराब हो सकने वाले प्रदार्थों के लिए एक सहज राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई चेन बनाने में मदद करेगा।
- किसान रेल योजना से पूरे देश के किसानों को लाभ होगा क्योंकि वे शहरी क्षेत्रों में अपनी उपज बेच सकेंगे। यह एक वातानुकूलित ट्रेन है और यह रेल पटरियों पर कोल्ड स्टोरेज की तरह है। शहरों में रहने वाले लोगों को ताजी सब्जियां मिलेंगी। ट्रकों की तुलना में ट्रेनों का किराया भी कम है।
- पहली किसान रेल ने 7 अगस्त, 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक इसका उद्घाटन किया। प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर, दूसरे किसान रेल ने 10 सितंबर, 2020 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली तक चलाया गया।
- किसान रेल स्टेशनों पर लोडिंग / अनलोडिंग की सुविधा के लिए एन–रूट स्टॉपेज के साथ बहु–वस्तु, बहु–खेप और बहु–खेप गाड़ियां हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हथकरघा परिवारों की भूमिका –

- हिमाचल प्रदेश में, अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है जो कृषि को अपनी आजीविका के रूप में देख रहे हैं। भूमि जोत बहुत छोटा है और औद्योगीकरण की गुंजाइश कम है, इसलिए इस राज्य में कौशल विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास की एक बड़ी गुंजाइश है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि, हथकरघा, सिलाई और ग्रामीण कारीगरों के कामों आदि में लगे हुए हैं। इस पत्र में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हथकरघा घरों की आय और रोजगार का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश कई हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ कालीन, शॉल, लकड़ी के काम, पेंटिंग और चमड़े के काम हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड राज्य के गरीब बुनकरों और कारीगरों के हितों की सहायता और बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
- निगम का उद्देश्य राज्य के भीतर और बाहर स्थित एम्पोरिया की अपनी श्रृंखला के माध्यम से प्रशिक्षण, डिजाइन इनपुट, कच्चे माल की स्थापना, सुस्त शिल्प को पुनर्जीवित करना और उन्हें विपणन सुविधाएं प्रदान करना है।
- हैंडलूम में चार मिलियन से अधिक बुनकर और संबद्ध उत्पादन श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से कई एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं से संबंधित हैं। यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है।
- सरकार को प्रशिक्षण सामग्री, टूलकिट, आधुनिक उपकरण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच को आसान बनाने और शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक में निवेश करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, मौजूदा प्रतिभाओं के प्रभावी उपयोग, स्थानीय कच्चे माल के उपयोग, उपलब्ध कौशल और उत्पाद डिजाइन, ऋण सुविधाओं, रोजगार के अवसरों के सृजन और गरीबों के लिए नवीनतम आधुनिक मशीनों पर कुछ सब्सिडी के प्रावधान के उन्नयन पर ध्यान देना। पारंपरिक घराने हिमाचल प्रदेश में कौशल संवर्धन के लिए नीतिगत मुद्दे हैं।
- हिमाचल प्रदेश में अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इस राज्य में कौशल विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास की एक बड़ी गुंजाइश है। कौशल विकास इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न परंपराओं से आने वाले दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला है। ग्रामीण इलाकों में। लोग कृषि में लगे हुए हैं। हथकरघा, सिलाई और ग्रामीण कारीगर काम आदि।
- कमजोर समूहों की रोजगार क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएँ हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में, अब तक के कार्यक्रम राज्य द्वारा संचालित किए गए हैं और कुछ मामलों में, उद्योग ने उन्हें नौकरी योग्य बनाने के लिए कर्मचारी को बनाए रखा है। आवश्यकता मांग–संचालित कौशल विकास की है, जो उद्योग की आवश्यकता को पूरा करता है।
- कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति, 2015 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिए के समूहों द्वारा कौशल विकास के लिए समान पहुंच के माध्यम से किसी भी विभाजन के बावजूद समावेश की परिकल्पना की गई है।
- अल्पसंख्यक, महिलाएं, स्कूल छोड़ने वाले, अलग तरह से रहने वाले और कठिन भौगोलिक स्थानों में रहने वाले लोग अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने, और अच्छे रोजगार के अवसरों तक पहुँच बनाने के लिए।
- पिछले वर्ष की तुलना में मेक इन इंडिया के विजन ने कौशल विकास को प्रमुख प्रोत्साहन दिया है। सरकार ने 2022 तक 150 मिलियन से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करने की योजना बनाई है – विभिन्न कौशल अंतरालों को समझने के लिए।
- और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता सहित उद्योग की आवश्यकताएं, छैक्ब एक सक्रिय भूमिका निभा रही है और इसने विभिन्न क्षेत्र कौशल परिषदों का गठन किया है जिसमें उद्योग के विशेषज्ञ और अन्य हितधारक शामिल हैं

उद्यम से आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्र का सफर –

- आज राष्ट्र आत्म–निर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है, स्टार्ट–अप, उद्यमशीलता के साथ, और कौशल विकास एक लाभांश का खेल भारत के पक्ष में है।
- प्रधानमंत्री ने कोरोनोवायरस महामारी संकट के दौरान आत्मनिर्भर भारत के शुभारंभ की घोषणा की, इसकी नींव रखना छह और एक चौथाई साल पहले शुरू हुआ था, जो केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और अभियानों में समय–समय पर दिखाई देता था।
- भारत में युवा लोगों और कार्यबल की बड़ी आबादी है, जो यह दर्शाता है कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या निर्भर जनसंख्या से अधिक है। कामकाजी आबादी का औसत लगातार बढ़ रहा है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 यह भी बताता है कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश वर्ष 2041 के आसपास अपने चरम पर होगा जब 20 से 59 आयु वर्ग के कामकाजी लोगों की हिस्सेदारी कुल आबादी के 59 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।
- यदि जनसांख्यिकीय लाभांश किसी देश का पक्ष लेता है, तो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, विकास दर बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है।
- सरकार ने 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कौशल से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की है। यह कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के अलावा उनके लिए धन उपलब्ध करा रही है।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि कौशल और ज्ञान किसी भी राष्ट्र के लिए सामाजिक–आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति है।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कुशल श्रमिकों की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना के माध्यम से, युवाओं को उद्योग–संबंधी कौशल में अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- स्थानीय बाजार के अनुसार, देश में संचालित 233 सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों के माध्यम से निरक्षर, नव–साक्षर और स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत अल्पावधि प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 34.14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
- इसमें से 28.36 लाख युवाओं को रोजगार मिला है।
- इसी तरह, पूर्व शिक्षण कार्यक्रम की मान्यता के तहत, 33.20 लाख युवाओं के कौशल को प्रमाणित किया गया है, जिनमें से लगभग 27.36 लाखों युवाओं को रोजगार मिला है।
- स्टार्ट–अप्स को बढ़ावा देने के लिए, 2019 में, सरकार ने इसकी परिभाषा बदल दी है। इसके अनुसार, अब एक स्टार्ट–अप को इसकी स्थापना के बाद दस साल के लिए स्टार्ट–अप के रूप में माना जाएगा और लाभ प्राप्त करना जारी रहेगा।
- स्टार्ट अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए start फंड्स ऑफ फंड्स' बनाए हैं।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भी आत्मनिर्भर भारत अभियान (आत्मनिर्भर) के तहत एक आचार निर्भय कुशल कर्मचारी–नियोक्ता मानचित्रण (ASEEM) भारत अभियान पोर्टल शुरू किया है।
- यह पोर्टल मांग और आपूर्ति के आधार पर कुशल कार्यबल का वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है।
- प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता नवीनतम तकनीक से संबंधित दीर्घकालिक प्रशिक्षण पर शुरू हुआ। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने आईबीएम के साथ एमओयू के माध्यम से जून 2020 में मुफ्त डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म (स्किल बिल्ड रिग्नाइट) लॉन्च किया है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कम्प्यूटिंग के समय में, नेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डिजिटल कौशल का सर्वांगीण प्रशिक्षण भी दे रहा है।
- उद्यमिता और कौशल के क्षेत्र में भारतीय शैली जैसे योग को भी जोड़ा गया है। अब तक 98 हजार से अधिक लोगों को योग प्रशिक्षक के रूप में रोजगार पाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
- प्रधानमंत्री युवा विकास अभियान (PMYUA) युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इसके माध्यम से, उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण, सलाह और अन्य सहायता प्रदान की जाती है, युवा उद्यमिता 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर लागू की जा रही है।
- उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार (NEA) भी स्थापित किया गया है। पुरस्कार का उद्देश्य उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और युवाओं को प्रेरित करना है।
- यह पुरस्कार युवा प्रथम उत्थान उद्यमियों और पारिस्थितिकी तंत्र बिल्डरों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो उद्यमशीलता और महिला उद्यमियों के लिए रचनात्मक वातावरण बनाते हैं।
- सरकार ने महिला उद्यमियों को स्टार्ट–अप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं।
- जर्मन की संस्था GIZ के साथ मिलकर सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
- उद्यमी और महिलाएं स्टार्ट–अप राजस्थान और तेलंगाना और उत्तर–पूर्वी राज्यों–असम, मेघालय, और मणिपुर में लागू किया जा रहा है।
- सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यवसाय को स्थापित करने और बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को ऋण सुविधा प्रदान कर रही है। इसमें मुद्रा योजना के साथ स्टैंड अप इंडिया योजना भी शामिल है।
- कृषि, बागवानी और पशुपालन, उद्यमिता और स्टार्ट–अप की अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में, सरकार ने संसद में कृषि सुधारों से संबंधित तीन कानून पारित किए हैं।
- इन कृषि सुधारों के साथ, किसानों को कई सुविधाएं और कहीं भी, किसी को भी अपने उत्पादों को बेचने की स्वतंत्रता है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में नए स्टार्ट–अप और उद्यमियों को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- मंडियों के अलावा कहीं भी कृषि–उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता, कृषि विपणन के लिए ई–प्लेटफॉर्म युवा उद्यमियों को कृषि क्षेत्र में पनपने के अवसर प्रदान करेगा।
- भंडारण की सीमा को समाप्त करने के कारण निजी क्षेत्र में भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, और प्रसंस्करण इकाइयों का विस्तार किया जाता है।
- आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनाज, आलू तों, और प्याज की तरह उत्पादन।
- आटमा निर्भार भारत अभियान के तहत, प्रधानमंत्री ने रुपये के कोष के साथ एक कृषि अवसंरचना निधि का प्रावधान किया है। 1 लाख करोड़, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र की दशा और दिशा को बदलना है। इस फंड से ग्रामीण इलाकों में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।
- प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

- इस राशि के साथ, दो लाख सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को वैश्विक पहुंच और 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता का समर्थन किया जाता है।
- इस फंड से उन उद्यमियों को लाभ होगा जो अपने उद्यमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप बनाना चाहते हैं या वे अपने स्वयं के ब्रांड स्थापित करना चाहते हैं।
- मौजूदा खाद्य उद्यमियों के साथ–साथ किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों को भी इस योजना में सहायता दी गई है।

ग्रामीण स्टार्ट–अप के लिए वित्तीय और संस्थागत समर्थन

स्टार्टअप्स को सरकारी सहायता

- 'डिजिटल इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' के लिए माननीय प्रधान मंत्री के स्पष्ट आह्वान के तहत स्टार्टअप आंदोलन को गति मिली है। स्टार्टअप इंडिया पहल देश में नवाचार और उद्यमिता के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। भारत में राज्य एवं केंद्र सरकारें स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

  सरकार के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं –
  1. रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देना।
  2. विनियामक बोझ को कम करने और नई नीतियों को पेश करके पर्यावरण को सक्षम बनाना।
  3. बुनियादी ढांचे के निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता का निर्माण।
  4. धन सहायता और राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करें।
  5. स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी सदस्यों को जोड़ने और सहयोग करने की सुविधा।

ग्रामीण स्टार्टअप के लिए संस्थागत और वित्तीय सहायता

- स्टार्टअप जीनोम के अनुसार, बेंगलुरु और दिल्ली दुनिया के शीर्ष 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हैं।
- **ऊष्मायन केंद्र** – भारत में 400 से अधिक इनक्यूबेटर और त्वरक हैं। अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के माध्यम से, अब तक लगभग 47 ऊष्मायन केंद्रों को वित्त पोषित किया गया है। जबकि इन ऊष्मायन केंद्रों में से कई टियर 2–3 में हैं, केवल कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अन्य क्षेत्रों में, कृषि एआईएम के फोकस क्षेत्रों में से एक है। कृषि विश्वविद्यालयों (जैसे TNAU) और नाबार्ड ने कृषि ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। आईसीएआर में एक कृषि–केंद्रित ऊष्मायन केंद्र भी है।
- **फंड ऑफ फंड्स** – 1976 में IFCI के पहले वेंचर कैपिटल फंड से 10000 करोड़ रुपये के सिडबी स्टार्टअप फंड्स के फंड्स से, लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा शहरी स्टार्टअप रहा है। फरवरी 18,2020 तक, SIDBI फंड ऑफ फंड्स ने 47 वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में 913 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
- **वेंचर कैपिटल फंडस** – वेंचर कैपिटल फंड्स का पहला सेट, जिसमें कुछ ग्रामीण स्टार्टअप स्पेस में निवेश किया गया था, में अविष्कार (2001 में स्थापित), एक्यूमेन और रूरल इनोवेशन जैसे इम्पैक्ट फंड शामिल थे। बाद में, कुछ वैश्विक नींवों, प्रभाव निवेशकों और परोपकारियों के रूप में बाहरी पूंजी तक पहुंच में काफी वृद्धि हुई एवं कृषि–ग्रामीण स्टार्टअप में निवेश शुरू किया।
- SIDBI के पास एक ग्रामीण उन्मुख कुलपति कोष था, जिसमें 60 करोड़ रुपये का कोष था और इसने कृषि निधि से समधी निधि में कुछ निवेश किया था। नाबार्ड कृषि/ग्रामीण वीसी फंडों का बहुत समर्थन करता है क्योंकि इसने वीसी फंडों में योगदान देना शुरू कर दिया था जिनके पास कृषि/ग्रामीण उनके मुख्य फोकस क्षेत्रों में से एक था। अब तक, NABARD ने 19 ऐसे फंडों का समर्थन किया है। इन फंडों ने मिश्रित प्रदर्शन दिया है और अब तक बहुत सारे अनारक्षित मौजूद हैं।
- 2019 में, नाबार्ड ने अपना उद्यम विकास इक्विटी फंड, NABVENTURES फंड की शुरुआत 500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ की। महामारी के दौरान, NABVENTURES ने स्टार्टअप्स में तीन एग्रीटेक और एक एग्री/रूरल फिनटेक निवेश किया है।
- **सीड केपिटल** – प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के विकास में सहायता के लिए बजट 2020–21 में एक राष्ट्रीय बीज निधि की घोषणा की गई थी। हाल ही में, RBI ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने के हिस्से के रूप में स्टार्टअप को ऋण देने की अनुमति दी है।
- NABARD और SIDBI क्रेडिट गारंटी स्कीम स्थापित कर रहे हैं, जो अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण जुटाने के लिए स्टार्टअप को सक्षम कर सकती हैं।
- वर्तमान में, एग्रीटेक स्टार्टअप की पहुँच केवल 10 प्रतिशत किसानों तक हैं। फंडिंग से परे, स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, निर्देशन और जोखिम की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का प्रबंधन करने वाले प्रमुख लोग उद्यमी / स्टार्टअप निवेशक हैं जो स्वयं को चलने वाले व्यवसायों के पहले हाथ के संपर्क में रखते हैं। यह इनक्यूबेटरों / त्वरक के लिए भी सही है क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले लोगों के बिना, केवल बेकार बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है।

ग्रामीण स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित रखने वाले तत्व –

- **शिक्षा** – शिक्षा और व्यावसायिक कौशल को कई देशों द्वारा पालन किए जाने वाले अभ्यास को एकीकृत करने की आवश्यकता है। हमें बुनियादी अंग्रेजी भाषा कौशल में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण युवाओं में से कई में 'सॉफ्ट स्किल्स' का अभाव होता है जैसे कि नए विचारों के साथ प्रयोग करने की क्षमता, व्यावसायिक अवसरों, बिक्री और विपणन की क्षमता आदि की क्षमता जो उन्हें कॉर्पोरेट में अधिक उत्पादक और रोजगार योग्य बना सकती है। ये कौशल उद्यमिता में भी मदद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से रोजगार सृजन मोबाइल इंटरनेट आधारित डिजिटल सेवाएं शिक्षित ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार वृद्धि का इंजन बन सकती हैं। एग्रीटेक, एग्री बेस्ड ईकॉमर्स, आईटीलिंकड एग्री–एक्सेन्सेनियन, सीड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्म मॉनिटरिंग, एग्री / रूरल फिनटेक आदि में नए अवसर उभर रहे हैं, जो शिक्षित ग्रामीण युवाओं को नए विचारों का पता लगाने, अनुसंधान और सेटअप स्टार्ट–अप करने में सक्षम बनाते हैं।

आगे को राह –

ए. ग्रामीण स्टार्टअप्स का ऊष्मायन/त्वरण – निकट अवधि में, ग्रामीण भारत में अधिक त्वरक और इन्क्यूबेटरों के लिए गुंजाइश है, जो मुख्य रूप से एग्रीटेक, फूडटेक, किफायती हाउसिंग टेक, ग्रामीण हेल्थटेक/एडिटेक, फिनटेक, भुगतान आदि पर केंद्रित हैं – ये होना चाहिए। अन्य विश्वविद्यालयों, मंडियों, प्रसंस्करण सुविधाओं, कृषि पार्कों आदि के साथ कुछ बड़े समूहों में रखे गए।

- इनक्यूबेटरों में से कुछ इंटरनेट सेवाओं, हार्डवेयर, भविष्य प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी आधारित कृषि, ग्रामीण में विशेषज्ञ हो सकते हैं। प्रौद्योगिकियों ने भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया है।
- नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी के संरक्षण के लिए, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मौजूदा बुनियादी ढांचे को ऊष्मायन/त्वरण केंद्र चलाने के लिए लिया जा सकता है।

बी. बड़ी संख्या में किसानों/ग्रामीण आबादी को लाभान्वित करने वाले स्टारअप में निवेश करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण बीज–सह–प्रभाव निधि का निर्माण –
1,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ सरकार समर्थित राष्ट्रीय ग्रामीण प्रभाव निधि (40 प्रतिशत के GOI के साथ AIF के रूप में) ग्रामीण स्टार्ट–अप में मितव्ययी नवाचार प्रदान करने के लिए निवेश की स्थापना की जा सकती है जो कि एक छोटे स्टार्टअप और सीमांत किसान के लिए भी सस्ती हो और जिनके समाधान का उद्देश्य बीज स्तर पर एफपीओ का समर्थन करना है। यह अधिकतम सामाजिक प्रभाव और बड़े कृषि व्यवसाय कॉर्पोरेट (दोनों घरेलू और विदेशी), नींव पैदा करेगा। भारत सरकार निधि में अन्य योगदानों को आकर्षित करने के लिए 10–20 प्रतिशत की सीमा तक पहले नुकसान की गारंटी प्रदान कर सकती है।

सी. एक राष्ट्रीय कृषि/ग्रामीण स्टार्टअप फंड का निर्माण – भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्टार्टअप फंड, एआईएफ की स्थापना पर विचार कर सकती है, जिसमें 25000 करोड़ रुपये की निधि कृषि/खाद्य/ग्रामीण स्टार्टअप में सभी चरणों (प्रारंभिक, मध्य और देर से) में प्रत्यक्ष निवेश की जाए। नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) फंड की तरह, भारत सरकार अपने योगदान को 49 प्रतिशत तक सीमित कर सकती है और शेष राशि घरेलू और वैश्विक दोनों से निवेशकों को जुटा सकती है। इस फंड के निर्माण के साथ, विदेशी निवेशकों को दांव लगाने के लिए बड़े स्टार्टअप की आवश्यकता नहीं हो सकती है। कृषि राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र है और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण ग्रामीण स्टार्टअप के स्वामित्व को घरेलू हाथों में रखा जाना चाहिए।

डी. एक राष्ट्रीय ग्रामीण निधि कोष का निर्माण – भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण निधि, एआईएफ की स्थापना पर विचार कर सकती है, जिसका प्रारंभिक कोष दो हजार करोड़ रुपये का होगा। यह फंड तीसरी पार्टी एआईएफ में अप्रत्यक्ष निवेश करेगा जो शुरुआती चरणों में बीज (पोस्ट इनक्यूबेशन/त्वरण) में कृषि/खाद्य ग्रामीण स्टार्टअप में निवेश करेगा। यह फंड समर्थित फंड्स एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में इक्विटी स्टेक लेगा और साथ ही निवेश भी करेगा।

ई. राष्ट्रीय उद्यम ऋण कोष का निर्माण – व्यावहारिक रूप से, कोई भी बैंक स्टार्टअप्स को ऋण देना नहीं चाहता है, जिसमें एग्री–स्टार्टअप शामिल हैं, जोकि वास्तव में कार्यशील पूंजी के लिए ऋण चाहते है नाकि इक्विटी के लिए। राष्ट्रीय उद्यम ऋण निधियों का सृजन, 1500 करोड़ रुपये के अंतरिक कोष के साथ एआईएफ (40 पूर्व योगदान) भारत सरकार इस समस्या का समाधान करेगी। फंड को वित्तीय रूप से पर्याप्त स्टार्टअप में निवेश करना चाहिए, जो 200 करोड़ रुपये या उससे अधिक के राजस्व तक पहुंचने के लिए परिपक्व हो गए हैं और जो पहले से ही उद्यम पूंजीगत धन की बड़ी राशि जुटा चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां, FI और बैंक स्टार्ट अप को प्रदान किए गए उद्यम ऋण के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष –

- ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयुक्त उद्यम क्षमता बहुत है। कृषि और ग्रामीण व्यवसाय अधिकतम सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र हैं लेकिन भारत में एक इक्विटी / स्टार्ट–अप निवेश के दृष्टिकोण से कमतर रहते हैं।
- एग्री–फूड–रूरल इकोसिस्टम पर केंद्रित केवल कुछ विशेषज्ञ फंड (2–3 से अधिक नहीं) हैं।
- इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे आदि के मामले में कमजोर हैं और तकनीक आधारित नवीन व्यवसायों के शुभारंभ के लिए परिपक्व हैं।
- ग्रामीण रीलों में इंटरनेट के प्रवेश से सुपर एप्स/नक्षत्रों का उदय होगा, जो ग्रामीण बैंकिंग, खरीदारी, व्यापार, ईकॉमर्स आदि का चेहरा बदल देगा।
- सरकार एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए उद्यमशीलता के महत्व को पहचानती है और कई स्तरों पर कार्य करती है। स्टार्टअप के लिए रुख बनाने वाली नीति को सरकारी धन के माध्यम से अप्रत्यक्ष निवेश से सरकारी स्वामित्व वाले वीसी फंड के माध्यम से प्रत्यक्ष निवेश करने की आवश्यकता है, जिसमें कई निवेश करने की क्षमता है।
- इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स (उद्यम ऋण सहित)। इसके अलावा, प्रत्यक्ष निवेश को वाणिज्यिक शर्तों पर प्रबंधित करने की आवश्यकता है और रिटर्न उत्पन्न करने के लिए और निवेश के भविष्य के दौर के लिए समग्र कार्यक्रम को टिकाऊ बनाने के लिए सामाजिक शब्द नहीं।

ग्रामीण महिला उद्यमी – एक नए भारत को सशक्त बनाना

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2018–19 के अनुसार, ग्रामीण भारत में 59.7 प्रतिशत महिलाएं स्वरोजगार कर रही हैं, 11 प्रतिशत नियमित वेतन या वेतन कमाने वाली हैं जबकि 29.3 प्रतिशत आकस्मिक श्रमिक हैं। इसकी तुलना में, ग्रामीण भारत में 57.4 प्रतिशत पुरुष स्व–नियोजित हैं, 14.2 प्रतिशत नियमित वेतन या वेतन पाने वाले हैं और 28.3 प्रतिशत लोग आकस्मिक श्रमिक हैं।
- जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच काम की प्रकृति का हिस्सा अलग–अलग नहीं है, पुरुषों और महिलाओं के बीच स्व–रोजगार के प्रकार में बहुत बड़ा अंतर है। ग्रामीण भारत में 84 प्रतिशत स्व–नियोजित पुरुष स्वयं के खातेदार या नियोक्ता हैं, जबकि केवल 37 प्रतिशत महिलाएं इस श्रेणी में आती हैं। ग्रामीण भारत में सबसे अधिक बेरोजगार महिलाएं (63 प्रतिशत) घरेलू उद्यमों में मददगार के रूप में काम करती हैं।

- पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार, जम्मू–कश्मीर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में ग्रामीण भारत में स्वरोजगार महिला श्रमिकों की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी।
- तुलना में, चंडीगढ़, केरल, बिहार और असम कुछ राज्य थे, जिनमें ग्रामीण महिलाओं की सबसे कम हिस्सेदारी थी, जो स्व–रोजगार वाली थीं।
- जबकि बिहार और चंडीगढ़ में ग्रामीण महिलाओं की अधिक हिस्सेदारी थी, जो आकस्मिक श्रम के रूप में काम करती थीं, असम और केरल में अधिक महिलाएं थीं, जिनकी नियमित मजदूरी और वेतन था। जिन राज्यों में कृषि सकल राज्य मूल्य में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के एक हिस्से के रूप में अधिक हिस्सेदारी थी, वे भी आत्मरक्षा के उच्च हिस्से के साथ जुड़े थे जो 0.30 के सहसंबंध गुणांक के माध्यम से इंगित किया गया था।
- एक राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बीच सहसंबंध ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार महिलाओं के अपने हिस्से के साथ 0.25 प्रतिशत पाया गया। इसका मतलब यह है कि राज्यों में स्व–नियोजित महिलाओं की अधिक हिस्सेदारी थी
- पीएलएफएस 2017–18 के सर्वेक्षण में बताई गई संख्याओं के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–नियोजित महिलाओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पुरुषों और महिलाओं के बीच सबसे कम मजदूरी अर्जित की। स्व–नियोजित शहरी पुरुषों द्वारा अर्जित औसत मजदूरी, ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं की तुलना में 4 गुना अधिक थी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–नियोजित पुरुषों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार वाली महिलाओं की तुलना में 2.5 गुना थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार वाली महिलाएं 1.7 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार महिलाओं द्वारा अर्जित मजदूरी।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार महिलाओं द्वारा एक सप्ताह में काम किए गए घंटों की संख्या में परिलक्षित होता है, जो शहरी स्वरोजगार पुरुषों की तुलना में लगभग 19–21 घंटे और स्वरोजगार ग्रामीण पुरुषों की तुलना में 10–12 घंटे कम है। शहरी क्षेत्रों में स्व–नियोजित महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों की तुलना में कुछ घंटों से अधिक काम किया, जो यह दर्शाता है कि उनके ग्रामीण समकक्षों की तरह, उन्हें भी घरेलू कामों में बड़ा हिस्सा मिलने की उम्मीद है।
- सामाजिक कंडीशनिंग के अलावा जहां महिलाओं को प्राथमिक देखभाल करने वाले होने की उम्मीद है और घर के अधिकांश काम करते हैं।
- ये बाधाएँ खराब शिक्षा के स्तर से लेकर सूचना विषमता के लिए वित्तीय सहायता के अभाव तक हैं।
- वर्षों से, सरकार ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर में सुधार की दिशा में सक्रिय कदम उठाए हैं। फिर भी, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में लैंगिक अंतर है।
- पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की औसत साक्षरता दर 78.1 प्रतिशत की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्रों में सात वर्ष की आयु तक केवल 65.7 प्रतिशत महिलाएं ही 2019 तक साक्षर थीं। इसके अलावा, साक्षरता में सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की दर, श्रम शक्ति में भागीदारी के उच्च हिस्से में अनुवादित नहीं हुई है।

CHAHAL ACADEMY

Chahal Academy has pan India presence

VISIT US AT

N New Delhi: 982-155-3677
Corporate Office
Office No.B-7, Lower Ground floor, Apsara Arcade Near Karol Bagh, Metro Gate No. 7, New Delhi - 110060

M Mumbai Branch: 990-911-1227
415, Pearl Plaza Building, 4th Floor, Exactly opp Station Next to Mc Donalds. Andheri West, Andheri West, Mumbai, Maharasthra,-

K Kolkata : 728-501-1227
31/3, Bankim Mukherjee Sarani, New Alipore, Block J- Siddharth Apartment, 3rd Floor, Opposite Corporation Bank, Kolkata - 700053, West Benga

A Ahmedabad: 726-599-1227
Office No. 104, First Floor Ratna Business Square, Opp. H.K.College, Ashram Road, Ahmedabad - 380009

A Anand: 720-382-1227
Head Office
T9-3rd Floor Diwaliba Chambers,Vallabh Vidyanagar, Near ICICI Bank, Bhai Kaka Statue, Anand - 388120

B Bhubaneswar : 720-191-1227
1899/3902, First Floor, Lane No. 2, Near Laxmi Narayan Temple, Nilakantha Nagar, Nayapalli, Bhubaneswar - 751006, Odisha.

C Chandigarh : 726-591-1227
2nd Floor, SCO-223, Sector-36-D, Above Chandigarh University Office, Chandigarh - 160036.

D Dehradun Branch: 721-119-1227
Near Balliwala Chowk, General Mahadev Singh Road, Kanwali, Dehradun, Uttarakhand- 248001.

G Gandhinagar: 6356061801
Office No. 122 , 1st Floor , Siddhraj Zori , KH, O, Sargasan Cross Road, Gandhinagar, Gujarat 382421

K Kanpur : 720-841-1227
2nd Floor, Clyde House, Opposite Heer Palace Cinema, The Mall Road, Kanpur Cantonment, Kanpur - 208004, Uttar Pradesh.

P Patna : 726-591-1227
3rd Floor, Pramila mansion, Opposite Chandan Hero Showroom, Kankarbagh Patna - 800020, Bihar

R Raipur Branch: 728-481-1227
D-117, first floor, Near Shri Hanuman Mandir, Sector-1, Devendra Nagar, Raipur, Chattisgarh- 492009.

R Rajkot Branch: 762-401-1227
3rd Floor,Balaji House 52 Janta Society Opp LIC Of IndiaTagore Road Rajkot 360001

R Ranchi: 728-491-1227
3rd Floor, SMU Building, Above Indian Overseas Bank, Purulia Road, New Barhi Toli, Ranchi - 834001, Jharkhand.

S Surat: 720-391-1227
Office No. 601, 6th Floor, 21st Century Business Centre, Besides World Trade Centre, Near Udhna Darwaja, Ring Road Surat - 395002

V Vadodara: 720-390-1227
102-Aman Square, Besides Chamunda Restaurant, Behind Fatehgunj Petrol Pump, Vadodara, Gujarat- 390002

COMING SOON : BENGALURU| GUWAHATI |HYDRABAD | JAIPUR | JAMMU | KOCHI | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE

Write us at: chahalacademy@gmail.com | www.chahalacademy.com

Follow us at: YouTube Linked in